सम्पादकीय

संवेदनशील राज्य पंजाब में सुरक्षा पर सवाल, अकाल तख्त में हुआ बड़ा हादसा

पंजाब अलगाववादी गतिविधियों के लिहाज से अब भी संवेनशील राज्य है। पिछले कुछ समय से फिर कनाडा आदि देशों में रह रहे कुछ अलगाववादी सिख खालिस्तान की मांग उठाने लगे हैं। उसका कुछ असर पंजाब में भी देखा गया। हालांकि सरकार ने चुस्ती दिखाई और ऐसे तत्वों पर लगाम कसने में कामयाब हुई। मगर पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, दिनदहाड़े और सरेआम किसी को गोली मार देने में भी अपराधियों को कोई हिचक नहीं होती। ऐसे वातावरण में पुलिस से अधिक चौकस रहने की अपेक्षा की जाती है। मगर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरह स्वर्ण मंदिर परिसर में जानलेवा हमला हो गया, उससे जाहिर है कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के अपेक्षित इंतजाम नहीं किए थे। जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई वह खालिस्तान समर्थक पूर्व आतंकवादी है। रामरहीम के आपराधिक मामले में सुलह करवाने के आरोप में अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर गुरुद्वारे में सेवा करने और कीर्तन सुनने का आदेश दिया था। उसी का पालन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर में वे सेवा दे रहे थे। एक व्यक्ति ने उसी वक्त उन पर हमला करने की कोशिश की। गनीमत थी कि वहां सादी वर्दी में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया। इस तरह गोली बादल को न लग कर दीवार पर जा लगी। हालांकि स्वर्ण मंदिर परिसर में उस तरह श्रद्धालुओं की तकनीकी जांच नहीं होती, जिस तरह अन्य अनेक पूजा स्थलों पर की जाती है। श्रद्धालु मुक्त रूप से परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। पर सुरक्षा के लिहाज से परिसर में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। यह अच्छी बात है कि श्रद्धा के मामले में वहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, मगर सुखबीर बादल वहां किसी सामान्य श्रद्धालु की तरह नहीं गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गनीमत है कि सादी वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर बंदूक लेकर कोई शख्स कैसे पूर्व मुख्यमंत्री के करीब तक पहुंच गया। अगर उसे परिसर में प्रवेश से पहले ही पकड़ लिया जाता, तो वह गोली चलाने में कामयाब ही न हो पाता। दूसरी बात, कि अगर मंदिर परिसर में सादी वर्दी में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो उन्हें उस व्यक्ति को पहचानने में इतनी देर कैसे हो गई कि वह बादल के करीब तक पहुंच गया। पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण भी बहुत संवेदनशील है। अमृतसर तो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। यह भी छिपी बात नहीं है कि अलगाववादी तत्वों के तार पाकिस्तानी दहशतगर्दों से भी जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बादल पर हमला किया, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि खालिस्तान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान गया था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षाबलों की मामूली लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर काबू न पा सकने की वजह से स्वाभाविक ही वहां की राज्य सरकार पर सवाल उठते रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी को सुरक्षित पंख लगाने को शी बॉक्स पोर्टल मज़बूत आधार

वैश्विक स्तरपर भारत के विज़न 2047 की पूरी दुनिया में गूंज हो रही है जो हर क्षेत्र में विकसित भारत के लिए बनाए गए रोड मैप का एक संयुक्त पत्रक है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ना भी है, जिसके लिए यह जरूरी है कि उनके लिए राजनीतिक सामाजिक कार्यपालिका सहित सभी क्षेत्रों में अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक सुरक्षित संरक्षित माहौल बनाया जाए, ताकि उनके टैलेंट को पंख लगा सके परंतु ऐसा देखा गया है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न होने की शिकायतें सामने आई तो सरकार ने इसको रेखांकित कर कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (शिकायत निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 बनाया परंतु उसके रि यान्वयन में देरी व लीकेजेस को रेखांकित कर 29 अगस्त 2024 को एक कार्यर म में शी-बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया था,

किशन सन्मुखदास भावनानी

जिसमें महिलाओं की शिकायतें दर्ज कर निगरानी करने,व त्वरित कार्रवाई करने का एकीकृत प्लेटफार्म है, जिसपर सभी संबंधितों की नजर होगी, इसलिए पारदर्शिता से कार्रवाई शीघ्र होगी जो 90 दिन निर्धारित हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि भारत में शुरू संसद के शीत सत्र 2024 में दिनांक 4 दिसंबर 2024 को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला बाल विकास कल्याण राज्यमंत्री ने उसके उत्तर में सटीक बातें कही, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,शी-बॉक्स पोर्टल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुरक्षित व संरक्षित बनाने व महिला कार्यबल मिशन 2047 में मील का पत्थर साबित होगा। साथियों बात अगर हम शी-बॉक्स पोर्टल को जानने की करें तो, कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम है।यह पोर्टल देश में आंतरिक समितियों और स्थानीय समितियों से संबंधित सूचनाओं के लिए एक स्टोरेज के रूप में काम करेगा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर होंगे।यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति पर निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उनकी शिकायतों का समय पर निपटारा हो, इसके लिए शिकायतों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि महिला को न्याय मिल सके,. केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस पहल से कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने के लिए पहले से अधिक कुशल और सुरक्षित मंच उपलब्ध कराया जा सकेगा,यह कदम देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कुकृत्य के बाद ही देश में आक्रोश का माहौल है,लोग इस घटना के बाद वर्क स्पेस पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे,ऐसे में सरकार वर्क स्पेस पर महिलाओं के काम करने और उनकी सुरक्षा को लेकर कई कदम उठा रही है। साथियों बात अगर हम शी-बॉक्स पोर्टल की विधि को जानने की करें तो, (1)विजिट वेबसाइट- सबसे पहले नोटिफिकेशन में दी गई वेबसाइट पर जाएं।(2) रजिस्टर कंप्लेंट- होम पेज पर रेड कलर में रजिस्टर योर कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करने के बाद आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड पेज पर पहुंच जाएंगे।(3)कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पेज पर प्रक्रिया शुरू करने के लिए रजिस्टर कंप्लेंट करें पर टैप करें।(4)यहां दो ऑप्शन होंगे- सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिस और स्टेट गवर्मेंट ऑफिस, आपको सेंट्रल गवर्मेंट ऑफिस पर टैप करना है। (5) पर्सनल डिटेल- अब आपके

सामने पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। इसमें नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और इम्प्लॉयमेंट स्टेट्स, इंसीडेंट डिटेल और एविडेंस जैसी चीजें शामिल हैं। (6) रिव्यू एंड सबमिट- एक बार ये सारी चीजें फिल करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। जिस पर टैप कर दें।अब शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा होगी। सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित अन्य तरह की ज्यादती होने पर इसकी ऑनलाइन शिकायत शी-बॉक्स पोर्टल पर जाकर दर्ज करा सकती हैं। संबंधित विभाग इस पर त्वरित पहल करते हुए संबंधित संस्थान या व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करेगा। जिला स्तरपर इसका नोडल पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को बनाया गया है, जो स्थानीय स्तरपर शिकायतों का निवारण एवं आवेदन प्राप्त कर उचित कार्रवाई करेंगे। कोई भी महिला बाल विकास मंत्रालय के वेब पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद उस शिकायत को सीधे संबंधित नियोक्ता के आईसीसी/एलसीसी को भेज दिया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए न केवल मंत्रालय, बल्कि शिकायतकर्ता भी जांच की प्रगति की निगरानी कर सकेंगी। इस पोर्टल के बारे में महिलाओं को अवगत कराने के लिए जिला प्रशासन इसका प्रचार-प्रसार करेगा। साथियों बात अगर हम पोर्टल के उद्देश्यों को जानने की करें तो,भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ रहा है, सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो महिलाओं को कार्यबल में सफल होने में सक्षम बनाता है। इस प्रयास की आधारशिला है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, जिसका उद्देश्य महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। हाल ही में लॉन्च किया गया शी-बॉक्स पोर्टल इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतें न केवल दर्ज की जाएं बल्कि सक्रिय रूप से उनकी निगरानी भी की जाए, जिससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा उपलब्ध हो। साथियों बात अगर हम 4 दिसंबर 2024 को लोकसभा में शी-बॉक्स पोर्टल संबंधी प्रश्न के लिखित उत्तर की करें तो, शी- बॉक्स पोर्टल मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीयसमितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाओं का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केंद्रीकृत संग्रह उपलब्ध कराना है,चाहे वे सरकारी हों या निजी क्षेत्र के और साथ ही एक संपूर्ण एकीकृत शिकायत निगरानी प्रणाली भीइसमें प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित करने का प्रावधान है,जिसे शिकायतों की वास्तविक समय निगरानी के लिए नियमिताधार पर डेटा/जानकारी का अद्यतन सुनिश्चित करना होता है शी-बॉक्स पोर्टल पर दर्जकी गई कोई भी शिकायत सीधे संबंधित कार्यस्थल के आईसी या जिले के एलसी के पास पहुंचती है, जैसा भी मामला हो पोर्टल कोइस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता के विवरण को छुपाता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि तरीकों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुरा लोगे और दूसरी तरफ, आपके सितारे कहां से सहायता तरना शुरू। तरन न सिर्फ हमारे साथ में और लाटन सुरी को सुनकर तरना सहायतारक ऊर्जा को सहयुक्त होगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां का स्वभावगत हमें संतुष्ट और कार्यक्षेत्र में सफल प्रदान करेगा

मेष
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

वृष
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कर्क
दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

सिंह
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

कन्या
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे।

तुला
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

वृश्चिक
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी। स्नेहीजनों के साथ चिन्हाशा बढ़ेगी।

धनु
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

मकर
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

कुंभ
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उत्सव में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मीन
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

शख्सियत

श्री नारायण टोंगस
एसपी नागौर (आईपीएस)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री नारायण टोंगस। जोकि इस समय नागौर जिले के पुलिस कप्तान पद को सुशोभित कर रहे हैं। 10 जून सन 1971 को पाली जिले के जैतारण तहसील के डिगरना गाँव में जन्में टोंगस साब बहुत ही ऊर्जावान पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। एम.ए (दर्शनशास्त्र) के रूप में एन्थ्रूकेन्द्र के बाद सन 1997 में राजस्थान पुलिस सेवा में आए और राजस्थान के विभिन्न जिलों में डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी के रूप में अपनी सेवाए दी और एक मजबूत और दमदार अधिकारी के रूप में मोर्चा संभाले रखा। 2020 में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति पर आए और कमाण्डेन्ट, 5जी बटालियन, आरएसी जयपुर लगे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक, चूरू। पुलिस उपायुक्त, क्राइम पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। पुलिस अधीक्षक, धौलपुर। पुलिस अधीक्षक, करौली। पुलिस अधीक्षक, एसओजी जयपुर। उपायुक्त पुलिस, जयपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन जयपुर।

अब पुलिस अधीक्षक, नागौर पद को सुशोभित कर रहे हैं। पुलिस सेवा में तनाव व भागदौड भरे जीवन में भी राजस्थान में टॉगस साब को एक ऐसे आईपीएस अधिकारी है के रूप में देखा जाता है जो अपनी फिटनेस के चलते दूसरे पुलिसकर्मियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। नागौर से खरनाल तक 20 किलोमीटर की दौर उन्होनें 68 मिनट में पूरी कर जवानों का हौसला बढ़ाया। फिटनैस के चलते पुलिस के जवानों के लिए मिसाल बन गए है नारायण टोगस सर रोज पाँच से दस किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं अभी हाल ही में। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उजवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

6 जून की महत्वपूर्ण घटनाएँ

- डेनमार्क तथा स्वीडन के बीच 1660 में शांति समझौता हुआ।
- शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की।
- भयंकर आग लगने के कारण मोस्को में 1752 को करीब 18,000 जलकर राख हो गए थे।
- नेपोलियन के भाई जोसफ को 1808 में आज ही के दिन स्पेन का राजा बनाया गया था।
- अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 1831 में दूसरा राष्ट्रीय काला सम्मेलन हुआ।
- अमेरिका के ईस्ट क्लीवलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार 1916 में दिया गया।
- सन 1918 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बेलेयू वुड के युद्ध में अमेरिका को पहली जीत मिली।
- फिनलैंड ने 1919 में बोलशेविक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- प्रिकमर्ग गणराज्य पर 1919 में हंगरी की लाल सेना का आक्रमण हुआ।
- ईसवी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी वायु सेना ने जापान के दक्षिणी नगर फ़ोकोला पर बम्बारी करके जापान के विरुद्ध अपना हवाई आक्रमण 1944 में आरंभ किया।
- ईरान गैस पाइप लाइन योजना पर 2005 में भारत और पाकिस्तान में सहमति।

6 जून को जन्मे व्यक्ति

- ब्रिटेन के रसायन व भौतिक शास्त्री जोज़फ़ प्रिसली का फ़ील्ड नामक नगर में 1733 को जन्म हुआ।
- एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज़ अधिकारी ह्यूम, ए. ओ. का जन्म 1829 में हुआ।
- हिंदी भाषा के साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 में हुआ।
- प्रसिद्ध शायर शौक़ बहराइची का जन्म 1884 में हुआ।
- मिस्र के विख्यात लेखक और साहित्यकार ताहा हुसैन का जन्म 1889 ईसवी को हुआ।
- 'कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक' और 'कन्नड़ की संपत्ति' के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक मास्ति वेंकटेश अय्यंगार का जन्म 1891 में हुआ।
- इण्डोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो का जन्म 1901 में हुआ।
- हिन्दी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार राजेन्द्र कृष्ण का जन्म 1919 में हुआ।
- अभिनेता, राजनेता और समाजसेवक सुनील दत्त का जन्म पश्चिमी पंजाब के झेलम (वर्तमान पाकिस्तान) 1929 में हुआ था।
- भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा का जन्म 1939 में हुआ।
- हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का जन्म 1955 में हुआ।
- स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी जिनको महान टेनिस खिलाड़ियों में गिने जाने वाले ब्योन बोर्ग का जन्म 1956 में हुआ।

6 जून को हुए निधन

- सामाजिक कार्यकर्ता कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का निधन 1967 में हुआ।
- कर्नाटक के हवें मुख्यमंत्री डी. देवराज अर्स का निधन 1982 में हुआ।
- दमदमी टकसाल के प्रमुख, खलिस्तान आंदोलन के नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले का निधन 1984 में हुआ।
- 'कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक' और 'कन्नड़ की संपत्ति' के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक मास्ति वेंकटेश अय्यंगार का निधन 1986 में हुआ।
- भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन 2004 में हुआ।

विशेष आलेख

बातचीत और आपसी संवाद ही एकमात्र विकल्प

भारत-बांग्लादेश वर्तमान संबंध (सम-सामयिक मुद्दा)

सुनील कुमार महला

पिछले कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश में एक-दूसरे के खिलाफ़ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में विवाद देखा जा रहा है और इस आशय की खबरें लगातार मीडिया की सुर्खियों में आ रहीं हैं। पाठक जानते होंगे कि बांग्लादेश में शेख़ हसीना सरकार के जाने और वहां अंतरिम सरकार के आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनाव के दौर से गुज़र रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिन्दू आठ प्रतिशत हैं, लेकिन यहां हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि कई मामलों में हत्याएं भी हो रही हैं, ऐसा मीडिया के हवाले से पता चला है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारत के खिलाफ़ प्रदर्शन कर चेतावनी दी थी कि बांग्लादेश में भारत के मंसूबे सफल नहीं होंगे। इधर,त्रिपुरा में बांग्लादेश के उप उच्चायोग में भारतीय प्रदर्शकारियों के घुसने की भी खबरें मीडिया की सुर्खियों में पढ़ने सुनने को मिलीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंसा के रवैए को देखते हुए आज भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश भारत के खिलाफ तो भारत बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश अंतरिम सरकार के क़ानूनी सलाहकार आसिफ़ नज़रुल ने कहा कि %बांग्लादेश भारत के 'प्रोपेगेंडा% का मिलकर सामना करेगा। देश सारे मतभेदों से ऊपर है। बांग्लादेश में इस सोच की कोई जगह नहीं है कि ये कमजोर, लाचार और झुका हुआ देश है?।% उल्लेखनीय है कि हाल ही में बांग्लादेश में चार दिसंबर को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक में देश की संप्रभुता, अस्तित्व, आज़ादी और गरिमा बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई गई है। बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है, वह बहुत ही चिंताजनक है। हमारे देश में अन्य देशों के साथ बांग्लादेश के लोग भी सुरक्षित तरीके से रहते हैं। भारत सभी की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और शांति, संयम, सद्भाव, सौहार्द में विश्वास करता है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले एक इस्कॉन मंदिर को बंद कराया गया और इसके एक दिन बाद हीइस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश ने चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों के एकाउंट को भी फ्रीज कर दिया। बांग्लादेश द्वारा संतों को भी गिरफ्तार किए जाने की खबरें आई हैं। जिन संतों को बांग्लादेश द्वारा गिरफ्तार किया गया है, वे भी इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए ही बताए जा रहे हैं। इस संबंध में इस्कॉन कोलकाता के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस्कॉन के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि वहां दो और हिंदू ब्रह्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं,चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता बताए गए हैं। हाल फिलहाल, भारत-बांग्लादेश के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति चल रही है,उसे ठीक नहीं ठहराया जा सकता है।भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर दोनों देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा हमेशा से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और शेख़ हसीना के बीच अनेक द्विपक्षीय मुलाक़ातें हुईं हैं और इससे भारत-बांग्लादेश के संबंधों का ग्राफ़ हमेशा ऊपर चढ़ता रहा है। उल्लेखनीय है कि जनवरी में शेख़ हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं थी, और भारतीय पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद शेख़ हसीना भारत आई थीं। भारत की अपनी द्विपक्षीय यात्रा के दौरान बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख़ हसीना ने यह बात कही थी कि %भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी, भरोसेमंद दोस्त और क्षेत्रीय साझेदार है और बांग्लादेश-भारत संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पीएम मोदी को बांग्लादेश आने के लिए आमंत्रित करती हूं।% बहरहाल कहना ग़लत नहीं होगा कि शेख़ हसीना के दौर में भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। आसिफ़ नसरूल का फ़ेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह कहना कि %भारत को ये समझना होगा कि ये शेख़ हसीना का बांग्लादेश नहीं है।%, कहीं न कहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर सवाल खड़े करता है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि दोनों देश चार हज़ार किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा आपस में साझा करते हैं और दोनों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते रहें हैं। बांग्लादेश की 94 फ़ीसदी सीमा भारत से लगती है। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश, भारत के लिए एक बड़ा बाज़ार बनकर उभरा है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच कई अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी है।पिछले साल ही दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार भारत-बांग्लादेश ऊर्जा पाइपलाइन भी शुरू हुई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच रेल कनेक्टविटी से लेकर बिजली की सप्लाई भी बढ़ी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में ही अखौरा-अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन किया गया था, जो बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के माध्यम से जोड़ता है। दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल जो दोनों देशों के बीच हो रहा वे वह ठीक नहीं है। दोनों देशों को पड़ौस की भूमिका को समझना चाहिए। आपसी सौहार्द, सद्भावना, संयम, शान्ति से ही दुनिया में सबकुछ संभव हो सकता है। झगड़ों, आपसी विवाद-फसाद, हिंसा, अत्याचार, एक दूसरे के खिलाफ आक्रोशित बयानबाजी,वैर-भाव से किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए बातचीत और आपसी संवाद ही एकमात्र विकल्प है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मामला बड़ा सूक्ष्म और उत्कृष्ट होता है। -व्लादिमीर जिरिनोवस्की

जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में हमला पंजाब राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति बताने के लिए पर्याप्त है। इस घटना के पीछे छिपी आतंकवादी एवं अलगाववादी साजिश की भी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

साजिश के संकेत

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में सेवा कर रहे पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर दिन-दहाड़े जानलेवा हमले की कोशिश न केवल राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बयां करती है, बल्कि सीमावर्ती राज्य पंजाब में सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। हालांकि इस घटना में सुखबीर सिंह बादल बाल-बाल बच गए, लेकिन प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े इनपुट मिले हैं, जो इसके पीछे गहरी साजिश का संकेत देते हैं। हमले के आरोपी का संबंध खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालसा लिबरेशन फोर्स से जुड़ा रहा है। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने तो साफ कहा कि अलगाववाद के मंसूबे को बढ़ावा देने के लिए यह हमला हुआ है। पाकिस्तान वर्षों से खालिस्तानी आतंकियों को सिर्फ शरण ही नहीं देता रहा है, बल्कि हथियारों की आपूर्ति करने के साथ उकसाता भी रहा है। ऐसे में, कोई हैरानी नहीं कि यह घटना उदारवादी माहौल को खत्म करने के इरादे से अंजाम दी गई हो। सिख श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होने के नाते स्वर्ण मंदिर में न तो वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है और न ही लोगों की तलाशी ली जाती है। अलबत्ता सादी वर्दी में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी वहां जरूर तैनात रहते हैं और उन्होंने ही हमलावर को मौके पर दबोचा। राज्य सरकार भले ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की चुस्ती के लिए पीठ थपथपा रही हो, पर सवाल उठता है कि सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद हमलावर जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त पूर्व उपमुख्यमंत्री के करीब कैसे पहुंच पाया और सुरक्षाकर्मी को उसके इरादों की भनक तक कैसे नहीं लग पाई, जबकि वह दो दिन पहले से रेकी कर रहा था। हालांकि आरोपी ने बताया कि सुखबीर सिंह बादल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को माफी दिलवाई और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करवाई थी,

इसलिए उसने हमला किया, लेकिन तथ्य यह है कि आतंकी चौड़ा की हिटलिस्ट में बादल परिवार पहले से ही था। वह इससे पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और खालिस्तानी आतंकवाद के दौरान वह 1984 में पाकिस्तान भी गया था। सीमावर्ती राज्य पंजाब आतंकी गतिविधियों के निहाल से संवेदनशील है। ऐसे में जरूरी है कि इस घटना की विस्तृत जांच की जाए और संलिप्त लोगों को सजा दिलवाने के साथ-साथ आतंकवादी एवं अलगाववादी साजिश की भी पड़ताल की जाए और पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था ऐसी मजबूत की जाए कि आतंकवादियों और अलगाववादियों के मंसूबे पूरे न हो सकें।

अमेरिका से सकारात्मक संदेश

ट्रंप द्वारा चीन और कनाडा विरोधी राजनेता को विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने से एशिया में समीकरण बदल सकते हैं। हिंदू-अमेरिकी को सलाहकार बनाना, विशेषकर तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक और काश पटेल को एफबीआई प्रमुख के रूप में नियुक्त करना सकारात्मक संदेश है।

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

दुनिया इस समय बड़े भू-राजनीतिक बदलाव के चौराहे पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों का भविष्य खासा महत्व रखता है, जिसके संकेत ट्रंप की दो प्रमुख नियुक्तियों से स्पष्ट हैं। ट्रंप ने भारत समर्थक माइकल वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) बनाया है, तो हिंदू अमेरिकी तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक नियुक्त किया गया है। एफबीआई प्रमुख नियुक्त किए गए काश पटेल की भारतीय विरासत उनके व्यक्तित्व में दिलचस्प आयाम जोड़ती है। अमेरिकी राजनीति में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव को भारत के बढ़ते महत्व के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि पटेल की नियुक्ति जातीय पृष्ठभूमि की अपेक्षा उनकी वफादारी, पेशेवर रिकॉर्ड और ट्रंप के एजेंडे में फिट बैठना है।

परंपरागत रूप से भारतीय-अमेरिकी समुदाय का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहता था, लेकिन अब ट्रंप के लिए समर्थन दिखता है। बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत और अमेरिका, अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिए तैयार हैं। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' की बातें वैश्विक वैश्विक स्तर पर विभाजनकारी हैं, लेकिन भारत के वैश्विक प्रभाव और आत्मनिर्भरता की आकांक्षाओं के साथ स्वाभाविक तालमेल हो सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही व्यापार, रक्षा और तकनीक में भी दोनों देशों के आगे रहने की संभावना है।

महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और उभरती सुरक्षा चिंताओं के बीच इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के बीच उभरती साझेदारी का केंद्र बिंदु होगा। भारत-अमेरिकी संबंधों की दिशा न केवल द्विपक्षीय भाग्य को, बल्कि व्यापक वैश्विक व्यवस्था को भी आकार देगी, जिसमें ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की रणनीतिक गणना में भारत का

प्रमुख स्थान सुनिश्चित होने की संभावना है। इस बार प्रभावी भारतीयों ने अमेरिका-भारत संबंधों को प्राथमिकता देने, सुरक्षा, व्यापार और आतंकवाद से लड़ने पर जोर देने की ट्रंप की नीतियों को अपना समर्थन दिया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय-अमेरिकियों का सालाना योगदान करीब 200 अरब डॉलर है। यह योगदान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों से आता है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका को उजागर करता है।

ट्रंप की वापसी ने कई देशों को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टिप्पणी की कि ट्रंप की वापसी से कई देश असहज हो सकते हैं, लेकिन भारत नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी को लाभ मिल सकता है, खासकर रूसी प्रतिबंधों और पश्चिम के साथ भारत के तनाव के बीच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाल्ट्ज को चुना है, जो अपने दृढ़ चीन विरोधी और जूटो विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप के कट्टर सहयोगी वाल्ट्ज से उम्मीद की जाती है कि वह ट्रंप के वादों के साथ जुड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक कठोर रुख अपनाएंगे। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की कार्रवाइयों की उनकी मुखर आलोचना इस क्षेत्र में संभावित संघर्षों के लिए अमेरिका के तैयार रहने पर बल देने को रेखांकित करती है।

वर्ष 2023 में स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भारत दौरे पर आए माइकल वाल्ट्ज ने भारत और अमेरिका के संबंधों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी तथा भारत को अमेरिका का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बताया था। वाल्ट्ज की नियुक्ति कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूदो के लिए बुरी खबर है। वह भारत के अनुकूल अमेरिका-कनाडा संबंधों को नया आकार दे सकते हैं। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले ट्रूदो को बाइडन प्रशासन का समर्थन मिलता था, लेकिन ट्रंप प्रशासन भारत-अमेरिका संबंधों पर जोर देता है। वाल्ट्ज ने भी कहा था कि 21वीं सदी में भारत-अमेरिका के संबंध सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने संवेदनशील नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के उपायों की वकालत करते हुए एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

विशेषज्ञों की राय है कि ट्रंप ने दीर्घकालिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए हिंदू अमेरिकी तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया है। भारत और अमेरिका संबंधों की प्रबल समर्थक तुलसी भारत और इसकी सांस्कृतिक विरासत पर अपने सकारात्मक विचारों के लिए जानी जाती हैं। नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक (डीएनआई) के रूप में वह अमेरिका की 18 एजेंसियों से खुफिया जानकारी के लिए समन्वय करेंगी, जो दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी और रणनीतिक खुफिया सहयोग को मजबूत कर सकती है। तुलसी भारत और अमेरिकी संबंधों की पक्षधर हैं, तो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी नीतियों की विरोधी। इससे भारत को आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई में फायदा होगा। गबार्ड की नियुक्ति से भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता पर भी एक तरह से अंकुश लगेगा। उनके कार्यकाल में क्वाड के भीतर खुफिया सहयोग में नया जोश देखने को मिल सकता है, खासकर समुद्री सुरक्षा और चीनी निगरानी रणनीति पर।

निर्णायक मोड़ पर खड़ी दुनिया के सामने ट्रंप की वापसी नाटो की प्रतिबद्धताओं, यूक्रेन युद्ध और भारत व चीन जैसी शक्तियों के साथ उनके संबंधों से पश्चिमी प्रभाव की भावी स्थिरता और वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्धारण होगा। यूरोप के प्रति ट्रंप की नीतियां अनुकूल व्यापार सौदों या रक्षा खर्च पर रियायतों की मांग में प्रकट हो सकती हैं। कुल मिलाकर, कई मायनों में ट्रंप का राष्ट्रपतित्व अमेरिकी विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन का प्रतीक होगा, जो व्यावहारिकता के साथ मिश्रित राष्ट्रवाद के अपने ब्रांड पर लौटेगा। हालांकि यह दृष्टिकोण सहयोगियों के साथ टकराव पैदा कर सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल सकता है और मौजूदा राजनयिक मानदंडों को चुनौती दे सकता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

प्रियांका वीरट

दिनचर्या में छिपी है हमारे हिस्से की खुशी

इतिहास में सबसे सफल लोग, जिन्हें अपने काम में 'प्रतिभाशाली' माना जाता है, अपनी कला का माहिर माना जाता है, उन सबमें उनकी प्रतिभा के अलावा एक और चीज पाई जाती थी कि वे अपनी कठोर (निश्चित) दिनचर्या का पालन करते थे। दिनचर्या उबाऊ लगती है और हमें 'अच्छी जिंदगी' के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, यह उससे ठीक उलट होती है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लगातार 'ज्यादा' पाने की इच्छा से खुशी मिलती है, यह और बात है कि वह 'ज्यादा' होता क्या है, फिर भी हम यह नहीं समझ पाते कि कोई दिनचर्या होने का मतलब यह नहीं कि आप उसी दफ्तर में उतने ही निश्चित घंटों तक बैठे रहें। हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में हर महीने किसी नए देश में जाना शामिल हो। वह एक तरह से नियमित रूप से अनियमित हो सकती है।

यहां मसला यह नहीं है कि दिनचर्या क्या है, बल्कि यह है कि लगातार गति और अपेक्षित परिणामों के माध्यम से आपका अवचेतन मन कितना स्थिर और सुरक्षित रह पाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी किन चीजों से मिलकर बनी है, बल्कि अहम बात यह है कि आप क्या फैसला लेते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं। दिनचर्या महत्वपूर्ण है, इससे हमारे व्यक्तित्व के विकसित होने का आयाम तैयार होता है। ध्यान रखें कि मन के मुताबिक चलने से वह सब आपकी जिंदगी में चला आता है, जिसे आप नहीं चाहते। हमारे लिए असल खुशी लाने वाली ज्यादातर चीजें अस्थायी, तुरंत संतुष्टि लाने वाली ही नहीं होतीं, उन चीजों के साथ प्रतिरोध भी बना रहता है और उनके लिए त्याग की जरूरत होती है। अन्य कारणों के साथ-साथ ये कुछ कारण हैं, जिनसे दिनचर्या महत्वपूर्ण हो जाती है और खुश रहने वाले लोग उनका अधिक पालन करते हैं। यह मानना हमें सही लगता है कि विचारों या तनावों से हमारे मूड बनते हैं, यानी जिन चीजों से दिन भर हमारा सामना होता है और जो हमें अचानक झटका देती हैं, पर ऐसा नहीं होता। मनोविज्ञानी रॉबर्ट थेयर के अनुसार, 'हमारी आदतों से हमारा मूड बनता है। हम कितना सोते हैं, हम कितना सक्रिय रहते हैं, हम कितनी बार सोचते हैं आदि।' कहने का अर्थ यह है कि कोई एक विचार हमें अचानक परेशान नहीं करता है, बल्कि लगातार उस विचार पर सोचने से उसका प्रभाव जमा होता चला जाता है। बेकाबू दिमाग बारूदी सुरंग जैसा होता है। किसी तरह का नियंत्रण न होने, ध्यान केंद्रित न होने या कोई आत्मनियंत्रण न होने की स्थिति में कोई भी चीज आपको इस सोच की तरफ ले जा सकती है कि ऐसा कुछ है, जो आपको चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। दिनचर्या के न होने से हम बस टालमटोल की स्थिति में रहते हैं। उससे हम अपने अवचेतन मन को मौका देते हैं कि वह हमसे कहे कि अब तुम काम से आराम ले सकते हो, जबकि असल में आपको निर्धारित समय में अपना काम पूरा करना है। ('101 एसेज दैट विल चेंज द वे यू थिंक' पुस्तक के अनुदित अंश।)

दिनचर्या के न होने से हम टालमटोल की स्थिति में रहते हैं। उससे हम अपने अवचेतन मन को मौका देते हैं, जो हमें काम से आराम के लिए उकसाता है, जबकि काम को निर्धारित समय में पूरा करना होता है।

सीखने पर दें जोर

सूत्र

सफलता कोई दुर्घटना नहीं है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, त्याग और सबसे बढ़कर, आप जो कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं उसके प्रति प्रेम है। जैसे-आपने निश्चय किया है कि किसी किताब के प्रतिदिन तीन पन्ने लिखेंगे, तो इसका पालन भी करना होगा। यदि यह आ गया, तो समझो यह हमारी दिनचर्या के प्रवाह की शुरुआत है।

दूसरा पहलू

अक्सर हम बच्चों को अनजबियों से बचाव के बारे में सचेत करते हैं, पर शोध बताते हैं कि परिचित ही ज्यादा यौन शोषण करते हैं।

बच्चों की सुरक्षा के तरीके भी बदलने होंगे

बाल यौन शोषण पर बात करना तो दूर, इस बारे में सोचना ही असहज है। एक वयस्क द्वारा बच्चे के साथ यौन व्यवहार में संलग्न होना, घिनौना है। इस बात पर यकीन करना आसान है कि ऐसा शायद ही कभी होता है, यह जब होता है, तो केवल उन बच्चों के साथ, जिनके माता-पिता उनकी रक्षा नहीं कर पाते। मेरे बच्चे छोटे थे, तब खेल के मैदान में खौफनाक पुरुषों पर नजर रखती थी। बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक और कोच पर संदेह करती थी। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, तो मैंने उन्हें सिखाया कि अच्छा स्पर्श क्या होता है, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य से गले मिलना। वहीं बुरे स्पर्श में कोई उनके निजी अंगों को छूता हो।

मेलिसा ब्राइट

15 वर्ष पारिवारिक हिंसा पर व 8 वर्ष बाल दुर्व्यवहार, जिसमें यौन दुर्व्यवहार भी शामिल है पर लगभग एक चौथाई सदी तक शोध करने के बाद पता चला कि हम बच्चों की सुरक्षा के लिए पुरानी रणनीतियां अपना रहे हैं। सेंटर फॉर वायलेंस प्रिवेंशन रिसर्च, जो बाल यौन शोषण के बारे में शिक्षित करते हैं और पीड़ितों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं कुछ बातें आपको आश्चर्यचकित भी कर सकती हैं। पहले, बाल यौन शोषण के बारे में दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण था, इसका सीधा-सा अर्थ, वयस्कों और बच्चों के बीच सभी यौन गतिविधियां दुर्व्यवहार का एक रूप हैं। वहीं बाल यौन शोषण में दो बच्चों के बीच सहमति के बगैर यौन संपर्क, इसमें यौन उत्पीड़न अपराध शामिल हैं। अब प्रौद्योगिकी आधारित बाल शोषण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें इंटरनेट आधारित गेम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा उत्पन्न सामग्री शामिल है।

कई लोग सोचते हैं कि उनके समुदाय में बाल यौन शोषण नहीं होता। लेकिन नवीनतम डाटा के अनुसार, दस में से एक वयस्क, संभवतः पांच में से एक यौन शोषण का अनुभव करता है। सभी जातीय समूहों में बाल शोषण होता है।

नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की 2021 से 2023 की रिपोर्ट दर्शाती है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में 300 फीसदी वृद्धि हुई है। कई लोग सोचते हैं कि उनके समुदाय में बाल यौन शोषण नहीं होता। लेकिन नवीनतम डाटा से पता चलता है कि दस में से एक वयस्क, संभवतः पांच में से एक यौन शोषण का अनुभव करता है। सभी जातीय समूहों में बाल शोषण होता है। खेल के मैदान में खौफनाक आदमी की पहचान उतना कारगर नहीं है, क्योंकि 90 फीसदी बाल यौन शोषणकर्ता पीड़ित को जानने वाले होते हैं। संक्षेप में कहें, तो बाहरी अजनबियों से सावधान रहना सिखाना जरूरी है, लेकिन बच्चों को अपनों से बचाव के तरीके भी बताने होंगे। साथ ही अपने बच्चों के सोशल मीडिया पर भी नजर रखें। (-द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

स्टील का आयात

भारत ने बीते वित्त वर्ष में चीन और दक्षिण कोरिया से सबसे ज्यादा निर्मित स्टील का आयात किया है।

चीन	32.30%
दक्षिण कोरिया	32.09%
जापान	15.31%
वियतनाम	8.86%
अन्य	11.44%

आंकड़े विभिन्न देशों से आयात किए निर्मित स्टील के, प्रतिशत में | स्रोत : PC

कुलशेखर भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि एक दिन रामकथा में खर-दूषण का प्रसंग आने पर श्रीराम की सहायता के लिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर लिया।

भक्त कुलशेखर

अंतर्यात्रा
संकलित

कोल्लिनगर (केरल) के राजा दृढ़व्रत बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके यहां तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। राजा दृढ़व्रत ने पुत्र का नाम कुलशेखर रखा। बताया जाता है कि कुलशेखर ने छोटी अवस्था में ही तमिल और संस्कृत भाषा के साथ ही सभी वेद-शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। राजा ने कुलशेखर को योग्य समझकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद ईश्वर भक्ति में लग गए। राज्य मिलने पर भी कुलशेखर भगवान की भक्ति में लीन रहे।

बताया जाता है कि वह सिंहासन पर भगवान राम को साक्षी मानकर राज्य करते थे। एक दिन कुलशेखर रामकथा सुन रहे थे, जिसमें खर-दूषण वध का प्रसंग आया। कुलशेखर रामकथा में इतने लीन हो गए कि जब उन्होंने कथावाचक से सुना कि प्रभु श्रीराम माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को कुटी पर छोड़ गए हैं और राक्षसों की सेना से लड़ने के लिए अकेले निकल पड़े हैं। कुलशेखर ने सोचा कि प्रभु श्रीराम अकेले खर-दूषण की सेना से कैसे लड़ेंगे। वह कथा से उठे और अपनी सेना को आदेश दिया कि खर-दूषण के खिलाफ युद्ध के लिए भगवान राम को सहायता के लिए चलें। कुलशेखर आगे बढ़ ही रहे थे कि कथावाचक ने कहा कि भगवान राम, खर-दूषण का वध कर लौट आए हैं, तब उन्हें शांति मिली।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 सितंबर, 1962

भारत और इंडोनेशिया के बीच भारी मनमुटाव

भारत व इंडोनेशिया के बीच भारी मनमुटाव उत्पन्न

इंडोनेशिया के उद्योग मंत्री ने कहा कि एशियाई खेल-कूदों में भारत के प्रतिनिधि का जो रवैया रहा है, उससे हमें ठेस पहुंची है। उसका असर भारत सरकार और भारतीयों के प्रति बरती जाने वाली नीति पर पड़ना स्वाभाविक है।

आंबेडकर की वैचारिक विरासत

डॉ. आंबेडकर दक्षिण-पंथ-वामपंथ, पुरातनता-आधुनिकता की प्रतिद्वंद्विता की अतियों के बीच 'सम्यक-विकास' का मार्ग निकाल कर लाए।

श्यौराज सिंह 'बेचैन' — परिनिर्वाण दिवस

आज छह दिसंबर, डॉ. बीआर आंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। उनके लिए शुक्रवार का एक और खास महत्व था। इस दिन उनके 'अस्पृश्यता' विरोधी आंदोलन के सहयोगी बाल गंगाधर तिलक के सुपुत्र 'श्रीधरपंत बलवंत तिलक' ने डॉ. आंबेडकर के नाम एक पत्र लिखकर शुक्रवार 25 मई, 1928 को आत्महत्या कर ली थी। डॉ. आंबेडकर ने बलवंत पर एक मृत्युलेख लिखा और उनके पत्र की छाया प्रति के साथ 'दुनिया' (मराठी स.) 2 जून, 1928 के 'तिलक' विशेषांक में बताया कि वह 'समाज समता संघ' पूना के उपाध्यक्ष थे। अस्पृश्यता का अंत करना जरूरी मानते थे। इस कारण उन्हें 'केसरी' की पत्रकारिता से पहले ही बाहर कर दिया गया था।

छह दिसंबर, 1956 को डॉ. आंबेडकर चले गए। दो दिन बाद 'दैनिक मराठा' के मुख्य पृष्ठ पर एक कविता उनकी श्रद्धांजलि के साथ छपी, उसका हिंदी अनुवाद है, 'अग्नि पर ही आजीवन प्रकाशित रहे, अग्नि पर ही चिर निद्रा ले रहे हो।/यह चिता तो बुझ जाएगी, परंतु तुम्हारा प्रकाश चिरंतन रहेगा।/ चांद सितारों की तरह उनके विचारों का प्रकाश तो दसों दिशाओं में फैला है, परंतु सूरज की भांति तेज पूर्ण प्रकाश यदि है, तो वह 'भारत का संविधान' है। हाल ही में 75वां संविधान दिवस मनाया गया है। केंद्र तथा राज्य सरकारों में पक्ष-विपक्ष सबने संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी-धर्मनिरपेक्ष शब्द को मूल ढांचे का अंग' मानते हुए प्रस्तावना से नहीं हटाए जाने की घोषणा करके संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि की पुष्टि की है।

आंबेडकर और संविधान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। डॉ. आंबेडकर दक्षिण-पंथ और वामपंथ, पुरातनता और आधुनिकता की प्रतिद्वंद्विता की अतियों के बीच 'सम्यक-विकास' का मार्ग निकाल कर लाए। विगत एक-डेढ़ दशक से संविधान और आंबेडकर को लेकर समसामयिक विमर्श अधिकाधिक तीव्र हुआ है। सरकार ने ऐसे कई संविधान संशोधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराए हैं, जिसके बारे में डॉ. आंबेडकर का पक्ष विचारणीय है। इनमें दो संशोधन तो आरक्षण को लेकर हैं, जिनमें एक 103वां संविधान संशोधन 2019 'दस फीसदी आरक्षण' को लेकर है। संविधान के प्रति पहला सम्मान तो, सांविधानिक पदों को रिक्त न छोड़ा जाना है। दूसरा, जिन नागरिकों की माली हालत अच्छी नहीं है, उन आम नागरिकों तक भी न्याय पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में संसद की सकारात्मक सक्रियता ही है, जो कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है, 'सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक न्यायाधीशों के पांच हजार छह सौ ग्यारह (5,611) पद रिक्त पड़े हैं। ग्रामीण नागरिकों का सर्वाधिक वास्ता जिला न्यायालयों से ही होता है।

सवर्ण गरीबों के लिए संविधान संशोधन संसद में सर्वसहमति से पास हुआ था। कांग्रेस, सपा, बसपा सहित वे दल, जो संविधान का रक्षक होने के दावे करते हैं और वर्तमान सरकार को संविधान विरोधी बताते हैं, उन्होंने इसे समर्थन दिया था। उसी तरह जब यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. सुखदेव थोरात प्रश्न करते हैं कि एससी, एसटी में विभाजन करने से न्याय कैसे मिलेगा? शताब्दियों से अस्पृश्यता के शिकार वंचितों को समानता का लक्ष्य कैसे प्राप्त कराया जाएगा, तो कहीं से कोई उत्तर नहीं आता? एससी, एसटी में उपजाति वर्गीकरण आंबेडकर की संकल्पना के अनुकूल नहीं है। संविधान से इतर भी उनके विपुल साहित्य में इसके कोई संकेत नहीं मिलते।

डॉ. आंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति के सक्रिय अध्यक्ष के रूप में अपनी सेहत की कुर्बानी दी। तथापि अपने इस महान कार्य को लेकर उन्होंने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि नहीं बदली। वे किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने न केवल संविधान, अपितु लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था, 'संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।' दूसरी आशंका उन्होंने 'बीबीसी' के ब्रिटिश पत्रकार को दिए साक्षात्कार में व्यक्त की, 'लोकतंत्र तो नाम के लिए ही रह जाएगा।'

आज दिखाया होगा कि संविधान को लेकर विमर्श किस दिशा में जा रहा है और लोकतंत्र के प्रति आंबेडकर की आशंकाएं सच तो नहीं होने जा रहीं। उन्होंने कहा था कि 'मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत-वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए लिया है।' वह मानते थे कि सवर्णता की मनोवृत्ति दलित मुक्ति की राह को कभी आसान नहीं होने देगी। उनके जाने के बाद भय और असुरक्षा की अभिव्यक्ति भाषायी दलित साहित्य में तीव्रता से हुई। वैचारिक रूप से वह और अधिक सशक्त प्रेरणा-पुंज बने।

भारत-बांग्लादेश संबंध

सुधार के प्रयास जरूरी

भारत-बांग्लादेश संबंध बहुत खराब स्थिति में हैं। यदि सुधार के प्रयास न हुए तो इनमें और गिरावट आ सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध लंबे समय से सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग से पहचाने जाते थे, पर हालिया महीनों में वे बहुत खराब हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन, राजनयिक नाराजी तथा बढ़ी हुई सुरक्षा चिन्ताओं के कारण पड़ोसियों के बीच खाई चौड़ी हो रही है। बांग्लादेश में एक हिंदू संत की गिरफ्तारी से अशांति भड़की है, संबंधों पर और दबाव पड़ा है जो अगस्त, 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहले से ही खराब थे। बांग्लादेश में ऐतिहासिक रूप से अल्पसंख्यकों को भेदभाव तथा कभी-कभी हिंसा का सामना करना पड़ा है। अक्सर राजनीतिक कारणों से यह हिंसा बढ़ी है। अगस्त में अचानक तख्तापलट के समय तक शेख हसीना की सरकार सत्ता में थी और उस समय वह अल्पसंख्यकों का काफी समर्थन करती थी, हालांकि उनके आलोचकों का मानना है कि यह समर्थन सुसंगत नहीं था। तथाकथित भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ भारी प्रदर्शनों के बाद हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद, लंबे समय से देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार की स्थितियां उजागर हो गई हैं। चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिससे चिटगांव में अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरोकारी के पक्ष में विरोध प्रदर्शन फूट पड़े। उनको जमानत देने से इनकार तथा बाद में उनके मामले की सुनवाई जनवरी, 2025 तक टालने से तनाव और बढ़ा है।

इस घटना से भारत में हिंदू संगठनों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है जिनको भारतीय जनता पार्टी-भाजपा का समर्थन प्राप्त है। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन में अगरतला में बांग्लादेश कौंसुलेट पर हमला हो गया जिससे राजनयिक तनाव और बढ़ गया। कौंसुलेट में उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ पर ढाका ने तीखी प्रतिक्रिया की। उसने घटना को 'अघन्य' बताते हुए भारत से कठोर कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। इस बीच भारतीय अधिकारियों ने हमले की निन्दा करते हुए बांग्लादेश राजनयिक मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है तथा भारतीय जनता का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया है। ढाका में कौंसुलेट पर हमले ने विरोध-प्रदर्शनों को हवा दी जिससे छात्र और एक्टिविस्ट भारत से जवाबदेही की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। यह स्थिति दोनों देशों के राष्ट्रवादियों व धार्मिक तत्वों के लिए 'उकसावे' की तरह है। दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने के व्यापक जोखिम हैं। भारत के लिए बांग्लादेश सीमा सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थायित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण साझीदार है। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं जिससे लंबे समय तक गतिरोध संकट का कारण बन सकता है। लेकिन वर्तमान समय में परस्पर विश्वास लगभग समाप्त हो गया है। भारत ने बार-बार बांग्लादेश से अनुरोध किया है कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफजारी हिंसा से निपटे। दूसरी ओर बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि भारतीय मीडिया का एक हिस्सा जानबूझ कर गलत सूचनायें फैलाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों को तत्काल तनाव घटाने के प्रयास करने चाहिए। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से पैदा तनाव तत्काल दूर करने के प्रयास होने चाहिए। उनको जल्दी से जल्दी रिहा करने के साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन पर उठ रहे सवालों को संबोधित करना होगा। भारत की जनता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया करती है, ऐसे में बांग्लादेश को अपने देश में कट्टरपंथियों पर कठोरता से लगाम लगानी चाहिए।

चुनाव परिणामों से प्रभावित विपक्षी एकता

हालिया चुनावों में पराजय से विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल दलों के बीच दरारें दिखने लगी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर उभरी है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं)

महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों के हालिया चुनाव परिणामों से विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में दरारें दिखने लगी हैं। विधानसभा चुनावों में निराशाजनक नतीजों के बाद 'इंडिया' गठबंधन के कुछ साझीदार अपने एजेंडों पर अलग से ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते वे संसद के वर्तमान सत्र में विपक्षी दलों के बीच परस्पर समन्वय की चिन्ता भी नहीं कर रहे हैं। इनमें आम आदमी पार्टी-आप तथा तृणमूल कांग्रेस शामिल हैं। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी और उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी गठजोड़ की संभावना खारिज कर दी है।

पहले 'इंडिया' समूह को उम्मीद थी कि वह एकजुट होकर दिल्ली में भाजपा-विरोधी मतों को एकसाथ ला सकता है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल की घोषणा से संभावित एकता में दरार स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। इसके साथ ही अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन बनाने में कोई दिलचस्पी लेंगे। शिवसेना की परंपरागत रूप से महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में मजबूत पकड़ रही है और बदली हुई परिस्थितियों में वे इसे फिर से खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में 'इंडिया' गठबंधन साझीदारों के तत्काल एकजुट होने तथा प्रभावी सहयोग की संभावनायें धूमिल हो गई हैं। गठबंधन में एकजुटता सुनिश्चित करना अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि हर राजनीतिक पार्टी गलतियां करती है, पर सफल पार्टियां इन गलतियों से सीख कर अपने कामकाज में सुधर करती हैं।

'इंडिया' समूह ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का लक्ष्य बनाया था और वह इसमें कुछ सीमा तक सफल भी हुआ। भाजपा को जदयू और तेलगू देशम पार्टी के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन विधानसभा चुनावों में गठबंधन ऐसी कोई रणनीति बनाने में विफल रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के हालिया चुनावों से दो प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आते हैं। पहला, महाराष्ट्र में भाजपा नीत राजग की महत्वपूर्ण विजय है। दूसरा, झारखंड में हेमंत सोरेन द्वारा अपनी स्थिति इस तथ्य के बावजूद आसानी से मजबूत बनाए रखना है कि उनको भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा था। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, रांकापा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने जमीनी स्तर पर उपलब्ध संकेतों को गलत समझा और क्या भाजपा ने झारखंड में गलतियां कीं?

हालिया चुनाव परिणाम दलगत विकास में खोए अवसरों का खुलासा भी करते हैं। यदि कांग्रेस ने अतीत की गलतियों से बेहतर सबक सीखे होते और आवश्यक परिवर्तन किए होते तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। कांग्रेस ने चुनाव-पश्चात स्थितियों पर वैसे विश्लेषण नहीं किए जैसे पचमढ़ी या शिमला सम्मेलनों में किए गए थे।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा उनके द्वारा चयनित सहयोगियों के नियंत्रण में है। हालांकि, राहुल गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों में कड़ी मेहनत की तथा व्यापक अभियान चलाया, पर पार्टी बेहतर नतीजे नहीं दिखा सकी। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि उन्होंने अभी हालिया हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम से कोई सबक नहीं सीखा है और वे प्रदेशों में दूसरों को अनदेखा कर केवल एक नेता पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके साथ ही टिकट वितरण में गलत निर्णय जीतने वाले उम्मीदवारों की संभावनायें सामने लाने में विफल रहे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि कांग्रेस पार्टी, रांकापा व शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को चुनावी विमर्श पर ध्यान देना होगा। कांग्रेस को जातीय मुद्दों तथा संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर पुनः विचार कर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना होगा क्योंकि मतदाता इससे आकर्षित नहीं होते हैं।

अगला महत्वपूर्ण अवसर 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों का चुनाव है। राजग के इनमें से पांच सीटों पर जीतने की आशा है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। यदि यह अनुमान सही बैठता है तो राजग को उच्च सदन में भी बहुमत मिल जाएगा

जनता से संबंध विच्छेद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी को अपनी रणनीति पर पुनः विचार करना होगा तथा ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जो सचमुच मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। इनमें रोजी-रोटी के मुद्दे शामिल हैं। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना जरूरी है। इसके पहले भी राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर किए हमलों से कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि इसके बजाय इससे कांग्रेस का शिवसेना के साथ तनाव बढ़ा था क्योंकि वह सावरकार को आदर्श मानती है। इन पार्टियों को भाजपा के मातृ संगठन आरएसएस की बढ़ती शक्ति का भी एहसास नहीं है जो भाजपा की सफलता के लिए लगातार काम करता है। कद्दावर मराठा नेता शरद पवार हालिया पराजय के बाद निराश हो सकते हैं क्योंकि उनको अपने भतीजे अजीत पवार के मुकाबले चुनाव में नीचा देखना पड़ा है, जबकि उन्होंने ही अजीत पवार को राजनीतिक शिक्षा दे कर पाला पोसा है। अजीत पवार के भाजपा के साथ जाने पर दोनों के बीच टकराव के संकेत स्पष्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने चाचा को धोखा दे कर भाजपा को सरकार बनाने में सहायता की थी। निर्वाचन आयोग द्वारा अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस स्वीकार करने से स्थिति और खराब हो गई थी, जबकि शरद पवार ने ही रांकापा की स्थापना की थी और वे उसे अनेक बार सत्ता में लाए थे।

निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से पवार को भारी धक्का लगा। इसी प्रकार शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को अपने पिता की विरासत मिली, लेकिन उनको पार्टी के नाम और चुनाव निशान से अलगाव झेलना पड़ा और वे चुनाव में पराजित हुए। शिवसेना के विद्रोही एकनाथ जिंदे ने एक गठबंधन के माध्यम से भाजपा को महाराष्ट्र सरकार में आने में सहायता की। इन दोनों नेताओं को अपनी लोकप्रियता में गिरावट के कारणों पर आत्मावलोकन करना चाहिए। दूसरी ओर 'इंडिया' गठबंधन के साझीदार झारखंड मुक्ति मोर्चा-जेएमएम ने दिखाया कि अनेक चुनौतियों के बावजूद विजय कैसे पाई जाती है। जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया जिसमें सोरेन का जेल जाना भी शामिल था। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनावों ने भी दिखाया है कि भाजपा अजेय नहीं है। भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव लगातार चलते रहते हैं जिसका अर्थ है कि चुनावों का मौसम कभी समाप्त नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण अवसर 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों का चुनाव है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इनमें से पांच सीटों पर जीतने की आशा है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है। यदि यह अनुमान सही बैठता है तो राजग को उच्च सदन में भी बहुमत मिल जाएगा जिससे कांग्रेस पार्टी की संसद में स्थिति और खराब होगी।

वर्तमान समय में आठ सीटें खाली हैं जिनमें से चार नामांकन श्रेणी में तथा चार जम्मू कश्मीर चुनाव के परिणामस्वरूप हैं। प्रत्येक चुनाव उम्मीदवारों और पार्टियों की सफलता और विफलता के रूप में महत्वपूर्ण सबक देता है। इन परिणामों का संबंध स्पष्ट रूप से पीढ़ीगत बदलावों से भी है और इस प्रकार परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भावी पीढ़ियों को अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। अंततः सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपनी गलतियों से तेजी से सबक सीखते हैं। विजेताओं को सहनशील होना चाहिए, जबकि पराजित होने वालों को भी अपने भीतर प्रेरणा जागृत रखनी चाहिए।

स्वभावना: रूपांतरण का मार्ग

> हमारा जन्मजात स्वभाव हमारे जीवन में एक परिभाषित शक्ति और एक दुर्जेय विरोधी दोनों है।

अजित कुमार बिश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक शिक्षक हैं)

हम इसके साथ पैदा होते हैं। स्वभाव ('स्वभाव') वह है जो हमने पिछले जन्मों में किया है और हमारी गहरी इच्छाएं जो अभी भी अधूरी हैं। यह भाग्य और बड़ी घटनाओं का हिस्सा है, दोनों अच्छे और बुरे ('प्रारब्ध')। स्वभाव हमें परिभाषित करता है। चरित्र, व्यक्तित्व, व्यवहार, मनोदशा, दृष्टिकोण, राय, विश्वास, प्राथमिकताएं, हम कैसे निर्णय लेते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं और हम किस चीज की परवाह करते हैं, ये सभी हमारे स्वभाव से जुड़े हैं। आध्यात्मिक रूप से कहें तो, तीन गुण ('गुण') इसे बनाते हैं। वे हर व्यक्ति में अलग-अलग प्रतिशत में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छे आदमी में अच्छाई का गुण ज्यादा होगा; एक बुरे आदमी में अंधकार का गुण ज्यादा होगा और बाकी गुण बीच में होंगे। हालांकि, ये गुण हमेशा वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अच्छाई जुनून और अंधकार पर हावी होकर प्रबल होती है; अंधकार अच्छाई और जुनून पर हावी होकर प्रबल होता है; और जुनून अच्छाई और अंधकार पर हावी होकर प्रबल होता है। (भगवद्गीता 14.10)अच्छे लोगों के साथ यही होता है।

अस्थायी रूप से उनके विचार और कार्य अंधकार में आ जाते हैं और वे काम-वासना, क्रोध आदि से व्यवहार करते हैं। इसकी तुलना बुरे लोगों से करें, जो स्वभावतः बुरा व्यवहार करते हैं। जब सद्गुण की प्रबलता प्राप्त होती है, तभी वे अच्छा व्यवहार करते हैं। दुर्भाग्य से, एक सामान्य व्यक्ति बीच में पड़ जाता है और उसके स्वभाव में अनेक दोष होते हैं। वह सामान्यतः क्या करता है? वह अपनी इंद्रियों का यथासंभव भोग करना चाहता है; कर्तव्यों से बचना चाहता है; चतुराई से काम करने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि धोखा भी करता है, अपने को श्रेष्ठ समझता है; दूसरों पर हंसता है; और जब भी दुःख आता है, तो उससे घृणा करता है, उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराता है।

यह इतना बुरा नहीं है कि वासना, क्रोध, लोभ, घृणा आदि नकारात्मक भावनाओं के अंतर्गत आ जाए। इनके द्वारा प्रेरित होकर व्यक्ति बुरे कार्य करता है और दण्ड का पात्र बनता है। उदाहरण के लिए, जब वासना प्रबल होती है, तो व्यक्ति मर्यादाओं को लांघ जाता है और ऐसा कार्य करता है जो जीवन भर कलंकित करता है। लोभी व्यक्ति अधिक पाने के अलावा कुछ नहीं सोचता और बहुमूल्य मानव जीवन को बरबाद कर देता है। कामवासना का निषेध करने पर क्रोध अपना भयानक रूप धारण कर लेता है। (18.66) और घृणा, जब अनियंत्रित होती है, तो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। (16.19) इसलिए, हर समय बहुत सावधान रहना चाहिए। स्वभाव, जो हमारी सोच और निश्चित रूप से हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। खुद को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है?

सबसे पहली बात यह है कि हर समय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। क्या मेरी गहरी इच्छाएं दोषपूर्ण हैं? क्या मैं सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन कर रहा हूं? क्या मैं धर्म का उल्लंघन कर रहा हूं? क्या मैं कर्तव्यों से बच रहा हूं? हम पाएंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं। फिर, क्या किया जाना चाहिए? क्या मैं खुद को नियंत्रित कर सकता हूं? शायद, थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं।

क्या मैं फंस गया हूं? हां और नहीं। हाँ, क्योंकि स्वभाव में भारी बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि स्वभाव हमारे भाग्य का हिस्सा है, जैसे कि नौकरी छूटने जैसी बड़ी घटनाएँ आएंगी और हम उन्हें आने से नहीं रोक सकते। नहीं, चूंकि भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने दोनों मामलों में एक रास्ता छोड़ दिया है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाता है, तो ईश्वर व्यक्ति को सभी परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करते हैं (18.58) जहां तक स्वभाव की बात है, यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है तो ईश्वर उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यह कठिन और धीमी प्रक्रिया है, लेकिन संभव है। निष्कर्ष क्या है? हमारे स्वभाव में समस्या है। चाहे वह वासना हो या क्रोध या लालच या घृणा या अतिशय अहंकार, हम वास्तव में फंस गए हैं।

इसलिए, ईश्वर की शरण में जल्दी से जाओ, यानी अभी से उन्हें प्रसन्न करना शुरू कर दो। ईश्वर को विश्वास दिलाओ कि तुम दृढ़ निश्चयी हो; वह निश्चित रूप से मदद करेगा। और जब हम ऐसा करेंगे, तो हमारे आस-पास के लोग भी हमसे कुछ प्रेरणा लेना शुरू कर देंगे, बजाय एक-दूसरे को सुधारने की कोशिश करने के, जो कि असंभव है।

आप की बात

मणिपुर में अशांति

मणिपुर जल रहा है। बार-बार भड़की अशांति के परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है, बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है और पहले से ही अस्थिर राज्य में तनाव बढ़ गया है। लंबे समय से चल रहे विवादों ने तनाव को बढ़ा दिया है। मई 2023 में मैतेई की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की स्थिति की मांग और कुकी बस्तियों को निशाना बनाकर बेदखली अभियान से भड़की हिंसा मौजूदा संकट की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनाती है। मणिपुर की स्थिति एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती है। सरकार को सामुदायिक संवाद और सशस्त्र समूहों के साथ युद्धविराम समझौतों सहित विश्वास-निर्माण उपाय शुरू करने चाहिए। इसके अलावा, सार्थक बातचीत और संघर्ष समाधान के लिए मैतेई और आदिवासी समुदायों के बीच बातचीत के लिए तटस्थ मंच बनाए जाने चाहिए। राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए विश्वास को फिर से बनाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि स्वामित्व और सामाजिक-आर्थिक समानता के मुद्दों को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए अन्यथा इसका उत्तर पूर्व के पूरे क्षेत्र की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को छह और पुलिस स्टेशनों तक बढ़ा दिया है।

– **सुजीत विश्वकर्मा**, दिल्ली

कांग्रेस का पाखंड

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस को पूंजीवाद के खिलाफ एक योद्धा के रूप में पेश करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके दूर की कोड़ी दिखाई देती है। यह पाखंड के अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अडानी साम्राज्य के विकास और विस्तारीकरण में सामने आकर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण हमें कांग्रेस शासित प्रदेशों में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। अडानी पर कांग्रेस के हमले सिर्फ उसके दोहरे चरित्र को उजागर करने, कमजोर योजनाएं और नाकाम रणनीति को छिपाने का काम करते हैं। साल 1988 में अस्तित्व में आया अडानी समूह के विकास का तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अंदाजा लगाना हो तो आसानी से 1990 के दशक में लगाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस उस समय सत्ताधारी दल था। साल 1993 में, गुजरात में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार का नेतृत्व चिमनभाई पटेल कर रहे थे, इसी सरकार के दौरान अडानी को उनके मुंद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर पर जमीन दी गई थी। इसके अलावा आगे भूमि आवंटन शंकर सिंह वाघेला द्वारा किया गया था, वाघेला को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था।

– **स्वतंत्र मिश्रा**, कानपुर

बांग्लादेश की दशा

वर्तमान दौर में बांग्लादेश की भयावह स्थिति से उबरने के लिए कनून व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। हिंदुओं पर अत्याचार , आगजनी, मारना, सताना , मंदिरों में दर्शन हेतु बाधा उत्पन्न करना। पुजारी पंडितो को डराना धमकाना विचारणीय और चिंतनीय है। आखिर बांग्ला देश की सरकार क्या सिद्ध करना चाहती हैं। खून खराबे और नफरत भरे माहौल में हिंदुओं का भय और पीड़ा जाने वाला कोई नजर नहीं आता। क्या यह उचित है। बांग्ला देश में हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा देखकर अमानवीय व्यवहार और क्रूरता का परिचय मिलता है। बांग्लादेश की सरकार को होश हवास में आना होगा और हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा की घटनाओं पर पूर्णत रोक लगाना होगी। किसी देश के विकास में यह घटनाएं विकास को बाधित ही कर सकती है। सरकार मुखिया के समान होती है और इस तरह का भेदभाव विचारणीय और चिंतनीय लगता है। आखिर वे गुनाह लोगों को कब तक इस हिंसा उपद्रव की आग में जलना होगा ? हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री जी मोदीजी को बांग्ला देश की गंभीर परिस्थिति को संज्ञान में लेकर हुंकार भरनी होगी। बांग्ला देश सरकार को दो टूक समझाना होगा। मोदीजी है तो मुमकिन है। निश्चित ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बांग्ला देश में हिंदुओं के बचाव के लिए कारगर रणनीति तैयार करेंगे। जल्द हि इस गंभीर परिस्थिति से मुक्ति दिलाएंगे।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह, मप्र

तकनीक पर निर्भरता

आज के युग में तकनीक का सहारा सुविधा के लिए होता है लेकिन आज कल हो रही घटनाएं सुविधा की बजाय जानलेवा साबित हो रही है। यह चिंताजनक है और तकनीक की निहित सीमाओं को दर्शाता है। इन दिनों गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करना अत्यधिक घातक हो गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले अधूरे पुल से कार गिरने पर तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की स्याही अभी सूखी भी नही थी कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बार फिर गूगल मैप के कारण हादसा हो गया। बरेली के इज्जत नगर थाना इलाके के पीलीभीत रोड स्थित एक कार गूगल मैप के कारण कलापुर नहर में गिर गई। कार में तीन लोग सवार थे। गनीमत रही कि समय रहते मदद मिलते सवारों की जान बच गई।ऐसी घटनाओं के मद्देनजर सतर्कता बहुत ही जरूरी है। जहां तक संभव हो यात्रा के दौरान गूगल के अलावा अन्य विकल्प भी साथ ही साथ उपयोग में लिए जाते रहना चाहिए। इससे जोखिम तो घटेंगे ही जान-माल का खतरा भी नहीं रहेगा।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.bindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 6 दिसंबर 2024

ख़तरा है वास्तविक

शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर बुधवार को जिस तरह से अमृतसर के स्वर्णमंदिर में जानलेवा हमला हुआ, वह बताता है कि खालिस्तानी अलगाववाद के दोबारा सिर उठाने का खतरा कितना वास्तविक है। गनीमत रही कि पंजाब पुलिस के ASI जसबीर सिंह की सतर्कता और तत्परता की बदौलत बादल बाल-बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने अलगाववादी ताकतों से जुड़े खतरनाक पहलुओं को बेनकाब कर दिया है।

सेवा के दौरान हमला | बादल पर हमला तब हुआ, जब वह अकाल तख्त के आदेश के मुताबिक स्वर्ण मंदिर के द्वार पर सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे। धर्म की आड़ लेकर पल रही उग्रवादी सोच कैसे करोड़ों लोगों की आस्था और उनकी धार्मिक भावनाओं की धज्जियां उड़ा देती है, वह इस घटना से एक बार फिर स्पष्ट हो गया।

उग्रवाद के सिर उठाने का डर

उग्रवाद का इतिहास | इस मामले में पकड़ा गया आरोपी 'लोन वुल्फ' की भूमिका में था या उग्रवादी-अलगाववादी संगठनों की सुनियोजित साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया गया, यह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमलावर आरोपी अतीत में अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त रहा है। वह न केवल खुद पाकिस्तान जा चुका है और कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका है बल्कि हाल के वर्षों में भी उसके खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल रहने की सूचना है।

निशाने पर युवा | यह बात सही है कि नब्बे के दशक के मध्य तक आते-आते पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद पर काफी हद तक काबू कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद पैदा हुई पीढ़ी के मन में उस दौर की कोई स्मृति न होने की वजह से उसे इस बात का अहसास नहीं है कि उस दौरान लोगों को उग्रवादियों के कारण किस-किस तरह की परेशानी हुई और किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसी बात का फायदा उठाते हुए बाद के दौर में खालिस्तान समर्थक तत्वों ने सोशल मीडिया के सहारे इन युवाओं को टारगेट करना शुरू किया।

झूठ, फंड, हथियार | ऑनलाइन चलाए जा रहे दुष्प्रचार में बड़े पैमाने पर झूठ का सहारा ली लिया ही जा रहा है, भारत विरोधी तत्वों की सहायता से फंड और हथियारों की सतत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी का परिणाम है कि जहां एक तरफ, छोटे ही सही पर सिख डायस्पोरा के एक हिस्से में खालिस्तान समर्थक भावनाएं सिर उठाती दिख रही है, वहीं देश के अंदर भी अमृतपाल सिंह जैसे कट्टर और उग्र नेताओं का उभार देखा जा रहा है। जाहिर है, इस खतरे को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

रोज़-ब-रोज़

कहां चला जाए

शैलेंद्र पांडेय

देश-विदेश से आने वालों को काशी की गलियां बहुत सुहाती हैं। कुछ तो इतनी संकरी हैं कि दोनों तरफ खड़े बहुमंजिला मकानों के छज्जे एक-दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। इतनी तंग जगहों पर भी जीवन जिस रफ्तार से चलता है, उसे देखकर कई पर्यटक हैरत से भर उठते हैं। हालांकि बनारस की कई सड़कें भी आपको इसी अंदाज की मिल जाएंगी, जहां पैदल और गाड़ी सवार- सब गड्डमड्ड हैं। सब एक रफ्तार से बढ़ रहे हैं और एक-दूसरे को धकियाते हुए बढ़ रहे हैं। पिछली सरकारों में, एक नगर विकास मंत्री जब दौरे पर आए, तो उनसे यह सवाल पूछे बिना नहीं रह गया कि यह कैसा अनोखा शहर है, जहां सड़क किनारे पटरियां ही नहीं हैं?

इस सवाल को आप देश के किसी भी शहर पर चस्पां कर सकते हैं। अंतर बस इतना हो सकता है कि कहीं पर आधी-अधूरी पटरियां मिल जाएंगी, लेकिन वह चलने लायक नहीं होंगी। ऐसे में जब देश में सड़क हादसे से जुड़े आंकड़े सामने आते हैं, तो उसमें पैदल चलने वालों का डेटा देख कोई अचरज नहीं होता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल का जो हाल बताया, उसके हिसाब से देश में 4.80 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए और इनमें 1.72 लाख लोगों की जान गई। इनमें 35 हजार पैदल चलने वाले थे।

पिछले 10 साल में देश में करीब 95 हजार किमी नया नैशनल हाइवे (NH) तैयार हुआ है। 2023-24 में हर दिन लगभग 34 किमी NH बनाया गया। यही गति हाई-स्पीड कॉरिडोर में भी दिख रही है और सड़कों के चौड़ीकरण में भी। लेकिन, इसके साथ ही साल दर साल हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि सड़कें पहले के मुकाबले आज पैदल चलने वालों के लिए अधिक असुरक्षित हो चुकी हैं। जब चलने वालों के लिए जगह पहले से ज्यादा है, तो चलने की जगह क्यों नहीं मिल पा रही? दरअसल, जगह तो है, लेकिन पैदल या साइकल सवारों के लिए नहीं। पुरानी बसावट को छोड़ दीजिए, नए बसे शहरों की सड़कों पर भी पैदल वालों का ख्याल नहीं रखा जाता। पटरियां और फुटपाथ होते भी हैं, तो उन पर दुकानदारी चल रही होती है। सरकार सड़कों को जितना चौड़ा कर रही है, हम लोग किस्म-किस्म के उपाय लगाकर उसे उतना ही संकरा कर देते हैं। अब जब एक ही लेन में पैदल और गाड़ी वाले साथ-साथ दौड़ेंगे तो हादसा कैसे नहीं होगा?

यातायात नियमों के प्रति हम जितना असम्मान दिखाते हैं, वह भी परिणाम में हादसे लेकर आता है। हेलमेट नहीं पहनने के कारण 54 हजार लोगों का घर जाना कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और यह भी कोई छोटी बात नहीं कि हादसों में जान गंवाने वालों में 10 हजार तो नाबालिग ही हैं।

एकदा

कोई कम नहीं

साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। इनमें पढ़े-लिखे, डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, तो अनपढ़, किसान, मजदूर भी होते। एक दिन एक धनाढ्य व्यक्ति पहले से गांधीजी से मिलने के लिए उनके कक्ष में थे। वहीं, एक डॉक्टर बाहर इंतजार कर रहे थे। धनिक व्यक्ति की बातों का कोई अंत नहीं था। वह गांधीजी से अनेक विषयों पर बात करते रहे। शायद वह सोच रहे थे कि जितनी अधिक गांधीजी से बात होगी, उतना ही उनका कद बड़ा होता जाएगा। उन्होंने गांधीजी के कीमती समय पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया। देखते-देखते एक घंटा बीत गया और बाहर दूसरे मिलने वालों की भीड़ बढ़ती गई। अब डॉक्टर साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें गांधीजी से कोई जरूरी काम था। वह इससे क्रोधित भी हो रहे थे। एक घंटे बाद जब वह धनिक व्यक्ति चले गए तो डॉक्टर अंदर आने में जान आई। उन्होंने लंबी सांस ली और कक्ष में प्रवेश कर गए। परेशान तो थे ही। कुछ कठोर होकर बोले, 'बापूजी, क्या आप उस व्यक्ति को कुछ समझा पाए?' डॉक्टर की बेचैनी को गांधीजी समझ गए और बड़े ही नम्र होकर मानो क्षमा मांगते हुए बोले, 'भाई, मैं लोभी ठहरा। जिस तरह तुम सब लोगों की खुशामद करता हूं, वैसे ही उनकी खुशामद भी कर रहा था। शायद किसी दिन देश के काम आ जाएं। यही कारण है कि उनकी लंबी बातचीत को बीच में रोक नहीं पाया।' गांधीजी की विनम्रता को देखकर डॉक्टर साहब शर्मिंदा हो गए। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति महत्त्वपूर्ण था।

Subrata Char

संकलन : ललित गर्ग

भारत की बढ़ती साख और भारतीय क्रिकेट के दबदबे का असर ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर दिखता है

क्या कालजयी बन पाएगी टीम इंडिया

विमल कुमार, एडिलेड ओवल से

आज से एडिलेड ओवल में बॉर्डर-गावसकर सीरीज का दूसरा मैच शुरू हो गया। भारत 5 मैचों की इस सीरीज में अभी 1-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट की हस्ती दुनिया और खासकर खेल के मैदान पर सबसे बड़ी चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया में किस कदर बदल गई है, उसकी झलक देखने के लिए एक बार यहां आना चाहिए। साल 2008 में टीवी रिपोर्टर के तौर पर जब मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर कदम रखा, तो हरभजन सिंह बनाम एंड्रयू साइमंड्स का मंकीगेट कांड सुर्खियों में था।

सचिन से नाराजगी | ऑस्ट्रेलिया ने डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर किसी को सबसे बेहतरीन क्रिकेटर माना, तो वह सचिन तेंडुलकर है। लेकिन, मंकीगेट का ऐसा असर हुआ कि सचिन तेंडुलकर के हरभजन का साथ देने से ऑस्ट्रेलियाई नाराज और मायूस हो गए। कुछ साल बाद एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि किस तरह उस वाकये से सचिन की साख को थोड़ा झटका लगा था।

IPL का असर | बहरहाल, सचिन की विरासत को आगे ले जाने वाले विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के साथ न सिर्फ अपने निजी रिश्ते, बल्कि भारतीय क्रिकेट के समीकरण भी पूरी तरह बदल डाले। यह सच है कि ऐसा अकेले सिर्फ विराट की असाधारण शख्सियत के चलते नहीं हुआ। 2008 में IPL ने बंगारूओं को एक उभरते हुए ताकतवर देश की झलक दिखलाई, तो भारत से आने वाले इंजिनियर और डॉक्टरों ने वहां के जनमानस पर वही असर डालना शुरू किया, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इंग्लैंड में 50 साल पहले ही हो चुकी थी।

विराट का दबदबा | विराट कोहली ने 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा किया था। तब से 2024 तक, वह यहां के पांच टूर कर चुके हैं और हर बार शतक जमाया है। इसमें अपवाद के तौर पर केवल पिछला दौरा रहा, जब वह सिर्फ एक टेस्ट खेलकर भारत लौट गए थे। विराट ने अपने प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियाई जनता ही नहीं, उनके प्रधानमंत्रियों को भी अपना मुरीद बनाया है।

कैसे बदले समीकरण

- सचिन से विरासत विराट तक पहुंची
- IPL ने भारतीय ताकत दिखाई
- इंडियन डायस्पोरा प्रभाव डाल रहा

भारतीय संस्कृति | कैनबरा में टीम इंडिया के अभ्यास मैच के दौरान मेरी मुलाकात एक युवा महिला मैरी से हुई। मैरी क्रिकेट की दीवानी हैं, साथ में हिंदी फिल्में भी चाव से देखती हैं। अमिताभ बच्चन उनके पसंदीदा नायक हैं और शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो न हो' का टाइटल गाना भी वह गुनगुना सकती हैं। क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह की छाप भारतीय संस्कृति ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर छोड़ी है, वह अपने आप में अविश्वसनीय है।

हर जगह तिरंगा | एडिलेड टेस्ट से ठीक पहले टीम इंडिया के पहले अभ्यास सत्र को आम जनता के लिए प्रो कर दिया गया था। कोहली और रोहित की सिर्फ एक झलक पाने के लिए करीब 5000 दर्शक पूरे एडिलेड ओवल में भारतीय तिरंगा लहराते हुए दिखे। ऑस्ट्रेलियाई मैदानों में यह सुखद बदलाव है। ज्यादातर मैदानों पर भारतीय और स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों की संख्या 50-50% होती है।

बुमराह के प्रशंसक | पहली बार कंगारू किसी भारतीय गेंदबाज की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, जैसी जसप्रीत बुमराह को मिल रही है। जिस देश ने डेनिस लिली और ग्लेन मैक्ग्रा जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज दिए हों, वहां के युवा खिलाड़ियों के लिए बुमराह का रोल मॉडल बनना अद्भुत है। ऐसा सचिन की सर्वोच्चता के दौर में भी देखने को नहीं मिला था। शायद इसकी वजह यह थी कि उनके पास रिकी पोंटिंग थे, जो उनकी नजरों में अब भी सचिन से 19 नहीं हैं। बुमराह ने कप्तान के तौर पर भी हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है।

टर्निंग पॉइंट | इन तमाम बातों के बावजूद अगर पिछले 25 बरसों में सिर्फ एक घटना को नजरिये में बदलाव का टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, तो उसके पीछे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी हैं। 2008 में टीम इंडिया ट्राइएंगुलर वनडे सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में थी। वह श्रृंखला टेस्ट सीरीज की कड़वाहट के बाद खेली जा रही थी। इससे पहले भारत ने कभी ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में नहीं हराया था।

बड़ा मौका | उस दूर पर इतिहास बदल गया। धोनी की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की कड़वी दवा पिला दी। उन्होंने पहले ही हर साथी से कह दिया था कि ट्रोफी जीतने के बाद भी कोई जोरदार ढंग से जश्न नहीं मनाएगा। कंगारू देखकर हैरान रह गए कि कैसे इतनी बड़ी जीत को भारतीय टीम ने हल्के में लिया। यही काम विराट और अजिंक्य रहाणे ने पिछले दो दौरों पर किया है। अगर रोहित की अगुआई में टीम सीरीज जीत की हैट्रिक लगाती है, तो उसका वही रुतबा होगा जो वेस्टइंडीज की कालजयी टीम का हुआ करता था।

(लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं)

टुकड़े होता है जिगर लखनऊ के सदमे सुनकर

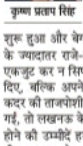

कृष्ण प्रताप सिंह

अंग्रेजों ने लखनऊ की रौनक तो खैर 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ व निर्वासित करके ही छीन ली थी, लेकिन उसके साल भर बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और बेगम हजरतमहल ने अवध के ज्यादातर राजे-रजवाड़ों को अपने साथ एकजुट कर न सिर्फ उन्हें दिन में तारे दिखा दिए, बल्कि अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कदर की ताजपोशी कराने में भी कामयाब हो गई, तो लखनऊ के फिर से जलवा अफरोज होने की उम्मीदें हरी हो गईं। लेकिन अगले ही बरस पासा ऐसा पलटा कि बेगम को वहां से भागकर हिमालय की तलहटी में शरण लेनी पड़ी और बदकिस्मती ने उन्हें एक बार फिर आ घेरा। फिर तो अंग्रेजों ने उन्हें बर्बरता और विनाश के ऐसे दिन दिखाए कि कद्रदानों के लिए यह एक हाय का नाम होकर रह गया। ऐसी कसक का, जो रह-रह कर उन्हें सताती व सालती रहती थी।

सालती भी क्यों नहीं, तब अंग्रेज सैनिकों ने लखनऊ और लखनवियों के मानमर्दन के लिए कत्लेगारत समेत कोई भी वहशत उठा नहीं रखी थी। खुल्लमखुल्ला लूट-पाट से कोहराम मचा रहे मामूली से मामूली अंग्रेज सिपाही भी हीरे-पन्ने, फर्शी, झाड़-फानूस, इत्र की बोतलें, फैंसी ग्लास, शीशे, लैंपशेड और सोने-चांदी की कंदीलें वगैरह हथियाकर खासे मालदार बन गए थे।

विडंबना यह कि शहरियों के पलायन के बीच यह बदअमनी महीनों बाद भी नहीं थमी, सालों खिंच गई। इससे लखनऊ इतना बदशक्ल हो गया कि पहचाना ही नहीं जाता था। उसकी इस हालत पर रेजिडेंसी के इंचार्ज रहे मेजर आइंस को भी लिखना पड़ा था, 'लखनऊ सुंदर महलों का शहर था/ महल तबाह कर दिए गए/ लखनऊ बागों का शहर था/ बाग बर्बाद कर दिए गए/ लखनऊ मेलों का शहर था/ मेले वीरान कर दिए गए। इसी तरह लखनऊ को रहस और थियेटर का शहर भी नहीं ही रहने दिया गया।

फिर तो इसकी कसक ने कोलकाता (तब कलकत्ता) के मटियाबुर्ज में जैसे-तैसे जिंदगी काट रहे वाजिद अली शाह को भी नहीं छोड़ा। किसी दिन वह बहुत कचोटने लगी तो उन्होंने यह शे'र कहकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की : अब लुट गया है क्या रहा दोजख से बढ़के है, रश्क-ए-बहिश्त कहते थे सब जा-ए-लखनऊ।

अवधनामा

फिर भी कचोट से छुटकारा नहीं मिला तो उन्होंने कहा : हर चंद लाख तरह भुलाता हूं याद को, 'अख्तर' पुकार उठता है दिल हाये लखनऊ। 'अख्तर' उनका शायरी का नाम था। उनके दिल-ए-शायर की बेकली और बढ़ी तो उसने तड़पते हुए से प्रार्थना शुरू कर दी : आए न मेरे पास तो मैं आप ही चलूं, मुझको खुदा करे कहीं बुलाए लखनऊ। लेकिन न बेबस लखनऊ उन्हें कहीं बुला सका, न वह खुद लखनऊ जा सके और न यह कसक उनका साथ छोड़ सकी। लखनऊ के जिस दर व दीवार पर हसरत से नजर करते हुए वे 'हम तो सफर करते हैं' कहकर मटियाबुर्ज (कोलकाता) चले गए थे, उसे एक बार फिर देखने की उनकी हसरत, हसरत ही रह गई। ऐसा भी नहीं कि यह हसरत सिर्फ उनके ही दिल-ए-शायर की रही हो या उसका वास्ता लखनऊ से कम और उनका राजपाट छिन जाने से ज्यादा रहा हो।

लखनऊ की बरबादी अनेक ऐसे शायरों के दिलों को भी सालती रहती थी, जिनका राजपाट से कोई वास्ता न था। खासकर उनके दिलों को, जिनका उसकी बहार के खिजां में बदल जाने के बावजूद वहीं, उसी पतझड़ में गुजारा था। उनमें से एक, नज्म तबातबाई को गहरा मलाल था कि, लखनऊ जिनसे इबारत थी हुए वे नापदीद, है निशान-ए-लखनऊ बाकी न शान-लखनऊ। मर्सियागो कितने यकता-ए-जमाना थे यहां, कोई तो इतनों में होता नौहाख्वान-ए-लखनऊ।

हकीम आगाजान ऐश दिल्ली के थे, फिर भी जितने दिल्ली के लुट-पिट जाने को लेकर परेशान थे, उतने ही लखनऊ को लेकर भी: ही गए वीरान देहली औ दयार-ए-लखनऊ, अब कहां वो लुत्फ-ए-देहली औ बहार-ए-लखनऊ। टुकड़े होता है जिगर देहली के सदमे सुनके ऐश, और दिल फटता है सुनकर हाल-ए-जार-ए-लखनऊ।

जब क़द के चलते CM नहीं बने मुलायम

केसी त्यागी

उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव के बारे में यह एक दिलचस्प सियासी दास्तान है। 1977 में ऐसा भी वाकया हुआ था, जब मुलायम को अपने छोटे कद के कारण मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य माना गया।

इंदिरा की हार के बाद बदलाव

आपातकाल खत्म होने के बाद हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटें जनता पार्टी के खाते में चली गईं। इंदिरा खुद भी समाजवादी नेता राज नारायण के हाथों रायबरेली से पराजित हुईं। सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में सरकारों को भंग कर दिया कि वे जनता का विश्वास प्राप्त करने में असफल रही हैं। लोकसभा चुनाव में हार का विधानसभा से कोई मतलब नहीं। दोनों के लिए जनादेश हासिल करना अलग बात है। तब सत्ता पक्ष के इस कदम की संविधान विशेषज्ञों ने आलोचना की थी। मई 1977 में इन्हीं राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए और सभी जगह जनता पार्टी विजयी हुई। जनता पार्टी में लोक दल और जनसंघ अपने संख्याबल के कारण सबसे महत्त्वपूर्ण घटक थे। सभी राज्यों में दोनों दलों ने मिलकर सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की।

मुलायम ऐसे बने सदन में उप-नेता

सबसे पेचीदा मामला उत्तर प्रदेश का था। 1974 के चुनावों में लोकदल को 100 से अधिक सीटों पर सफलता मिली थी। लोकदल के साथ राज नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेता डॉ. फरीदी की पार्टी भी शामिल थी। चौधरी चरण सिंह नेता प्रतिपक्ष और रामसेवक यादव उप-नेता चुने गए। डॉ. राम मनोहर लोहिया के बाद रामसेवक यादव सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में शुमार थे। लेकिन एक हादसे में वह बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। लोक दल और समाजवादी लोगों के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। चौधरी चरण सिंह सामाजिक समीकरण बैठाने में निपुण थे। उन्होंने उप-नेता पद के लिए मुलायम सिंह यादव को चुना।

सीएम कैंडिडेट की तलाश

उत्तर प्रदेश विधानसभा में जनता पार्टी को तीन चौथाई बहुमत मिल चुका था। निर्वाचमान नेता प्रतिपक्ष चौधरी चरण सिंह देश के गृहमंत्री बन चुके थे और उनके उत्तराधिकारी की तलाश जारी थी। चौधरी चरण सिंह जनसंघ के नेता माधो प्रसाद त्रिपाठी की सादगी और संगठन क्षमता से काफी प्रभावित थे। मुख्यमंत्री के रूप में त्रिपाठी का भी उन्हें आया, लेकिन लोक दल समर्थक विधायकों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण उन्हें यह विचार त्यागना पड़ा। चौधरी चरण सिंह के करीबी लोगों में ठाकुर बालचीर का भी नाम चर्चा में रहा, लेकिन यह तय हो चला था कि मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से होगा। यादव जाति से होने की संभावना सबसे अधिक थी, लेकिन कोई नाम नहीं सूझ रहा था।

विशुद्ध राजनीति

दास्तान

जेल जाने की शर्त पर खरे उतरे

इसी बीच, कई नेताओं ने उप-नेता होने के कारण मुलायम सिंह यादव का नाम सुझाया। मुलायम सिंह बेशक चौधरी साहब के चहेते नेताओं में से थे और काफी लंबा समय आपातकाल में इटावा जेल में गुजार चुके थे। तब आपातकाल में जेल जाने वाली बात अनिवार्य शर्त की तरह थी। इसी तरह से हिमाचल में शांता कुमार, हरियाणा में चौधरी देवीलाल, राजस्थान में भैरोसिंह शेखावत, बिहार में कर्पूरी ठाकुर और मध्य प्रदेश में वीरेंद्र कुमार सकलेचा का चयन किया जा चुका था। चौधरी साहब ने मुलायम सिंह यादव को बुलावा भेजा। 37 साल के मुलायम कद-काठी में छोटे थे, हालांकि उनकी कर्मठता और विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं थी। चौधरी साहब को उनका कद बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के चयन के लिए कम लगा। आखिर में, आजमगढ़ से निर्वाचित सांसद रामनरेश यादव को इस पद के लिए चुना गया, जबकि इससे पहले उनका कोई संसदीय अनुभव नहीं था। वह कांग्रेस के कद्दावर नेता चंद्रजीत यादव को हराकर संसद तक पहुंचे थे।

चौधरी साहब ने मानी गलती

रामनरेश यादव के पास प्रशासनिक अनुभव न होने के कारण उन्हें बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ा और बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के सीएम बने। उत्तर प्रदेश में संगठन की बागडोर मुलायम सिंह को सौंपकर चौधरी साहब आश्वस्त थे। कई अवसरों पर चौधरी साहब ने स्वीकार किया कि मुलायम सिंह को सीएम न बनाकर उन्होंने गलती की। कद का पद से कोई रिश्ता नहीं है। नेपोलियन लगभग मुलायम सिंह के कद के बराबर थे और अपने शौर्य से सर्वाधिक लोकप्रिय योद्धा साबित हुए। चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद हुए दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ने मुलायम सिंह यादव को और मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर वह तीन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

(लेखक पूर्व सांसद और JDU के सीनियर नेता हैं)

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ ताकि पेच न फंसे

5 दिसंबर का संपादकीय 'गुड गवर्नेंस की चुनौती' पढ़ा। आमतौर पर पार्टी में आंतरिक अनुशासन और सहयोगी दलों में आपसी सामंजस्य को लेकर NDA बड़े-बड़े दावे करता आया है। लेकिन जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के बाद 12 दिनों तक बने रहे, वह किसी भी तरह ठीक बात नहीं। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि चुनावों के पहले दल भले ही आपस में कितना भी गठजोड़ कर लें, लेकिन जब कुर्सी का मामला सामने आता है तो पेच फंस ही जाता है। अच्छा यही है कि गठबंधन के जाते-रिश्ते और मर्यादाएं पहले से ही तय कर लिए जाएं।

अमृतलाल मारू, ईमेल से

■ पद की जिम्मेदारी

यह पत्र 4 दिसंबर के संपादकीय 'बुरे फंसे बाइडन' से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से अपने बेटे हंटर बाइडन को क्षमादान देना कई सवाल खड़े करता है। बाइडन ने पहले कहा था कि वह अपने बेटे के मामले में दखल नहीं देंगे। तब उन्हें बहुत वाहवाही भी मिली थी, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने पलटी मारकर अपने आलोचकों को मौका दे दिया है। उनका फैसला न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है, बल्कि यह भी इशारा करता है कि सिस्टम का बर्ताव कुछ खास लोगों के लिए कैसे बदल जाता है।

अंशु भारती, ईमेल से

■ बांग्लादेश को चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में आक्रोश है। जब हिंदू उत्पीड़न की बात हो, तो कुछ बुद्धिजीवी और सेक्युलर लोग मूक रहते हैं। मोदी सरकार को कागजी बयानबाजी के बजाय, बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए कि अगर हमले बंद नहीं हुए, तो भारत कड़ी कार्रवाई करेगा और सभी कूटनीतिक संबंध खत्म कर दिए जाएंगे। भारत को सॉफ्ट स्टेट बनने के बजाय मजबूत रुख अपनाना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाना भी जरूरी है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

दर्द कम करने वाली दवाएं ही बढ़ा रही मर्ज – एक खबर

– इलाज का तरीका गलत या दवाएं ही नकली।

पीयूष राणा

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

जीवन का दुख इसलिए कभी ख़त्म नहीं होता

स्वामी विवेकानंद

जीवन विरोधाभासों से भरा है। संसार की परस्तुएं जैसी दिखती हैं, वैसी हैं नहीं। हम जो चाहते हैं, वह मिलता नहीं। जो मिलता है, वह टिकता नहीं। जो टिकता है, उसका भोग हम नहीं कर पाते। जिसका भोग करते हैं, वह स्थायी संतोष नहीं देता। और यदि हम यह मानें भी कि संतोष स्थायी है, तो भी वह कष्ट पैदा करने वाला और नीरस होता है। प्रत्येक सुख के पीछे भी भय और चिंता का भाव बना रहता है और यह सभी पर लागू होता है। स्वस्थ को रोग का, धनी को चोर-लुटेरों का, सुंदर को गुप्तांगरक्षा का, संभ्रांत को अपमान का, विद्वान को प्रतिवादी का और गुणवान को निंदा का भय लगा रहता है।

मानव रोते हुए जन्म लेता है, शिकायतें करते हुए जीता है और असंतुष्ट अवस्था में मरता है। सामान्य तौर पर देखें तो जवान आदमी आशावादी होते हैं और भविष्य के सुनहले स्वप्न देखते रहते हैं। दूसरी ओर वृद्ध लोग लंबी आयु जीकर निराशावादी हो जाते हैं और वे अतीत के चिंतन में मग्न रहते हैं। जीवन की वेदनाएं उनके सुखों और आशाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होती हैं। अतीत का चिंतन तो हर हाल में दुखदायी होता है। अतीत अच्छा था, तो वर्तमान से तुलना कर दुखी होते हैं। और अतीत दुखमय था तो यह याद कर दुखी होते हैं कि मेरा जीवन तब कितना कष्टमय था।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए जीवन समस्याओं, विपत्तियों, संघर्षों, चिंताओं और निराशाओं की एक श्रृंखला ध्यान मात्र होता है। तो फिर जीवन में सांत्वना कहां खोजें? जीवन की समस्याओं का सामना न कर पाने के कारण कुछ लोग तो लोग हताश, और इसी कारण कई बार दुस्साहसी हो जाते हैं। कुछ मानते हैं कि जीवन की समस्याओं का कारण बाह्य जगत है और वे उन्हें भौतिक उपायों से दूर करने का प्रयास करते हैं, पर असफल ही रहते हैं। कुछ लोग एक ऐसे राष्ट्रराज्य के आगमन की व्यर्थ प्रतीक्षा करते रहते हैं, जहां दुख नहीं होंगे, केवल सुख ही सुख होगा। कुछ अन्य लोग जीवन की समस्याओं को समाधान रहित समझते हैं और मृत्यु उपरांत स्वर्ग में चिर सुख की बाट जोहते रहते हैं। दूसरे कुछ लोग समस्याओं को पूर्व नियोजित मानते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं। कहा जाता है कि विवाह के बारे में निर्णय कर पाने में असमर्थ एक युवक ने सुकरात से सलाह चाही। सुना है कि सुकरात ने उसे कहा था, 'सुनो भाई, यदि इच्छा हो तो विवाह कर लो। अगर तुम्हारी पत्नी अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा और यदि वह बुरी हुई तो तुम मेरी तरह एक दार्शनिक बन जाओगे।' जीवन की समस्याओं का निश्चित समाधान खोजने का प्रयत्न लौकिक या धार्मिक, सभी दर्शनशास्त्रों ने किया है।

जहां एक ओर दर्शन शास्त्र मानव जीवन की समस्याओं को केवल भौतिक या मानसिक दृष्टिकोण से देखता है और उनका समाधान देता है, वहीं परंपरागत धर्म इन्हें पारलौकिक (आध्यात्मिक) दृष्टिकोण से देखता है और इनका समाधान देता है। लेकिन जीवन को दो भागों में बांटना सही नहीं है। इसलिए जीवन की समस्याओं का समाधान सिर्फ दार्शनिक नहीं, बल्कि वास्तविक और व्यावहारिक तरीके से भी किया जाना चाहिए।

(साभार : 'मन की शक्तियां' पुस्तक से)

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 6 दिसंबर 2024 (नवभारत टाइम्स प्रकाशन लिमिटेड की ओर से दिल्ली प्रेस पब्लिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नोएडा (उ.प्र.) में मुद्रणालय नवभारत प्रेस, नई दिल्ली-110020 से प्रकाशित तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद (उ.प्र.) में मुद्रणालय नवभारत प्रेस, नोएडा-201301 से मुद्रित। प्रधान संपादक: राजेश मित्तल, संपादक: राजेश जयंत, कार्यकारी संपादक: मनोज कुमार सिंह, कार्यकारी संपादक (नवभारत टाइम्स): अनुराग पुनेठा। (फोन नंबर : 23420000) विज्ञापन: 23420001, मैनेजिंग एडिटर, नवभारत टाइम्स, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

चिंतन

वायु प्रदूषण से मुक्ति के लिए सख्ती आवश्यक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सख्ती में राहत ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन से मुक्ति भी जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट दिल्ली में ग्रैप-4 (जीआरएपी) पाबंदियों में ढील दे दी है, यह ढील मानवीय आधार पर दी है कि मजदूरों को काम मिलने में कठिनाई न हो। इसी के साथ अदालत ने हिदायत भी दी है कि अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो सख्ती बढ़ा दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पाबंदियां ग्रैप 2 से नीचे नहीं जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे और मॉनिटरिंग की जरूरत है। अभी हम कमीशन को ग्रैप 2 लागू करने की इजाजत देते हैं। बेहतर होगा कि कमीशन ग्रैप 3 की भी कुछ जरूरी पाबंदियों को लगाए रखें। हिदायत दी कि अगर कभी भी एक्यूआई 350 के पार जाता है तो तुरंत ग्रैप-3 की पाबंदियां लगाई जाएं। ऐसे ही 400 पार जाने पर ग्रैप-4 की पाबंदियां फिर से लगाई जाएंगी। दरअसल, कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने बताया कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम हुआ है। इसलिए अब हमें ग्रैप की पाबंदियां कम करने की जरूरत है। एक तरफ जहां दिल्ली में हवा दमघोंटू है, वहीं वहां जमकर राजनीति भी होती रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन ईमानदारी से किसी भी सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने की दिशा में पर्याप्त काम नहीं किया है। अदालत और नियामक एनजीटी की सख्ती के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा नहीं सुधरी है। सरकारी लापरवाही और हीलाहवाली के चलते जहरीली होती हवा से आम लोग पीड़ित हो रहे हैं, सांस के रोगों के मरीज बढ़ रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों को हर्जाने के मुद्दे पर चार राज्यों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता जाहिर की। प्रावधान किया गया था कि ग्रैप-4 पाबंदिया लागू रहने के दौरान करीब 90 हजार मजदूरों को हर्जाने के तौर पर आठ हजार रुपये प्रति मजदूर देने की बात कही गई थी, राज्यों ने केवल दो हजार रुपये ही दिए। कोर्ट ने राज्यों के लिए सख्त टिप्पणी की कि 'क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं?' सरकारों को मजदूरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और अदालत के निर्देश का समय से पालन करना चाहिए। दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण लोगों पर विपरीत असर डाल रहा है। लोग शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं। दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण के स्तर का बढ़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन समय रहते सरकारें पर्याप्त कदम नहीं उठाती हैं, सर्वोच्च न्यायालय व एनजीटी की सख्ती के बाद ही वे जागती हैं और हाथ-पैर मारती दिखती हैं। एक तरफ भारत पेरिस क्लाइमेट करार का हिस्सा है और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है, दूसरी तरफ वह अपनी राजधानी में भी वायु प्रदूषण कम नहीं कर पा रहा है। यहां प्रदूषण कम करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय करने होंगे। आबादी अनुपात संतुलन, हरितकरण, जहरीले गैस उत्सर्जन वाले उद्योगों को बाहर करने, इलेक्ट्रिकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने, हाइड्रोजन ईंधन चालित वाहन को प्रयोग में लाने, एसी के बजाय कूलर के प्रयोग को प्रोत्साहित करने, सौर बिजली को अधिक से अधिक अपनाने जैसे अनेक उपाय करने होंगे। दिल्ली सरकार, स्थानीय निकाय व प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर काम करें, राजनीतिक मतभेद के चलते जनता को तकलीफ में नहीं डालें। स्वच्छ और हरित राष्ट्रीय राजधानी लक्ष्य होना चाहिए।

दिवस विशेष
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

डॉ. आंबेडकर के भारत की खोज

भारत के लोगों के लिए जीवन देने वाले डॉ. आंबेडकर का एकांत उन्हें पुस्तक, कलम और चिंतन के साथ जोड़े रखा, इसका प्रमाण तो 'बुद्ध एंड हिज धम्म' की प्रस्तावना को बार-बार परिवर्तन करने की उनकी कोशिश से समझा जा सकता है। 06 दिसंबर उनके जीवन के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। वे जिस लोकतांत्रिक गणराज्य की खोज कर रहे थे वह अद्भुत था। उनका मानना था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र वह जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है।

डॉ. आंबेडकर ने जीवन की आखिरी रात भी देश की चिंता करते हुए खत्म की थी? इसका अर्थ है अपने जीवन के उत्तरार्ध को उन्होंने बुद्ध धर्म में बिताया। पुस्तक, कलम और दिमाग की दोस्ती डॉ. आंबेडकर की अपनी रुचि के विषय थे। सशरीर जीवन भर अपने त्याग, परिश्रम, सृजन के लिए डॉ. आंबेडकर जाने जाते हैं। कर्तव्यपरायणता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की धुन कैसी हो, इसे उनसे कोई सीखे। आमजन के डॉ. आंबेडकर, आमजन की चिंता में मग्न डॉ. आंबेडकर की दृष्टि लौकिक जगत के लिए इसीलिए आज आदर के साथ स्मरण की जाती है क्योंकि उन्होंने सदा ऐसे तबके की आवाज़ बनने की कोशिश की जिनका सहारा कदाचित कोई था। अंतिम दिनों में उनके कुछ विशेष जीवन से जुड़े लोग जिसमें शारदा कबीर, सुदामा, नानकचंद रत्तू, डॉ. माधव मालवनकर, चांगदेव भवानराव खैरमोडे जैसे नाम सम्मिलित हैं, वही जानते हैं कि डॉ. आंबेडकर का अंतिम क्षण कैसा था।

शारदा कबीर उनकी धर्म पत्नी थीं। सुदामा, उनके आवास पर सभी काम देखने वाले थे। नानकचंद रत्तू उनके निजी सचिव थे, डॉ. माधव उनके विशेष चिकित्सक और चांगदेव खैरमोडे उनके मित्र जिन्होंने 12 खण्डों में 'डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर' उन पर पुस्तक तैयार की थी। अंतिम दिनों के साक्षी वही हैं। डॉ. आंबेडकर अपने अंतिम दिनों में एकांत में रहना पसंद करते थे। उनके पास कम लोग ही आया करते थे। 'बुद्ध एंड हिज धम्म' पुस्तक की प्रस्तावना के लिए उनकी मुलाकातें हुईं तो उसके लिए या फिर कभी-कभार डॉ. आंबेडकर के इच्छानुसार कोई ख़ास व्यक्ति। जीवनभर भारत के लोगों के लिए जीवन देने वाले डॉ. आंबेडकर का एकांत उन्हें पुस्तक, कलम और चिंतन के साथ जोड़े रखा, इसका प्रमाण तो 'बुद्ध एंड हिज धम्म' की प्रस्तावना को बार-बार परिवर्तन करने की उनकी कोशिश से समझा जा सकता है। 06 दिसंबर उनके जीवन के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है जबकि शारदा कबीर यानी माईसाहेब ने अपनी पुस्तक 'डॉ. आंबेडकरांच्या सहवासात' में यह जिक्र किया है कि जब वह सुबह उनके कमरे में गईं तो वे इस जगत में नहीं थे क्योंकि उसके बाद जितनी भी कोशिशें की गईं, वे सब निरर्थक साबित हुईं। कहते हैं लंबी बीमारी के कारण 1955 में डॉ. आंबेडकर का स्वास्थ्य खराब हो गया था। 6 दिसंबर, 1956 को दिल्ली में नींद में ही उनका निधन हो गया। डॉ. आंबेडकर जिस लोकतांत्रिक गणराज्य की खोज कर रहे थे वह अद्भुत था। उनका मानना था कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो. सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का एक तरीका जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है. वे अपने इस दृष्टि को संविधान आत्मार्पित होने के एक दिन पूर्व स्पष्ट कर रहे थे। वह चाहते थे कि यह संविधान का दस्तावेज़ लागू हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी सामाजिक अभिव्यंजना जो आज है, वही बनी रहेगी तो इस संविधान का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तीन शब्द दिए- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। डॉ. आंबेडकर के भारत की खोज इन तीन शब्दों में

अभिव्यंजित होती है जिसमें वह निःसंदेह छुआछूत से मुक्ति, सबके लिए सामान अवसर और गरिमा की उपस्थिति चाहते थे। उन्हें समाज में व्याप्त बुराइयों से ज्यादा चिह्न रूढ़िवादी व्यवस्था के बने रहने से थी क्योंकि उनको यह विश्वास था कि बुराइयों की जड़ें तो इन व्यवस्थाओं में है। इसीलिए वह सतत अपने जीवन के उत्तरार्ध तक दलितों, वंचितों, शोषितों और महिलाओं के उत्थान हेतु शिक्षा को सबके जीवन का हिस्सा बनाना चाहा। वह महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर ही हिन्दू कोड बिल पर सदैव अड़े रहे और उसके लिए संघर्षरत रहकर आवाज बुलंद करते रहे। उन्हें किसी भी प्रकार की छद्म राजनीति पसंद नहीं थी। अंतिम दिनों में जब देश में छद्म राजनीति अपना ज्यादा पांव पसारने लगी तो वह इससे त्रस्त हो गए और मंत्रालय तक को त्याग दिए। वह उनका त्याग और उनकी कोशिश आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वास्तविक डॉ. आंबेडकर का हमें दर्शन कराती है। उनके अंतिम दिनों को स्मरण करें तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके बुद्धिष्ट भारत की खोज के बारे में लोग बात करने से कतराते हैं। संविधान लागू होने के बाद जिस सामाजिकी का भारत वह ढूंढ़ रहे थे, ऐसा लगता है कि वह चाहते थे कि भारत के दलित, दमित, वंचित, शोषित लोग बुद्धिष्ट भारत की मांग करें। यदि मांग न करें तो वे सभी जो उनको मानते हैं, कम से कम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और वैसा जीवन जीएं। इसके पीछे उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा संभवतः थी। यद्यपि भारत अब जिस संविधान से आज 21वीं सदी के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर रहा है तो आज ऐसे कई सवाल ऐसे दस्तक दे रहे हैं कि डॉ. आंबेडकर अपने भारत की खोज में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। नई-नई चुनौतियों के बीच डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय की संवेदनशील अवधारणा अभी भी भारत के दलितों, गरीबों और भूखे लोगों के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। समानता की लड़ाई अभी भी कहीं न कहीं अधूरी रह गई है। आज भारत में दलितों व वंचितों के साथ छुआछूत के मामले में कमी आई है। भेदभाव कम हुआ है। लेकिन गरीबी और भुखमरी में कमी आई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है कि डॉ. आंबेडकर अंतिम-जन के लोगों के सुखमय जीवन वाले भारत की खोज में आज भी हैं। उनका भारत अभी भी सहेजा नहीं जा सका है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। सच्चा सामाजिक न्याय तो तभी आएगा जब सभी वर्ग के लोग, सभी लिंग, समुदाय के लोग समान गरिमा के अधिकारी बनेंगे। आज भारत में दलितों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हुई है। आंबेडकर मजदूरों, श्रमिक वर्ग के रोजगार को महत्व देते थे, आज का आधुनिक राष्ट्र बेरोजगारी से मुक्ति के लिए श्रम के अवसर व आर्थिक उन्नति के आधार तैयार को लेकर कठिन दौर से गुजर रहा है। सत्ता में भागीदारी और नीति निर्माण करने का अवसर भारत ने उपलब्ध यदि दलित समाज को उपलब्ध कराया तो ऐसे कई राजनीतिक नेताओं के उदाहरण हैं आज हमारे सामने कि वे अपने आप को कायम नहीं रख सके। डॉ. आंबेडकर चाहते थे नैतिक ईमानदार और प्रतिबद्ध समाज जो दलितों के हितों को निरंतर उठाये और ऐसे भारत की रचना करे जो सबकी गरिमा व विश्वास का हो। आज डॉ. आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। उन्हें स्मरण करें। लेकिन यदि आज सभी लोग उनके मन, वचन और कर्म को आत्मसात कर उनके सपनों का भारत निर्मित करें तो ही उस महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच यह है कि आज उनकी अपेक्षाएं किसी खास वर्ग, जाति, लिंग व समुदाय से नहीं है, उनकी अपेक्षाएं भारत के सभी नागरिकों से है, यह हमें तय करना है कि उस दिव्य पुरुष के भारत को कैसे निर्मित होते हम देखना चाहते हैं।

(लेखक डॉ. आंबेडकर चेयर में प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विमर्श

डॉ.सौरभ मालवीय

आंबेडकर, समरसता और संघ

देश में सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रमुखता से स्वर मुखर करने वालों में डॉ. भीमराव आम्बेडकर का नाम अग्रणीय है। उन्होंने बाल्यकाल से ही अस्पृश्यता का सामना किया था। विद्यालय से लेकर नौकरी तक उन्होंने भेदभाव का दंश झेला। इससे उनकी आत्मा चीत्कार उठी। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने देशभर की यात्रा की तथा दलितों के अधिकारों के लिए स्वर मुखर किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अस्पृश्यता के उन्मूलन के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि सेवक बनकर ही कोई बड़ा कार्य किया जा सकता है। इसलिए वह कहते थे- 'एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है।' डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समरसता का जो स्वप्न देखा था, उसे साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान चला रहा है। वास्तव में संघ अपने स्थापना काल से ही सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार ने सामाजिक समरसता, एकता, अखंडता एवं सशक्त समाज के निर्माण के उद्देश से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। उनका कहना था कि हमारा निश्चय एवं स्पष्ट ध्येय ही हमारी प्रगति का मूल कारण है। हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि जिस कार्य को करने का हमने प्रण किया है, और जो उद्देश्य हमारे सामने है, उसे प्राप्त करने के लिए हम कितना कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक अधिकारी एवं शिक्षक को प्रत्येक के मन में यह विचार भर देना चाहिए कि मैं स्वयं ही संघ हूं। अपने चरित्र को कभी भी कमजोर व क्षीण न होने दें। आप इस भ्रम में न रहें कि लोग हमारी ओर नहीं देखते। वे हमारे कार्य तथा हमारे व्यक्तिगत आचरण की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। हमें केवल अपने कार्य में व्यक्तिगत चाल-चलन की दृष्टि से सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, अपितु सामूहिक एवं सार्वजनिक जीवन में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। वह कहते थे कि बिना कष्ट उठाए और बिना स्वार्थ त्याग किए, हमें कुछ भी फल मिलना असंभव है। अपने समाज में संगठन निर्माण कर उसे बलवान तथा अजेय बनाने के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं करना है। इतना कर देने पर सारा कार्य स्वयं ही हो जाएगा। अनुशासन अपने संगठन की नींव है, इसी पर हमें विशाल इमारत को खड़ा करना है। सामाजिक समरसता के बारे में उनका कहना था कि संघ का लक्ष्य भारत राष्ट्र को पुनः परम वैभव तक ले जाना है। समरसता के बिना, समता स्थायी नहीं हो सकती और दोनों के अभाव में राष्ट्रीयता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा कार्य अखिल हिंदू समाज के लिए होने के कारण, उसके किसी भी अंग की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। वह कहते थे कि संघ का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें लोक संग्रह के तत्वों को भली-भांति समझ लेना होगा। संघ केवल स्वयंसेवकों के लिए नहीं, अपितु संघ के बाहर जो लोग हैं, उनके लिए भी है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि उन लोगों को हम राष्ट्र के उद्धार का सच्चा मार्ग बताएं। प्रत्येक व्यक्ति को उत्साह और हिम्मत से आगे आना चाहिए और संघ कार्यों में जुट जाना चाहिए। इस समाज को जागृत एवं संगठित करना ही राष्ट्र का जागरण एवं संगठन है। यही राष्ट्र धर्म है।

ध्येय पर अविचल दृष्टि रखकर, मार्ग में मखमली बिछौने हो या कांटे बिखरे हों, उनकी चिंता न करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ने को दृढ़ निश्चय वाले क्रियाशील तरुण खड़े करने पड़ेंगे। पूर्ण संस्कार दिए बिना, देशभक्ति का स्थाई स्वरूप निर्माण होना संभव नहीं है तथा इस प्रकार की स्थिति का निर्माण होने तक सामाजिक व्यवहार में प्रमाणिकता भी संभव नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने सामाजिक समरसता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि समरसता के लिए आत्मग्लानि दूर करने के लिए आत्मबोध को जगाना पड़ेगा, स्वार्थ के स्थान पर निःस्वार्थ भाव का निर्माण करना पड़ेगा। सभी भेदों को भुलाकर एकात्मकता का भाव जागृत करना पड़ेगा। भीमराव आंबेडकर समानता पर सर्वाधिक बल देते थे। वह कहते थे कि अगर देश की अलग-अलग जातियां एक-दूसरे से अपनी लड़ाई समाप्त नहीं करेंगी, तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। एक सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष का होना ही काफी नहीं है अपितु इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है, वह सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिज्ञ से ज्यादा साहसी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं।

(लेखक राष्ट्रपतिय राष्ट्रदूत के अध्येता हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सजगता से दूर होती है चिंता

संकलित
दर्शन

जब तुम चिंता का अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढ़ते हो। उसके उपाय खोजते हो। लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता है। विचार के द्वारा चिंता का विसर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। यह विधि बहुत आसान है। यह कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो। सिर्फ सजग हो जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरे जेन गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन दिन में या कभी-कभी रात में भी वह जोरों से कहता थे, 'बोकोजू'। यह उनका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहते, 'हां महोदय, मैं मौजूद हूं।' जबकि वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उनके शिष्य उससे पूछते थे, 'क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद कहते हैं, हां, मैं उपस्थित हूं?' बोकोजू ने कहा, 'जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हां महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचारणा, चिंता विलीन हो जाती है।' फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी दो-तीन वर्षों में उन्होंने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और न ही यह कहा कि हां, मैं मौजूद हूं।

भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं

संकलित
प्रेरणा

एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा- भाई! मैं तो हूं संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूं, तुम जो हो रहे हो तो यह लो 100 रुपए मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से सौ रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल पड़ा। वह श्री जगन्नाथ पुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन, हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। भक्त भी वहीं रुक कर हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। उसने सोचा क्यों ना सेठ के सौ रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास दो रुपए बच गए उसने सोचा चलो अच्छा हुआ दो रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अंत में उसने सेठ के दो रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए और उस दो रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए।

अंतर्मन

आज की पाती

जागरूकता अभियान चलाया जाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों पर चिंता जताई। मोदी ने साइबर ठगी से बचने के जो उपाय बताए, उन पर लोगों को खुद भी जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भी करना चाहिए। देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जो लोगों के खून-पसीने की कमाई को मिट्टी में मिला रहे हैं। कुछ समय पहले प्रदेश में पैसा दोगुना करने के नाम पर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें एक कंपनी ने लोगों को पैसा डबल करने का झांसा दिया और उनके पैसे लेकर कंपनी रफूचक्कर हो गई। आरबीआई ने लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए हुए हैं, फिर भी न जाने वे क्यों झांसे में आ जाते हैं।

-सुरेश यादव, भाटापारा

ट्रेंड

भूटान से स्थायी साझेदारी

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक और रानी उस राजा से सम्मान करते हुए खुशी हो रही है। हम भूटान के साथ अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हॉकी टीम को हार्दिक बधाई

पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि उनकी उत्कृष्ट टीम वर्क, समर्पण और अद्वितीय धैर्य का प्रमाण है, जिससे इस ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया। यह जीत भारत का नाम बढ़ाती है।

-जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष

देश का उज्ज्वल भविष्य

कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य के नेता हैं। मैं कहता हूँ, नहीं! वे आज और कल के नेता हैं। अपने-आप को वे बाल शोषण, सामाजिक अन्याय, असहायता, भेदभाव और विभाजन से लड़ते हुए, वे देश के उज्ज्वल भविष्य को साकार करते हैं।

-कैलाश सत्यार्थी, बाल अधिकार कार्यकर्ता

अभी शुरुआत करें

बुढ़े फिट रहने के लिए अलग-अलग चीजें आजमाना पसंद है लेकिन पिलेट्स इनोवा मेरा पसंदीदा है। यदि आप में से कोई भी शुरुआत करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो अभी शुरुआत करें क्योंकि कभी भी देर नहीं होती है।

-प्रीति जिंटा, अभिनेत्री

करंट अफेयर

हसीना के 'घृणास्पद भाषणों' के प्रसार पर लगा प्रतिबंध

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के सभी ''घृणास्पद भाषणों'' के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह आदेश हसीना के हालिया भाषण के बाद आया है, जो चार महीने पहले बांग्लादेश से जाने के बाद उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। इसमें उन्होंने देश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस पर तीखा हमला करते हुए उन पर 'नरसंहार' करने और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। बांग्लादेश संवाद संस्था (बीएसएस) ने बताया कि न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार के नेतृत्व में दो सदस्यीय न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया और अधिकारियों को सोशल मीडिया से हसीना के सभी 'घृणास्पद भाषणों' को हटाने तथा भविष्य में सभी प्रकार के मीडिया में उनके प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अब्दुल्ला अल नोमान ने समाचार एजेंसी को बताया कि न्यायाधिकरण ने आईसीटी प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग (बीटीआरसी) के सचिवों से आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कहा है।

ऑफ बीट

रूक-रूक कर उपवास से बचा जा सकता है अल्जाइमर से

जैसे-जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, अल्जाइमर रोग तेजी से आम होता जा रहा है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे प्रचलित रूप है।

डिमेंशिया एक बीमारी है जिसका उपयोग उम्र के साथ मस्तिष्क की कार्यक्षमता में गिरावट से जुड़े लक्षणों की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लक्षणों में स्मृति हानि, संचार कठिनाइयाँ, समस्या-समाधान संघर्ष और व्यक्तित्व या व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। हाल के वर्षों में, अल्जाइमर रोग जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों पर शोध के सबसे आशाजनक क्षेत्रों में से एक मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन का संचय रहा है। विशेष रूप से अमाइलॉइड। अमाइलॉइड अल्जाइमर रोग में अनुसंधान का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है क्योंकि इसका बढ़ना इस स्थिति के विकास से जुड़ा है। रोग प्रक्रिया में इसकी भागीदारी को समझना हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने और रोग के निदान, रोकथाम और उपचार के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अमाइलॉइड के संचय से प्लाक का निर्माण हो सकता है। ये प्लाक मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार में बाधा डाल सकते हैं। यह अंततः संज्ञानात्मक गिरावट और अल्जाइमर रोग से जुड़े अन्य लक्षणों में योगदान देता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 250

अस्वाभाविक पहलू

विगत दो महीनों में शेयर बाजार में आई गिरावट के कुछ अस्वाभाविक पहलू भी हैं। यह गिरावट विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा लगातार की गई बिकवाली के कारण आई है जबकि इस अवधि में घरेलू संस्थान और खुदरा निवेशक लगातार तेजी के रुख पर रहे हैं। एक अन्य अस्वाभाविक बात यह है कि स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों ने लार्जकैप की तुलना में अधिक रक्षात्मक मजबूती दिखाई है। निफ्टी जहां सितंबर के उच्च स्तर से छह फीसदी नीचे है वहीं स्मॉलकैप सूचकांक 2.5 फीसदी ही लुढ़का है। स्मॉलकैप ने सितंबर तक तेजी में भी निफ्टी को आसानी से पीछे छोड़ दिया था। जनवरी से सितंबर के बीच निफ्टी ने जहां 26 फीसदी तेजी हासिल की वहीं स्मॉलकैप ने 38 फीसदी मजबूती पाई। तेजी के दौर में छोटी कंपनियों का आगे निकल जाना आम है। परंतु मंदी के दौर में रक्षात्मक मजबूती आसान नहीं है। यह कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के तरीके बदल रहे हैं।

एफपीआई की बिकवाली के कारण हो रही गिरावट भी एक वजह है जिसके चलते स्मॉलकैप का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा। एफपीआई की छोटे शेयरों में हिस्सेदारी नहीं है। उनका रुख देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों से प्रभावित होता है और वे दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजों से प्रभावित हुए होंगे। एफपीआई को अपने उभरते बाजार पोर्टफोलियो में चीन को भी नए सिरे से संतुलित करना होगा और वे अमेरिका में ट्रंप के आगामी प्रशासन के नीतिगत निर्णयों के बारे में भी कयास लगा रहे होंगे। बहरहाल, जहां लार्जकैप का प्रदर्शन दूसरी तिमाही में कमजोर रहा है वहीं स्मॉलकैप के शेयरों ने वृद्धि हासिल की है। इसके पीछे यह सिद्धांत भी है कि छोटी कंपनियों के लिए जल्दी वृद्धि हासिल करना आसान होता है। बहरहाल यह भी सही है कि देश के जिन क्षेत्रों ने बीते कुछ वर्षों में तेज वृद्धि हासिल की है उनका निफ्टी में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है या फिर कई मामलों में तो उनका जरा भी प्रतिनिधित्व नहीं है।

वृद्धि हासिल करने वाले बड़े क्षेत्रों में हरित ऊर्जा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कई प्रकार के विनिर्माण, अधोसंरचना क्षेत्र, उपभोक्ता तकनीक और खुदरा वित्तीय क्षेत्र एवं संपत्ति प्रबंधन जैसे नए सूचीबद्ध क्षेत्र शामिल हैं। तेज विकास की संभावना वाले अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं- इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण सेवाएं, ठेके पर औषधि निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को फिर इस्तेमाल करने लायक बनाना, स्मार्ट मीटर और डेटा सेंटर निर्माण। इन सभी क्षेत्रों में छोटी कंपनियों का दबदबा है। ये ऐसी कंपनियां हैं जो इतने लंबे समय से कारोबार में हैं कि वे अच्छा खासा मुनाफा और राजस्व कमा सकें। एक बार फिर परिभाषा के स्तर पर देखें तो इन क्षेत्रों में कम आधार से तेज वृद्धि संभव है।

चूंकि यह वृद्धि निफ्टी में नजर नहीं आ रही इसलिए बड़े संस्थागत कारोबारियों मसलन एफपीआई आदि के लिए उचित यही है कि वे इसके प्रति रूढ़िवादी या मंदी का रुख रखें। यकीनन चुनिंदा म्युचुअल फंड को छोड़ दें तो स्मॉलकैप में घरेलू संस्थागत निवेश भी काफी कम है। यह संभव है कि कुछ चतुर खुदरा निवेशक जिन्होंने पूरी जांच परख कर ली हो उन्होंने बड़े कारोबारियों की तुलना में अधिक पूंजीगत लाभ कमाया हो क्योंकि उन्होंने छोटे किंतु उच्च वृद्धि वाले कारोबारों में निवेश किया। कम आधार के कारण उच्च वृद्धि के पीछे जहां एक गणित है वहीं यह भी सही है कि मिडकैप और स्मॉलकैप क्षेत्र का मूल्यांकन हमेशा से बढ़ा है। निफ्टी मिडकैप 100 वित्त वर्ष 25 की अग्रिम आय के 32 गुना पर कारोबार कर रहा है जबकि 10 सालों का औसत मूल्य आय (पीई) अनुपात 17 है। निफ्टी स्मॉलकैप 100 का मूल्य आय अनुपात 24 जबकि उसका 10 साल का अग्रिम औसत 16-17 है। छोटी कंपनियां जहां तेजी से बढ़ सकती हैं वहीं अगर समग्र वृद्धि की बात करें तो उनके पास मंदी के दौर से निपटने के लिए संसाधन भी कम होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े और दूसरी तिमाही के कारोबारी नतीजे धीमेपन का संकेत दे रहे हैं। यकीनन स्मॉलकैप क्षेत्र में मूल्य और संभावित कई गुना मुनाफा देने वाले क्षेत्र भी हैं लेकिन निवेशकों को ऊंचे मूल्यांकन के कारण सतर्क रहने की भी जरूरत है।

बिनय सिन्हा

जलवायु परिवर्तन से सही ढंग से निपटना जरूरी

जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत के प्रयास उन उपायों से एकदम अलग हैं जो भारत के लोगों और खेतों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए उठाने की आवश्यकता है। बता रहे हैं लवीश भंडारी

कॉप 29 बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकसित देश अपने पापों की भरपाई नहीं करेंगे। इसके परिणामस्वरूप भारत तथा अन्य विकासशील देशों को न तो समुचित सहायता मिलेगी और न ही सब्सिडी वाला ऋण मिलेगा। वहां जो कुछ हुआ वह कम से कम मेरे लिए पूरी तरह अपेक्षित था। जिस पैमाने पर सहायता की आवश्यकता है वह किसी भी विकसित देश के लिए राजनीतिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे ऋण सुविधाओं का वादा कर सकते थे जो विकासशील देशों को भारी कर्ज में डालने वाली बात ही होती। बहरहाल, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बदलावों से जुड़े कर्ज की समस्या अब आड़े नहीं आएगी। इसके बजाय अब हमें बुनियादी समस्या पर ध्यान देना होगा। मसलन जलवायु परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के बीच हम कैसे बचें और समृद्धि हासिल करें।

यह चुनौती छोटी नहीं है। साक्ष्य बताते हैं कि बदलाव और आय को होने वाला नुकसान दोनों अनुमान से अधिक होंगे। जलवायु मॉडल बताते हैं कि दक्षिण एशिया सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है। अब यह स्पष्ट है कि औसत ताप वृद्धि जहां 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से ऊपर रहेगी वहीं चुनिंदा स्थानों पर कुछ खास दिनों में तापमान अनुमान से अधिक रहेगा। ऐसे में उत्तर भारत में 50 डिग्री से अधिक गर्मी का हालिया अनुभव उस बात की झलक है जो आने वाले समय में सामने आ सकती है।

इतना ही नहीं, हालिया शोध बताता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आय पर पड़ने वाला असर बहुत गहरा होगा। यह पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं अधिक होगा। कृषि पर हुए अध्ययन पहले ही यह दिखा रहे हैं कि उच्च तापमान और कम खाद्य उत्पादन के बीच गहरा संबंध है। असंगठित क्षेत्र की आय भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है क्योंकि उच्च तापमान स्वास्थ्य आदि को प्रभावित कर रही है। कुल मिलाकर बढ़ती गरमी आय और उत्पादकता पर नकारात्मक असर डाल रही है।

संयुक्त राष्ट्र चाह रहा है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर उठोरक कदम उठाए जाएं। वह कई देशों में नैशनल एडाप्टेशन प्लान सहित कई प्रकार की पहलों पर जोर दे रहा है। भारत ने भी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) तैयार की है। बहरहाल, एनएपीसीसी लोगों को होने वाले आय संबंधी नुकसान पर ध्यान नहीं देता। न ही वह लचीलापन बढ़ाने या उन्हें गर्म होती दुनिया के मुताबिक ढलने में सक्षम बनाने केंद्रित है।

एनएपीसीसी के आठ घटक या मिशन हैं जिसमें शामिल हैं: ज्यादा सौर ऊर्जा, बेहतर ऊर्जा किफायत, ऊर्जा किफायत वाला शहरी निर्माण, जल का बेहतर इस्तेमाल, हिमालय की पारिस्थितिकी में सुधार, वनाच्छादित क्षेत्र में इजाफा और जलवायु परिवर्तन को लेकर जानकारी और समझ में सुधार। ये सब सही हैं हालांकि इनमें से कुछ के मोर्चे पर प्रदर्शन सही नहीं है। ज्यादा महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमें आय को बचाने की जरूरत है, मजबूती हासिल करनी है और पेशागत और जीवन शैली संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने में मदद करनी है। एनएपीसीसी चाहे जितना उद्देश्यपूर्ण हो लेकिन वह उभरती समस्याओं को हल नहीं करेगा।

अधिकांश भारतीय राज्यों ने गर्मी से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान (एचएपी) तैयार किए हैं लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्देशित होते हैं जिसका ध्यान स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम आधारित प्रणाली अपनाने का है। दूसरे शब्दों में कहें तो एचएपी अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है जो काफी हद तक वैसा ही है जैसे प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी। जिस प्रकार जीआरएपी प्रदूषण के अधिक व्यवस्थित मामलों से निपटने में नाकाम है वैसे ही एचएपी अनुकूलन की चुनौतियों से निपटने में। देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में जो तरीके अपना रहा है वे उसके बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ असंगत हैं।

इस चुनौती को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक गर्मी, अधिक अस्थिर जलवायु को अपनाने में नाकामी से हुए नुकसान पर विचार करें। उत्पादकता में गिरावट न केवल कृषि और पालतू-पशुओं पर असर डालेगी बल्कि व्यापार, परिवहन, विनिर्माण और असंगठित विनिर्माण, पारिवारिक लोग भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। जिन पेशों में बाहर उत्पादन होता है वहां भी असर होगा। यहां तक कि अगर हवा के आने-जाने और ठंडा रखने का उचित इंतजाम नहीं हुआ तो घर के भीतर से किए जाने वाले काम भी प्रभावित होंगे। शिक्षा के प्रभाव पर भी असर पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति पर भी। जब समस्या इतनी बड़ी हो तो शुरुआत कहां से की जाए?

सब कुछ करने के बजाय, हमें कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना होगा जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अलावा हमें ऐसी क्रियान्वयन प्रणालियों की मदद से काम करना होगा जिन्हें बनाने में वर्षों का समय नहीं लगता और जो पहले ही सफल साबित हो चुके हैं। मैं यहां दो बातों पर ध्यान केंद्रित करूंगा।

पहली चुनौती है लोगों को अत्यधिक गर्मी से बचाना। इसमें शामिल है घरों, कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक जगहों मसलन फुटपाथ, छोटे बाजारों और चौपाल आदि को अत्यधिक गर्मी से बचाना। भारी गर्मी वाली जगहें जीवन और स्वास्थ्य को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके लिए कई पहल करने की आवश्यकता होगी। इनमें ठंडी छतों को अपनाना, घरों को हवादार बनाना और पौधों, वृक्षों आदि की मदद से सार्वजनिक स्थानों को गर्मी के प्रभाव से बचाने के प्रयास करना शामिल है। पानी की उपलब्धता भी एक अहम बात है। जल जीवन मिशन के दावों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण इलाकों में गर्मी से निपटने संबंधी लक्ष्यों को इसमें शामिल किया जा सके। शायद इसके लिए एक जल ताप मिशन शुरू करना होगा ताकि शहरों में गर्मी की समस्या से निपटने का प्रयास किया जाए। ऐसे मिशन को जरूरी स्थानीय निकायों और समुदायों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि गर्मी से संबंधित जोखिमों के बारे में जागरुकता बढ़ाई जा सके और गर्मी से निपटने के प्रभावी उपायों पर काम किया जा सके।

दूसरा प्रमुख मुद्दा कृषि से संबंधित है और इसमें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पहले ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। वह पालतू पशुओं और बीजों को लेकर शोध, नवाचारी व्यवहार को लेकर फंड मुहैया करा रहा है। तकनीकी रूप से देखें तो नाबार्ड कोई सरकारी संस्थान नहीं है लेकिन कृषि संबंधित विनिर्माण, शोध संस्थानों, व्यापार एवं अन्य सेवाओं के मामले में उसका व्यापक नेटवर्क उसे सक्षम बनाता है कि वह कृषि में जरूरी बदलाव में मदद कर सके। भारत को एक व्यापक खाद्य भंडारण व्यवस्था भी कायम करनी होगी। मौसमी उतार-चढ़ाव कृषि उत्पादन पर असर डालेगा और कीमतों पर भी। यहां भी नाबार्ड मददगार साबित हो सकता है।

इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जाना है लेकिन चौतरफा प्रयास करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रयास करें और उन चीजों पर काम करें जो ज्यादा मायने रखती हैं। फिलहाल के लिए इसका अर्थ है लोगों को, खेतों को अत्यधिक तापमान और मौसमी उतार-चढ़ाव से बचाना।

उत्सर्जन में कमी की बात करें तो भारत पहले ही पंचामृत और एनएपीसीसी के साथ उस दिशा में काम कर रहा है। इन प्रयासों को रोकने की आवश्यकता नहीं है केवल नई पहलों पर ध्यान देना होगा जो अधिक गर्म और अप्रत्याशित जलवायु से निपटने में सक्षम हों।

ट्रंप की नीतियां और अमेरिका का भविष्य

एक ऐसे विशाल देश की कल्पना कीजिए जहां राष्ट्रीय ऋण का बोझ वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 100 प्रतिशत था, वहीं अब 2024 में यह बढ़कर 125 प्रतिशत पर पहुंच गया है। बजट घाटा प्रति वर्ष औसतन लगभग 6 प्रतिशत के स्तर पर है। अब नई सरकार 2025 में करों में कटौती करने की योजना बना रही है, ताकि ऋण से जीडीपी अनुपात की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके।

हालात संभालने के लिए सरकार कई वस्तुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। व्यापारिक साझेदार देश इस कदम का कड़ा विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे भी बदले में अपने यहां आने वाली वस्तुओं पर शुल्क लगाने का फैसला कर लें। इससे व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। नतीजतन ऐसे कदमों से महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जिस देश की यहां बात हो रही है, वह पहले से ही भारी व्यापार घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में आयातक नए करों में जाने वाली रकम की भरपाई उपभोक्ताओं से करना चाहेंगे। जो भी विनिर्माता सामान आयात करेगा, वह मोटा मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाएगा।

इसके अलावा सरकार कार्यबल में भी लगभग 5 प्रतिशत जबरन कटौती की संभावनाएं तलाश रही है। इस कटौती से वेतन-भत्तों में जाने वाली अच्छी-खासी रकम रुक जाएगी और करों के साथ जुड़कर एक मोटी धनराशि खजाने में पहुंचेगी, जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इनपुट के साथ जीडीपी में 6 से 7 प्रतिशत का योगदान देगी। रोजगार के मोर्चे पर हालात सामान्य हैं, इसलिए कार्यबल में कटौती के बाद खाली होने वाले पदों पर भर्ती की जल्दबाजी नहीं होगी।

सरकार बीजा नियमों को भी और सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके जरिये विदेश से उच्च कौशल वाले कर्मचारी लाने में मदद मिलती है। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और अनुसंधान एवं विकास नहीं, सरकार बड़े स्तर पर अफसरशाहों को बर्खास्त करने अथवा उन्हें हटाकर उनकी जगह नए अधिकारी नियुक्त करने के बारे में सोच रही है। इसके पीछे तर्क यह है कि नए अधिकारियों के जरिए ऐसे शासकीय संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से डेटा एकत्र करने और वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखते हैं। सरकार का कुछ निकायों को खत्म करने का भी इरादा है। नई सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य देखभाल जैसे कई सामाजिक सुरक्षा आधारित कार्यक्रमों और योजनाओं में भी कटौती की जाए। साथ-साथ वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के कार्यक्रमों-उपायों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। इसके अलावा सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नियमों में ढील देना चाहती है।

देवांशु दत्ता

मैं ये सब बातें अमेरिका के संबंध में कह रहा हूं, जहां डॉनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रचार अभियान के दौरान नीतियों में बदलाव लाने के लिए मतदाताओं से वादे किए थे और अब वह राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्हें लागू करने की दिशा में काम करेंगे। इनमें से बहुत सी नीतियां सकारात्मक प्रभाव डालने वाली प्रतीत नहीं हो रही हैं। अनेक असामान्य नीतियों के अप्रत्याशित रूप से गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कई ऐसी नीतियां हैं जो आज के युग में उपयुक्त नहीं हैं, ऐसे में इनसे अपेक्षित परिणाम हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा।

डॉनल्ड ट्रंप के नए शासन में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक इलॉन मस्क के अनुमान के मुताबिक अमेरिका कम से कम दो साल तक मंदी की चपेट में रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो यह स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से अमेरिका वैश्विक वृद्धि का महत्त्वपूर्ण इंजन बना हुआ है। मौजूदा भू-राजनीतिक वातावरण में कोई अन्य राष्ट्र ऐसा नहीं है, जो हालात को संभालने की स्थिति में हो।

इस समय अमेरिका 28 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है और यह वैश्विक जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान देता है। डॉलर विश्व की रिजर्व करेंसी है। अमेरिका की आर्थिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन होने से मंदी के अलावा भी कई अन्य प्रभाव पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर डॉलर से भरोसा उठने का वैश्विक बाजार पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। व्यापार युद्ध शुरू होने से आपूर्ति श्रृंखला भी अप्रत्याशित रूप से प्रभावित होगी। इनमें से कुछ भी हो सकता है, किसी चीज की गारंटी नहीं है। उदाहरण के लिए जापान में दशकों तक ऋण से जीडीपी अनुपात 250 प्रतिशत से अधिक रहा है। इस दौरान इस विकसित देश में कोई वृद्धि नहीं हुई।

अमेरिका बहुत ही असाधारण स्थिति से गुजर रहा है। वह घाटे से उबरने के लिए डॉलर छाप सकता है। लेकिन, यह उपाय तब तक ही कारगर साबित होगा जब तक अमेरिकी डॉलर से विश्वास नहीं डगमगाता। किसी नई संतुलित स्थिति तक पहुंचने से पहले हम अगले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक बाजारों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से दो-चार हो सकते हैं। काफी कुछ भीड़ की बुद्धिमत्ता और बाजार से आने वाली असामान्य खबरों से व्यापारियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगा। लेकिन, अभूतपूर्व हालात से निपटना आसान नहीं होगा।

समय को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना ही व्यवहारिक होगा। उदाहरण के लिए भारतीय कंपनियां यदि दक्षिण अप्रीकी इकाइयों के साथ समझौते करती हैं, तो संभव है लेनदेन अमेरिकी डॉलर में ही होगा। अब यदि अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव आता है तो यह सौदा प्रभावित होना तय है।

धातु, रबर, कच्चा तेल, चिप्स जैसी अधिकांश वस्तुओं की खरीद-बिक्री अमेरिकी डॉलर में ही होती है। ऐसे में यदि अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव आता है तो इन सभी वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। शुरुआत में बाजार पर ये प्रभाव देखने को शायद न मिलें। लेकिन, यदि ट्रंप अपने चुनावी वादों के अनुसार नीतियों में बदलाव के एजेंडे पर आगे बढ़ते हैं तो मजबूत वृद्धि दर का परिदृश्य उभरना मुश्किल होगा। वैश्विक बाजार के लिए पिछले कुछ वर्ष बहुत ही शानदार रहे हैं। वर्ष 2025 में बाजार में दोबारा मंदडियों की हलचल देखने को मिल सकती है।

आपका पक्ष

नेपाल और चीन के संबंध पर सतर्कता बरतने की जरूरत

चीन-नेपाल के बढ़ते संबंध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इससे माओवाद, ड्रग्स, अवैध हथियारों की आवाजाही बढ़ने का खतरा है। चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत, नेपाल में अपनी पैठ खो सकता है। साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है। चीन कभी भी नेपाल के लिए भारत का विकल्प नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत-नेपाल और नेपाल-चीन की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। भारत-नेपाल के संबंध न केवल सांस्कृतिक रूप से मजबूत हैं बल्कि भौगोलिक कारण भी इन संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। बहरहाल कहीं नेपाल किसी अन्य देश के साथ मिलकर हमारे लिए परेशानी का सबब न बन जाए। इसलिए कूटनीतिक स्तर पर प्रभावशाली निर्णय लेने की जरूरत है। नेपाल-भारत संबंध अहितीय और अनुकरणीय हैं। भारत वह पहला देश है जो जरूरत के समय नेपाल की मदद के लिए आगे आता है। हाल के दिनों में, चीन अपने आर्थिक और राजनीतिक जुड़ाव के जरिये नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे नेपाल में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। इसके बावजूद, भारत के साथ बराबरी करने के लिए चीन को अभी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि भारत-नेपाल संबंध बहुत गहरे हैं और सदियों पुराने हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

नेपाल के प्रधानमंत्री (बाएं) और चीन के राष्ट्रपति ने बुधवार को बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव सहयोग मसौदा समझौते पर हस्ताक्षर किए

ट्रंप की धमकी, डॉलर पर निर्भरता घटाने का समय

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर का विकल्प अपनाने पर 100 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने की धमकी वैश्विक व्यापार और कूटनीति के लिए गहन चुनौती प्रस्तुत करती है। यह न केवल बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। भारत, जो ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य और अमेरिकी बाजार का महत्त्वपूर्ण भागीदार है, इस स्थिति में संतुलन साधने की कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। भारत को अपनी आर्थिक स्वायत्तता मजबूत करते हुए डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए स्थानीय मुद्रा व्यापार प्रणाली और पारदर्शी वित्तीय ढांचे का विकास करना होगा।

आरके जैन, बड़वानी

भारत की जैव विविधता: संकट और संरक्षण

भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व में जाना जाता है। देश में पौधों, जानवरों और अन्य जीवों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण यह जैव विविधता खतरे में है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में आयोजित सीबीडी कॉन्फ्रेंस में भारत ने राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को अद्यतन किया है। इस योजना का उद्देश्य जैव विविधता के नुकसान को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करना है। जन-जागरूकता बढ़ाने, सख्त कानून लागू करने और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने से जैव विविधता को बचा सकते हैं।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

इसरो ने गुरुवार को पीएसएलवी-सी59 रॉकेट के जरिये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। प्रोबा-3 (प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी) में दो उपग्रह हैं, जिनमें दो अंतरिक्ष यान ने एक साथ उड़ान भरी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि प्रोबा-3 के साथ, मिशन 'मांग पर सूर्यग्रहण' बनाने में सक्षम होगा। इसरो के लिए यह प्रक्षेपण अपने पहले मिशन- आदित्य-एल 1 के बाद सूर्य पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। आदित्य-एल 1 को सितंबर 2023 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।

एंटीबायोटिक दवाएं हो रही हैं बेअसर

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रमुख वैश्विक समस्या बन गया है। जुकाम, गले में दर्द व फ्लू आदि के लिए तो लोग बिना सलाह खुद से ही एंटीबायोटिक ले रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक व गलत उपयोग के कारण कुछ बैक्टीरिया ने दवाओं के खिलाफ सुरक्षा विकसित कर ली है। इस कारण सामान्य रोगों का इलाज भी कठिन हो रहा है। बता रही हैं **स्मिता सिंह**

204
देशों में भारत 60 वें स्थान पर है, जहां माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण प्रति एक लाख आबादी पर होने वाली मृत्यु सबसे अधिक है। 2019 में करीब 3 लाख मौतें देश में इस कारण हुई।

हाल में कुछ दिन पहले एक डॉक्टर किसी टीवी चैनल पर एक 19 साल की आरती (बदला हुआ नाम) की मौत के बारे में बता रहे थे। आरती ल्यूकेमिया से पीड़ित थी। ल्यूकेमिया के उपचार व कीमोथेरेपी का मुकाबला भी आरती ने बहादुरी से किया। पर, वह जिंदगी की जंग हार गई। वह इलाज के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शिकार हो गई। सभी दवा बेअसर साबित हो रही थीं, क्योंकि वह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) से जूझ रही थी। इस कारण संक्रमण बढ़ गया। आरती की मौत कैंसर से नहीं, बल्कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाने के कारण हुई।

विशेषज्ञों के अनुसार, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक व गलत उपयोग इसे बढ़ा रहा है। कई बैक्टीरिया, जैसे ई.कोलाई, क्लेबसिएला, एसिनेटोबैक्टर आदि ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हासिल कर ली है। ऐसे में सामान्य रोगों का उपचार कठिन हो जाता है, कभी-कभी जानलेवा भी। जानकारी के अभाव में एएमआर से सबसे अधिक प्रभावित कम आय वाले लोग होते हैं।

एंटीबायोटिक दवाओं का काम

फोर्टिस अस्पताल, बेंगलुरु में कन्सल्टेंट गैस्ट्रो-एंटेरोलॉजिस्ट डॉ. प्रणव होन्नावरा श्रीनिवासन बताते हैं, 'जब शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया संक्रमण फैलाते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाएं इन्हें खत्म करने या वृद्धि को रोकने में मदद करती हैं। ये दवाएं बैक्टीरिया के प्रोटीन व डीएनए निर्माण को बाधित करती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं केवल जीवाणु संक्रमणों पर प्रभावी होती हैं। सामान्य रोग जैसे सर्दी व फ्लू आदि वायरसजनित रोगों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। दिक्कत है कि लोग तुरंत समस्या का हल चाहते हैं। पर, एंटीबायोटिक हर समस्या के लिए मैजिक बुलेट नहीं है।'

कब जरूरी हो जाती हैं ये दवाएं

डॉ. प्रणव होन्नावरा श्रीनिवासन के अनुसार, एंटीबायोटिक दवा तभी ले, जब डॉक्टर इसे संक्रमण के उपचार के लिए जरूरी मानें। जैसे-

1. **बैक्टीरियल इन्फेक्शन :** जैसे निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, त्वचा व गले के संक्रमण।
2. **जटिल संक्रमण :** यदि संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, जैसे ब्लड पॉइजनिंग (सेप्सिस)
3. **रोगनिवारक उपयोग :** कुछ विशेष हालात में, सर्जरी या इम्यूनिटी कमजोर होने पर संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं।
4. **पाचन तंत्र संक्रमण :** जैसे बैक्टीरियल डायरिया, जिसमें साल्मोनेला या कैंपिलोबैक्टर शामिल होते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लें। अनुचित उपयोग शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाता है।

क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तब होता है, जब बैक्टीरिया विशेष को मारने के लिए बनाई गई एंटीबायोटिक दवा के खिलाफ बैक्टीरिया सुरक्षा विकसित कर लेते हैं। एक बार जब शरीर किसी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेता है, तो उसका असर कम हो जाता है। ऐसे में एंटीबायोटिक दवा लेने के बावजूद कुछ प्रतिरोधी बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और शरीर में बढ़ते जाते हैं। इस कारण, सामान्य उपचार के लिए अलग -अलग एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, जिनका शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज भी कठिन हो जाता है। कुछ मामलों में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। दवाओं का अधिक व गलत उपयोग ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण बनता है।

एएमआर का बढ़ता बोझ

शिव नाडार विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर के डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस (स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज) में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ऋचा द्रिवदर्शनी बताती हैं, 'बैक्टीरिया में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) का तेजी से बढ़ना एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन गया है। इसका पता इससे भी चलता है कि 1990 से 2023 के बीच हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु एएमआर के कारण हो रही है। कई बैक्टीरिया, जैसे ई.कोलाई, क्लेबसिएला, एसिनेटोबैक्टर व स्टैफिलोकोकस ऑरियस ने एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हासिल कर लिया है। ये तथाकथित 'सुपरबग' संक्रमण का कारण बनते हैं और इलाज कठिन हो जाता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'देश में उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी, साफ पानी और सेहत सुविधाओं की पहुंच में जबर्दस्त कमी भी एएमआर के प्रसार के प्रमुख कारक हैं। एएमआर संक्रमण के कारण होने वाली मौतों की संख्या के 2050 तक कैंसर से होने वाली मौतों से अधिक होने का अनुमान है। एएमआर से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है।

एंटीबायोटिक लेते समय सावधानी

1. **डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएं दवा :** बिना डॉक्टर से सलाह लिए कभी भी एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करें। डॉक्टर आपके संक्रमण को सही तरीके से समझ करके उचित दवा और उसकी मात्रा तय करते हैं।
2. **दवा का कोर्स पूरा करना है जरूरी :** भले ही किसी रोग के लक्षण दवा खत्म होने के पहले समाप्त हो जाएं, दवा का कोर्स पूरा करना जरूरी है। अधूरा कोर्स बैक्टीरिया को दोबारा सक्रिय होने का अवसर प्रदान कर सकता है।
3. **अनावश्यक उपयोग से बचें :** वायरस जनित रोगों जैसे सर्दी-जुकाम में इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। लक्षणों के आधार पर दूसरों को दी गई दवाएं या पहले कभी ली गई दवाएं खुद से न खरीदें।
4. **साइड इफेक्ट को रखें ध्यान :** एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट जैसे कि दस्त, स्किन रैशेज या पेट दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
5. **स्वाभाविक प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखें :** बार-बार एंटीबायोटिक का उपयोग शरीर में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है, जिससे जटिल संक्रमणों का उपचार कठिन हो सकता है। हर व्यक्ति पर एक ही तरह की एंटीबायोटिक फिट नहीं होती। साथ ही तुरंत समाधान पाने के लिए हर तरह की दवा लेने में जल्दबाजी न करें।

महत्वपूर्ण जानकारियां

- बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आदि सूक्ष्मजीवी जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) विकसित कर लेते हैं, वे सुपरबग कहलाते हैं। अनुमान के अनुसार, अगले 25 सालों में 4 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु इन सुपरबग्स के कारण हो सकती हैं।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में एएमआर से होने वाली मौतों की संख्या श्वसन संबंधी संक्रमण, टीबी, आंत संबंधी संक्रमण, मधुमेह और किडनी रोग, मेटरनल एवं नीओनेटल डिसऑर्डर से होने वाली मौतों से अधिक है।
- अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, एंटीबायोटिक प्रतिरोध का स्तर चीन में सबसे अधिक है, उसके बाद कुवैत व अमेरिका का स्थान है।
- रेजिस्टेंस से जुड़ी मौतों के लिए छह प्रमुख पैथोजेन ई. कोलाई, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, क्लेबसिएला न्यूमोनिया, एसिनेटोबैक्टर बाउमानी और स्यूडोमोनस एरुगिनोसा हैं।

समय पर उपचार से वर्टिगो की परेशानी को बढ़ने से रोकें

वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति का सिर चकराने लगता है। इसका एक प्रमुख व आम कारण कान के आंतरिक भाग में गड़बड़ी आना है। पर, वर्टिगो के कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। समस्या की गंभीरता के बारे में बता रहे हैं **विवेक शुक्ला**

आमतौर पर वर्टिगो की समस्या में व्यक्ति को चक्कर आते हैं। पर, यह केवल सिर चकराने तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति में इसके कारण अलग होते हैं। महिलाओं में गर्भावस्था और बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप भी वर्टिगो का कारण बन सकता है। वर्टिगो दो प्रकार का होता है।

- **पेरिफेरल वर्टिगो:** जब कान के अंदरूनी भाग खासकर वेस्टिबुलर नर्व या तंत्रिका में समस्या होती है, तब पेरिफेरल वर्टिगो का सामना करना पड़ता है। यह नस शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
- **सेंट्रल वर्टिगो:** स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सिर पर गंभीर चोट लगना, माइग्रेन, इंफेक्शन आदि से ऐसा हो सकता है।

लक्षण करते हैं सचेत

- **चक्कर आना:** यह सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके साथ ही अन्य लक्षण भी सामने आ सकते हैं....
- **टिनिटस:** कानों में विशेष आवाजें सुनाई देना, जिन्हें अन्य नहीं सुन सकते
- एक या दोनों कानों से सुनाई न देना
- शरीर का संतुलन बिगड़ना, पसीना आना, जी मिचलाना, सिरदर्द होना
- आंखों के आगे अंधेरा छा जाना
- तेज आवाज से सिरदर्द होना
- गिरने या हिलने का अहसास होना

उपरोक्त लक्षण कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक और कई घंटे तक बने रह सकते हैं।

वर्टिगो में जांच व उपचार

- **वेस्टिबुलर टेस्ट बैटरी :** मरीज के आंतरिक कान या मस्तिष्क की समस्या का पता चलता है।
- **इमेजिंग परीक्षण :** सीटी स्कैन व एमआरआई जांचें कराई जाती हैं।

कई विधियां हैं उपचार की

वर्टिगो का उपचार लक्षणों व किस कारण से समस्या है, उसके आधार पर किया जाता है। बुनियादी रोग का उपचार होने पर समस्या में आराम आ जाता है।

- **दवाएं:** चक्करआना, जी मिचलाना या उल्टी की स्थिति में डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुरूप दवाओं का परामर्श देते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवाएं न लें।
- **कैनालिथ रिपोजिशनिंग प्रक्रिया :** इसे 'इप्ले मैन्युवर' भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में आंतरिक कान में कैनालिथ को पुनः स्थापित करने के लिए व्यायाम कराए जाते हैं। यह प्रभावी उपचार है।
- **सर्जरी :** अन्य विधियों से राहत न मिलने पर सर्जरी करा सकते हैं।
- **विशेष व्यायाम:** शारीरिक संतुलन से जुड़े विशेष व्यायाम मस्तिष्क को असंतुलन से निपटने में मदद करते हैं। इस संबंध में डॉक्टर की सलाह लें।

ऐसे मिलेगी राहत

- चक्कर आते ही बैठ जाना
- सहारे के लिए तकिये पर सिर ऊंचा करके सोना
- वर्टिगो का एहसास होने पर अंधेरी जगह में लेट जाना या लाइट बंद कर देना
- पर्याप्त नींद लेना
- तनाव का प्रबंधन करना
- पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थ पीना।
- याद रखें, शराब का सेवन चक्कर, असंतुलन या मतली की समस्या बढ़ाता है, इससे दूर रहें।

...जटिलताओं से बचे रहें

वर्टिगो की समस्या अचानक गिरने जैसी जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है। बुजुर्गों में हड्डी टूटने (बोन फ्रैक्चर) या फिर चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए वर्टिगो से ग्रस्त मरीजों को वाहन चलाने, तैराकी करने से बचना चाहिए। वीरासम या बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद नहीं करना चाहिए।

(मेदांता, गुरुग्राम के ई.एन.टी. विशेषज्ञ डॉ.के.के.हान्डा से बातचीत पर आधारित)

आंखों को प्रदूषण से बचाएं

सवाल-जवाब

■ मुझे देर तक फील्ड में रहना पड़ता है। आंखों में लाली, खुजली व जलन रहती है। क्या प्रदूषण आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है ?

जी हां, प्रदूषकों के संपर्क में आने से आंख की बाहरी परतों (कॉर्निया व कंजंक्टिवा) में ऑक्सीडेटिव क्षति व सूजन संबंधी बदलाव होते हैं। ये प्रदूषक प्राकृतिक आंसुओं की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आंखों में सूखापन, जलन, खुजली व एलर्जी होती है। शोध बताते हैं कि अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहने वाली आबादी में बच्चों में मायोपिया (चश्मा लगना) और वयस्कों में मैक्यूलर डिजनेरेशन (एआरएमडी) की घटनाएं बढ़ रही हैं।

लक्षण

प्रदूषण के स्तर व आंखों की संवेदनशीलता पर ये लक्षण निर्भर करते है-

■ आंखों में जलन व खुजली ■ आंखों में संक्रमण, खासकर आंखों को रगड़ना ■ आंखों का लाल होना ■ आंखों का सूखापन बढ़ना, ऐसा आंखों की प्राकृतिक आंसू बनाने की प्रक्रिया में बाधा आने से होता है ■ आंखों में पानी आना

प्रदूषण से कैसे बचाएं आंखें

■ बाहर जाने से बचें, जब वायु प्रदूषण कम हो, उस समय में जाएं

डॉ. विकास वीरवाल
निदेशक, फेस आई सेंटर, इंडिरापुरम, गाजियाबाद

■ हर समय खिड़कियां व दरवाजे खोलकर न रखें।
■ बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मा पहनें।
■ दोपहिया वाहन चलाते समय बंद हेलमेट पहनें।
■ आंखें न रगड़ें, इससे संक्रमण व कॉर्निया को नुकसान हो सकता है।
■ आर्टिफिशियल टियर्स इस्तेमाल करें, इससे आंखों की नमी बनी रहती है।
■ खुजली होने पर 5 से 7 मिनट तक ठंडी सिकाई करें। प्रदूषक तत्वों को हटाने के लिए समय-समय पर आंखों को ठंडे पानी से धोएं।
■ भरपूर पानी पिएं।
■ समस्या गंभीर हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

भेजें अपने सवाल

अपनी सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-

तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन अशांत हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में बाधा आ सकती है। कारोबार के लिए माता-पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

वृष : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। पर, मन परेशान हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के मौके मिलेंगे।

मिथुन : मन में बुरे विचारों से बचें। परिवार की सेहत का भी फिलहाल ध्यान रखें। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। खर्चों की अधिकता रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। आलस संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि के साधन बन सकते हैं।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है।

कन्या : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। क्रोध व वर्चस्व के वाद-विवाद से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान भी रखें।

तुला : मन प्रसन्न तो रहेगा। फिर भी बातचीत में संयत रखें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृश्चिक : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। पर, मन अशांत हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग बढ़ेंगे।

धनु : मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। दैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा।

मकर : वाणी में मधुरता रहेगी। पर, मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। कारोबार बढ़ेगा।

कुंभ : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबारी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। वाहन के रख-रखाव पर खर्च होंगे।

मीन : मन अशांत रहेगा। आलस संयत रहें। क्रोध से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। संतान की सेहत का ध्यान रखें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषभकांत गोस्वामी

06 दिसंबर, शुक्रवार। शक संवत: 15, मार्गशीर्ष (सौर) 1946, **पंजाब पंचांग:** 21, मार्गशीर्ष मास प्रविष्टे 2081, **इस्लाम:** 03, जमादि-उस्सानी1446, **विक्रमी संवत:** मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी दोपहर 12. 08 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि, चन्द्रमा मकर राशि मे रात्रि 05.07 (सूर्योदय पूर्व) तक उपरांत कुंभ राशि
सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल। पंचक प्रारंभ रात्रि 05.07 बजे से (सूर्योदय पूर्व। श्री पंचमी। स्कंद षष्ठी।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हाथों में जो लाल कलावा बांधते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है?
-रोहित पाल, दिल्ली

- लाल कलावा कच्चा सूत होता है, जो पवित्र होता है।
- हाथ में कलावा बांधने से यह हमारे लिए रक्षा कवच की भांति काम करता है।
- लाल कलावे को तुलसी के पौधे में बांधते हैं तो यह मुसीबतों से रक्षा करता है।
- लाल कलावे को शमी के पौधे पर बांधने से यह राहु केतु के दोषों में कमी करता है।
- यदि लाल कलावे को पीपल के पेड़ पर बांधते हैं तो सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।
- लाल कलावे को शिव परिवार के चारों ओर बांधने से परिवार में प्रेम भाव बढ़ता है।

वर्ग पहेली : 7807

ऊपर से नीचे
2. तपना; धधकना; लपट फेंकते हुए जलना (4)
3. एक रंग; आकाश जैसा रंग (2)
4. अप्रिय काम से कतराना; कष्टसाध्य काम से कतराना; पीछा छुड़ाना; भागना (2,3)
5. ईश्वर; जगदीश्वर; परम आत्मा (4)
7. चढ़ना; सवारी पर बैठना (3,2)
8. बिगाड़; विरोध; झंझट; झगड़ा (4)
9. तालाब; सरोवर (5)
10. भलमनसाहत; शिष्ट व्यवहार; सात्विक व्यवहार (4)
13. स्याही; काजल (2)

हरीश चन्द्र सन्नी, विविधा विधा, दिल्ली (उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं
1. निस्संतान रह जाना (2,2,2,2)
6. क्षमता; बल; शक्ति; सामर्थ्य (3)
7. जो सदा हरा भरा रहे; जिस पर हमेशा बहार बनी रहे, एक प्रकार के फूल का नाम (5)
9. अत्याचार करना; जुल्म करना, जुल्म ढाना (3,2)
11. प्रतिकार करना; वैर निकालना (3,2)
12. अभिधार्थ; अभिधेय; चीज; वस्तु (3)
14. इहलोक त्यागना; परलोक जाना; मृत्यु के बाद इस लोक से परलोक जाना, स्वर्गवास हो जाना (4,4)

वर्ग पहेली 7806 का उत्तर

अ		न	क	द	ना	रा	ण	
स्त्री		रा		वा			रा	
बा	र्य	र	त		ब	ट	क	ना
र		द			प		दा	म
क			स	ब	ल			बा
ऊ	स		म			ड़		की
मा	र	की	य		फ	म	जी	र
	का			वा		क		ह
हु	री	ते	ज	क	र	ना		ना

सुडोकू : 7789

* आसान

8			1				9	
	9		8	4			7	3
	7				2	4		
4		8	7					
	1						8	
					1	9		5
		6	5				1	
7	5			3	6		2	
	8				4			6

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

हल : सुडोकू नं.7788

1	3	6	4	5	2	9	8	7
9	4	7	1	3	8	2	5	6
2	5	8	9	6	7	3	4	1
5	8	2	6	1	9	7	3	4
4	1	3	7	2	5	6	9	8
6	7	9	8	4	3	1	2	5
7	6	5	2	9	4	8	1	3
3	2	1	5	8	6	4	7	9
8	9	4	3	7	1	5	6	2

दैनिक जागरण
सही समय की प्रतीक्षा में बहुत समय व्यर्थ चला जाता है

विदेशी हस्तक्षेप

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर देश के हितों के खिलाफ काम करने का जो सनसनीखेज आरोप लगाया, उसके बाद दोनों दलों में तकरार और अधिक बढ़ना तय है। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है, जो पहले से ही हंगामे का शिकार है। संबित पात्रा ने इस आधार पर राहुल गांधी को कठघरे में खड़ा किया कि एक प्रवंसीसी मीडिया समूह ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि स्वर्ब को संगठित अपराध और भ्रष्टाचार से लड़ने एवं स्वतंत्र बताने वाला अमेरिकी मीडिया समूह ओसीसीआरपी वस्तुतः न केवल वाई की सरकार की वित्तीय सहायता से चलता है, बल्कि उसकी एजेंसियों के हिसाब से दूसरे देशों और वाई के संस्थानों को निशाना बनाता है। इतना ही नहीं, ओसीसीआरपी को अमेरिकी निवेशक जार्ज सोरोस के ओपेन सोसायटी फाउंडेशन से भी पैसे मिलते हैं। जार्ज सोरोस के बारे में यह किसी से छिपा नहीं कि वह मोदी सरकार के कटु आलोचक हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि ओसीसीआरपी किस तरह भारत को नीचा दिखाने वाली खबरें प्रकाशित करता रहा है। ओसीसीआरपी अदाणी समूह के खिलाफ भी हमलावर रहा है। वह इस समूह के खिलाफ कई खबरें प्रकाशित कर चुका है। ध्यान देने की बात यह है कि उसकी खबरों के आधार पर भारत में हंगामा होता रहा है-संसद में भी और संसद के बाहर भी। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसी का उल्लेख किया।

उल्लेखनीय केवल यह नहीं कि ओसीसीआरपी की खबरों के जरिये हंगामा करने और सरकार को कठघरे में खड़ा करने में कांग्रेस आगे रही है, बल्कि यह भी है कि राहुल गांधी इस मीडिया समूह को वित्तीय मदद देने वाले जार्ज सोरोस के ओपेन सोसायटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से संपर्क-संबाद करते रहे हैं। कहना कठिन है कि राहुल गांधी किस उद्देश्य से ओपेन सोसायटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों से मिलते रहे हैं, लेकिन यह कोई रहस्य नहीं कि कुछ विदेशी मीडिया संस्थान और गैर सरकारी संगठन भारत की छबि खराब करने में लगे रहते हैं। उनकी रीति-नीति यही बताती है कि वे भारत के बढ़ते कद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे इस चेष्टा में भी रहते हैं कि भारत उनके हिसाब से चले। यह कई बार सामने आ चुका है कि यदि उन्हें अपना एजेंडा पूरा होता नहीं दिखता तो वे भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़ देते हैं। कोविड महामारी के दौरान ऐसे संगठन भारत में स्थिति को बेकाबू बताने में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस का कुछ भी कहना हो, यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि कई विदेशी ताकतें ऐसी हैं, जो भारत का हित नहीं चाहतीं। उनसे केवल सरकार ही नहीं, विपक्षी दलों को भी सतर्क रहना चाहिए। सबसे लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस इससे अपरिचित नहीं हो सकती कि अतीत में भी विदेशी ताकतें भारत में समस्याएं खड़ी करती रही हैं।

भूमि सर्वेक्षण में राहत

यह अच्छा हुआ कि बिहार सरकार ने प्रदेश में हो रहे भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा एक महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दी। ऐसा नहीं होने से कई प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी बढ़ जाती। कई लोग सर्वे में भाग लेने से वंचित रह जाते। अब लोग अगले वर्ष 31 मार्च तक स्वघोषणा पत्र जमा कर सकेंगे। निश्चित रूप से इससे बिहार के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। कागजात जुटाने में लोग परेशान थे। अनेक जगहों पर अफसरफरों का माहौल था। अब इसके लिए पर्याप्त समय मिल गया है। उम्मीद की जाती है कि कागजात के लिए कार्यालयों में जो अफसरफरी की स्थिति बन रही थी, वह अब कम होगी। कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी चाहिए कि वे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनने दें। मांगने पर आवश्यक कागजात उपलब्ध करा दें। दस्तावेज के लिए लिखवा मांगे जाने की भी कुछ जगहों से शिकायतें मिलती रही हैं। गत दिवस मुजफ्फरपुर में भइयों के बीच अलग-अलग जमाबंदी कायम करने के लिए लिखत लेते एक राजस्वकर्मी को गिरफ्तार भी किया गया। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह की शिकायतों पर अधिकारियों को नजर रखनी होगी। सरकार का प्रयास है कि सर्वे में सभी भूमि मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। खतियान, जमाबंदी पंजी जैसे राजस्व अभिलेख आनलाइन भी उपलब्ध हैं। लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कागजात कम हैं या आधे-अधूरे हैं तो भी स्वघोषणा से नहीं चूकें। सरकार ने इसकी भी छूट दे रखी है। सर्वे के दौरान जमीन पर अपने दावे के लिए स्वघोषणा के तौर पर बंशावली समर्पित करें। इसे किसी से अभिप्रमाणित कराने की भी जरूरत नहीं है। सरकार व विभाग की ओर से हर समस्याओं के समाधान की कोशिश की जा रही है।

पूर्वी पाकिस्तान बनता बांग्लादेश

विकास सारस्वत

भारत को इस सोच से बाहर आना होगा कि विकट स्थिति में भी वह बांग्लादेश पर सिर्फ कूटनीतिक दबाव ही बना सकता है

शेख हसीना सरकार के खूनी तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं। वहां से हिंदू कर्मचारियों के जबरन इस्तीफे लेने, उनकी जमीनें पर कब्जे, मकानों को जलाए जाने, मंदिर और मूर्तियों को तोड़े जाने एवं महिलाओं से दुष्कर्म के समाचार लगातार आ रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विश्व के बड़े मीडिया प्रतिष्ठान मुख्यतः इन हमलों की अनदेखी करते रहे, परंतु एक हिंदू संगठन के प्रमुख और इस्कान धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू दमन का संज्ञान लेने पर विवश किया है। चिन्मय और अन्य हिंदू नेताओं पर आरोप है कि उनकी चटगांव जनसभा में इस्कान का ध्वज बांग्लादेश के झंडे के ऊपर फहरा कर राजद्रोह किया गया। जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारियां हुईं हैं, उस आधार पर फुटबाल स्टेडियम में बैठे हर उस दर्शक को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके पर्सडीदा क्लब का झंडा बांग्लादेशी झंडे से ऊपर दिख जाए।

जिस दंड संहिता 121 और 124 के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा कायम हुआ है, उसमें कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है, परंतु ढाका पुलिस ने सीधे गिरफ्तारी कर ली। यह बांग्लादेश शासन और वहां की पुलिस की धृष्टता ही है कि वह सैकड़ों मंदिरों पर हो रहे हमलों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों पर तो पूरी तरह निष्क्रिय है, लेकिन गृह मंत्रालय के आदेश पर 15 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 'प्रदर्शनकारियों' पर गोली चला कर सभी मुकदमे वापस ले चुकी है। बांग्लादेशी पुलिस नितांत फर्जी मुकदमे में हिंदुओं की पकड़-धकड़ कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिस नेता फिरोज खान की शिकायत पर हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी हुई, उसे बीएनपी ने इस बेहूदा शिकायत के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार हिंदू धर्मगुरु को हिंदू हितों की रक्षार्थ किए गए साहस के लिए सबक सिखाना चाहती है। यह भी साफ है कि अंतरिम सरकार यह चाहती है कि हिंदू स्वयं पर ही रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर न उतरें। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी की अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद अन्य लोगों के अलावा दो और इस्कान संतों को गिरफ्तारी किया गया। इस्कान के कई बैंक खाते भी सील किए गए हैं। उससे जुड़े संतों को भारत आने से रोका जा रहा है।

चिन्मय के वकील रमन राय पर जानलेवा हमले से स्वीफजदा कोई भी वकील उनकी पैरोकारी के लिए आगे नहीं आ रहा है। दरअसल चटगांव की 25 अक्टूबर की ऐतिहासिक हिंदू रैली से इस्लामी कट्टरपंथी और यूनुस सरकार बौखलाई हुई है और वह किसी भी तरह हिंदू नेतृत्व को कुचलना चाहती है। बांग्लादेश में चार-पांच माह से जारी हिंसा इस मायने में अलग है कि इसे नकारने, छिपाने या कम करके पेश करने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत वायस आफ अमेरिका रेडियो चैनल द्वारा एक सर्वे कराकर बांग्लादेशियों से पूछा गया कि क्या अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? यह सर्वे कितना फर्जी था, इसे इससे समझा जा सकता है कि मात्र 1000 व्यक्तियों के इस सर्वे में 927 उत्तरदाता मुसलमान थे। सर्वे में 64.1 प्रतिशत लोगों ने अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति को शेख हसीना शासन से बेहतर बताया। इस फर्जी सर्वे के नतीजों को बांग्लादेशी और विदेशी मीडिया ने तथ्यों की तरह पेश किया।

अवधेश राजपूत

हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल के अनुसार तख्तापलट के पहले माह में ही अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले हुए। बांग्लादेश के सबसे बड़े समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' ने अपने संवाददाताओं से कराई पड़ताल में 5 और 20 अगस्त के बीच 49 जिलों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 1068 हमलों की पुष्टि की। इन हमलों में नौ हिंदू मारे गए थे। इस समाचार पत्र के संवाददाता इनमें से 546 हमलों के स्वयं साक्षी रहे। बांग्लादेश पुलिस न सिर्फ हिंदू विरोधी हिंसा रोक पाने में पूरी तरह विफल है, बल्कि उसने हिंदुओं को ही निशाना बनाया हुआ है। चटगांव के हजारी लेन, रंगपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर बर्बर लाठीचार्ज इसका उदाहरण है।

अल्पसंख्यकों की इच्छा के विरुद्ध बने पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में यदि अल्पसंख्यक खतरे में आते हैं तो उनकी रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी भारत की ही बनती है। बांग्लादेश के संबंध में तो भारत की भूमिका और अहम हो जाती है, क्योंकि उसके निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चूंकि वहां जब भी हिंदुओं पर हमले शुरू होते हैं, तब शरणार्थियों के जत्थे भारत की तरफ आते हैं, इसलिए भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की जान-माल की रक्षा करने की अपील की है, परंतु यह पर्याप्त नहीं। जब बांग्लादेश का शासकीय तंत्र फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की ओर चल पड़ा है, तब भारत को भी अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए।

यदि भारत यह सोचता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कूटनीतिक प्रयासों द्वारा वह बांग्लादेश पर दबाव बनाएगा तो तब तक देर हो सकती है। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए भारत बांग्लादेश में संयुक्त फोर्स की तैनाती का दबाव बना सकता है। ऐसे मिसाल अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ देशों में संयुक्त फोर्स की तैनाती की गई है। समय आ गया है कि बांग्लादेश के भीतर ही अल्पसंख्यकों के लिए स्वायत्तशासी क्षेत्रों के निर्माण के लिए जोर दिया जाए। अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते बांग्लादेश बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है। भारत को आर्थिक प्रतिबंध और व्यापारिक अवरोध समेत सीन्ध हस्तक्षेप का विकल्प भी खुला रखना चाहिए। भारत को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि विषम से विषम स्थिति में भी वह सिर्फ कूटनीतिक या अंतरराष्ट्रीय दबाव का ही सहारा ले सकता है। भारत को यह देखना होगा कि वह इसके इतर क्या कर सकता है?

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

आरक्षण में सेंधमारी न होने पाए

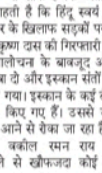

हरेंद्र प्रताप

डा. आंबेडकर के विचारों के जरिये वंचित वर्गों को मतांतरण कराने वालों के चंगुल में जाने से रोकना होगा

आरक्षण पर आंबेडकर के विचारों का पालन हो। फाइल

बाबा साहब डा. भीमराव आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस उचित अवसर है कि हम भारतीय संविधान के शिल्पकार के मूल्यों एवं शिक्षाओं को आत्मसात कर एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में उस राह पर चलने की प्रतिबद्धता का संकल्प लें। ऐसे ही संकल्पों का एक पहलू है कि संवैधानिक भाव एवं मूल्य तिरोहित न हों और देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें सुसंगत किया जाता रहे। हमारे संविधान निर्माता इस संदर्भ में बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इस लोकतांत्रिक ग्रंथ को जड़वत न बनाकर लचीला बनाया। भारतीय संविधान की सफलताओं में इस पहलू की विशिष्ट भूमिका भी रही है। यह पहलू संविधान की उचित व्याख्या के लिए गुंजाइश प्रदान करता है और इस दायित्व से संबंधित संस्थाएं समय-समय पर अपने इस कर्तव्य की पूर्ति भी करती रहती हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसाई पंथ से जुड़ी तमिलनाडु की एक महिला के अनुसूचित जाति के लाभ से जुड़ी याचिका के मामले में ऐसा ही किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अनुच्छेद-25 के दुरुपयोग की बात कही। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म यानी पंथ को निर्बाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसकी आड़ में देश में मतांतरण का घृणित कुचक्र चलाया जा रहा है।

ईसाई और इस्लाम पंथ में मतांतरित अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। भारत के संविधान में शिक्षा, सेवा, सत्ता और शासन में अनुसूचित जाति-जनजाति की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रविधान किया गया। अस्पृश्यता के खिलाफ डा. भीमराव आंबेडकर के लंबे संघर्ष के नाते तमाम दलों के नेता बात-बात में उनका नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। राजनीतिक दल और गठबंधन उसका फायदा उठाने के लिए इस्लामी और ईसाई संगठनों के पक्षकार बनकर देश में उनके द्वारा किए जा रहे मतांतरण पर मौन हैं। समय-समय पर ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के मतांतरण के समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। भय या लालच की आड़ में मतांतरण कराने वाले जब पकड़े जाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद-25 की आड़ लेकर बच निकलते हैं। बिहार के बक्सर जिले में पादरियों ने ईसाई पंथ में महिलाओं को मतांतरित करते समय उनकी मांग के सिंदूर को भी धो दिया था। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अगले दिन ही उन्हें जमानत मिल जाने से कानून की कमजोरी उजागर हो गई। अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ईसाई या इस्लाम पंथ स्वीकार करने का कोई प्रमाणिक मामला सामने इसलिए नहीं आ पाता, क्योंकि अनुसूचित जाति की जनगणना में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध का ही कालम होता है। उनके ईसाई या मुसलमान होने का उल्लेख नहीं मिलता।

तमिलनाडु के उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह सिद्ध हो गया कि अनुसूचित जाति के लोग ईसाई बनते रहे हैं। इसी तरह जनजाति समाज के लोग मतांतरित होते रहते हैं। इससे सभी अवगत हैं, लेकिन कोई भी समस्या की तह तक जाने को तैयार नहीं। जनजाति समाज के मतांतरण के कारण पूर्वोत्तर के नगालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई बहुल राज्य हो गए हैं। निकट भविष्य में अरुणाचल तथा मणिपुर के भी ईसाई बहुल होने के आसार बन गए हैं। वर्ष 1947 में देश का एक विभाजन हो गया। मिजोरम के ईसाई मुख्यमंत्री ने भी ईसाई देश बनाने की वकालत की थी। एससी-एसटी समाज के मतांतरण में लगे इस्लामी और ईसाई संगठनों से बचाने के लिए डा. आंबेडकर के विचारों को समेने लाकर इन समाजों को छल-बल से मतांतरित होने से रोकना होगा।

आंबेडकर जीवन चरित के लेखक धनंजय कीर ने बाबा साहेब के दृष्टिकोण को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है, 'अगर अस्पृश्यों ने इस्लाम या ईसाई पंथ स्वीकार किया तो वे हिंदू धर्म के साथ हिंदू संस्कृति से भी बाहर जाएंगे। अस्पृश्यों के मतांतरण की वजह से सामान्य रूप से देश पर क्या असर होगा, यह ध्यान में रखने लायक है। अगर वे मुसलमान हुए तो मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर वे ईसाई हुए तो ईसाइयों की संख्या पांच-छह करोड़ हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि इस देश पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ अधिक मजबूत होने में सहायता होगी।' ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि वोटों के सौदागर ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण देने की मांग उठाते रहे हैं।

अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2022 को गठित आयोग को मतांतरित दलितों की एससी का दर्जा देने की स्थिति के व्यापक अध्ययन का काम सौंपा गया। आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 10 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 1950 के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत वर्तमान कानूनी ढांचा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एससी का दर्जा देने की अनुमति देता है। आरंभ में यह आदेश केवल हिंदू समुदाय तक सीमित था, किंतु 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्र और समाज हित में संविधान संशोधन होते रहे हैं। आगे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक बार देश का विभाजन हो चुका है अतः मत-मजहब के प्रचार-प्रसार के नाम पर मतांतरण की छूट न दी जाए। इसके साथ ही मतांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ न मिले, इसके लिए भी कड़ा कानून बनाया जाए।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बद्ध और मुक्त

संसार में जिन लोगों का जीवन देहाभिमान और वासना से युक्त होता है, वे बद्ध कहे जाते हैं तथा जो इनसे परे होते हैं, वे मुक्त कहे जाते हैं। बंधन और मुक्ति का निर्णय जीवन में ही हो जाता है। इस नश्वर संसार को अपना मान लेना ही बंधन, जबकि इसे भगवान का मानना ही मोक्ष है। संसार का कोई संबंध और वस्तु स्थिर नहीं है। जैसे किसी यात्रा के समय जिस सीट पर हम बैठते हैं उसे छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही सांसारिक यात्रा पूर्ण होने पर करना पड़ता है। यात्रा का टिकट आयु है। जिस अभीष्ट स्थान पर जाना है वह मृत्यु है। जीवन में तेरी-मेरी और तेरा-मेरा का द्वंद्व उसी दिन विराम ले लेता है, जिस दिन शरीर प्राणशून्य हो जाता है। अतः समय व स्वस्थ रहते हुए ही आत्मकल्याण का साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ?

आज सत्संग से विमुख हो रहा मनुष्य भटकाव का शिकार हो गया है। वह धन, बल और वैभव आदि को ही सत्य मान बैठा है। भरणधर्मा संसार में अनेक जीव आते-जाते हैं, किंतु लोक में उसी का आना-जाना उत्तम है, जिसने अपने जीवनकाल में मानवता के लिए कोई ऐसा महनीय कार्य किया हो, जिसका जनमानस सम्मान करते हुए उसे अपने आचरण में उतारकर वैसा ही करने का प्रयास करे। वस्तुतः, जिसके सत्कार्यों का गुणगान जनमानस करे, वह सदा मुक्त है।

जीवन की प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति ही संसारिक बंधन हैं तथा अनुकूलता एवं प्रतिकूलता में सम रहना ही विमुक्त पुरुषों के सुलक्षण हैं। जिसे भी नश्वर संसार के बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा हो वह केवल दो कार्य करे। प्रथम स्वयं को उपलब्ध धन, जन और ऐश्वर्य आदि में अपनत्व का भाव तथा जो नहीं प्राप्त है उन कामनाओं का परित्याग। व्यक्ति कर्मों से बंधन में नहीं होता, अपितु कर्मों में आसक्ति के कारण बंधन में जकड़ जाता है।

आचार्य नरायण दास

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी

सुमीता मिश्रा

भारत पिछले एक दशक में 'महिला विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की ओर बढ़ा है

भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 'वुमेन एंपावर इंडिया' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें रोजगार से जोड़ना है, ताकि वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम बनें और अपने देश को सशक्त बनाएं। इस कार्यक्रम के लिए यूरोपियन यूनियन ने यूएन वुमेन (लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था) को 27.8 लाख डालर का फंड मुहैया कराया है।

भारत जैसे देश में महिला श्रम बल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय महिलाएं आज अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे घर एवं बच्चों को संभालने के साथ-साथ नौकरी भी कर रही हैं। स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। इसका राजफाश हाल ही में जारी किए गए सरकारी आंकड़ों में हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में 23.3 प्रतिशत थी जो 2023-24 में 41.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम बल भागीदारी दर 23 प्रतिशत बढ़ी है, जो 2017-18 में 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 47.6 प्रतिशत हो गई है। यह ग्रामीण उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गांव में खेती-बाड़ी से लेकर पशुओं के दूध का कारोबार, ये सभी काम ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को लेकर सभी कार्य क्षेत्रों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, उनका सम्मान भी बढ़ा है। लेकिन आज भी कई जगहों पर वे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।

कई बार महिलाओं को पुरुषों की भांति कामकाज के सिलसिले में घर-परिवार छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। वहां कई लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इन सबके बावजूद चिकित्सा का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, व्यवसाय हो या राजनीति, देश में अनेक क्षेत्रों में न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, बल्कि वे हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। जिस प्रकार बिना नारी शक्ति के सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है, उसी प्रकार आधी आबादी के सशक्त हुए बिना देश का विकास संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन द्वारा भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास सराहनीय है। ऐसे में महिलाओं को परिवहन, हास्टल और शिशु गृहों की सुविधा देकर कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलवाक्स

सामूहिक प्रयासों से ही समाधान संभव

'कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में शिवकांत शर्मा ने विश्लेषण किया है कि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए सरकार और जनता के बीच समन्वय जरूरी है। आज जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या से अधिक स्थानीय चुनौती बन गई है। बढ़ते तापमान, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाएं सीधे हमारे जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। भारत में कृषि-प्रधान राज्यों को भी इसकी तपिश झेलनी पड़ रही है। किसानों की फसलें अनियमित बारिश और सूखे से नष्ट हो रही हैं, जिससे न केवल उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। इस समस्या का समाधान न केवल तकनीकी, बल्कि सामाजिक भागीदारी में भी छिपा है। ग्रामीण इलाकों में जल-संचयन तकनीकों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। छोटे स्तर पर सामुदायिक तालाब, वर्षा जल संरक्षण और नदियों के पुनर्जीवन की दिशा में प्रयास कारगर हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा और हरित भवनों को प्रोत्साहन देकर ऊर्जा खपत को कम किया जा सकता है। सर्वजनिक परिवहन का उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देकर कार्बन उत्सर्जन घटाया जा सकता है। हालांकि, असली बदलाव तब आएगा जब सरकार और समाज मिलकर जिम्मेदारी लें। योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि स्थानीय लोगों को इसमें सक्रिय भागीदार बनाया जाए। पर्यावरण शिक्षा को व्यावहारिक बनाया जाए ताकि नई पीढ़ी सतर्क हो सके। जलवायु परिवर्तन को रोकने की लड़ाई में हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही इसका समाधान संभव हो सकता है।

awanishg30@gmail.com

दिव्यांग शब्द का गलत प्रयोग

काफी समय से शरीर के किसी अवयव, विशेषकर हाथ पैर के सदोष, शक्तिहीन या विकल होने को लेकर संबंधित व्यक्ति को 'दिव्यांग' कहा जाता है। सरकारी प्रयोग में भी यही है। यह प्रचलन सरासर गलत है। अंगहीनता या अपाहिज होना भला दिव्यता की श्रेणी में कैसे आ सकता है? महाभारत में महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो क्य उनकी आंखें टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थीं? नहीं। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए और फिर अंतर्गाल्हा वहां से दिव्य लोक भेजे गए। क्या वहां सब अपाहिज लोग थे? यह शब्द सदा अच्छे अर्थों में प्रयुक्त होता है, न कि नकारात्मकता के अर्थ में। ग्रंथों और उच्च स्तरीय रचनाओं में अंग हीनता या विकलांगता के अर्थ में यह कहीं नहीं प्रयुक्त हुआ है। बोल न पाने वाले को मूक और पैर से विकल को 'पंगु' कहा गया है। जैसे- मूक होहिं वाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन। श्रवणेंद्रिय काम न करने पर बधिर शब्द प्रयुक्त हुआ है, ''कोऽपि पादेन खंजः कोऽपि कर्णाभ्यां बधिरः'' इति। कोई विशेष अंग न होने पर हीन शब्द भी ब्रह्मों ने इस्तेमाल किया है, जैसे 'कोउ मुख हीन विपुल मुख काहू। बिनु कर पद कोउ बहु पद बाहू।' हाथ पैर की असमर्थता के लिए 'लुंज' शब्द भी साहित्यकारों ने प्रयोग किया है। ऐसे में, कम से कम सरकारी प्रयोगों में अंग भंग के लिए दिव्यांग लिखना बंद किया जाय।

रघोत्तम शुक्ल, लखनऊ

अतिक्रमण की समस्या

चार दिसंबर को प्रकाशित अग्रलेख में सही ही लिखा गया है कि सरकारी भूमि पर कब्जे व उस पर अनधिकृत निर्माण के घोटालों में सारा अमला शामिल रहता है। नहीं तो किसी भी जगह पर कोई भी भवन रातोंरात तो बन नहीं जाता। निर्माण होने में साल तक लग जाता है, उस स्थान पर न मालूम कितने सरकारी कर्मचारी और पुलिस के अधिकारी आते जाते रहते हैं, सभी उस निर्माण को देखते हैं, पर या तो उस भू-माफिया के भय से या उससे प्राप्त नकद लक्ष्मी नारायण के कारण आंख मूंद लेते हैं। फुटपाथ गायब ही हो गए हैं। सड़क पर चलना असुरक्षित हो गया है, अतिक्रमण के कारण भयंकर जाम भी लग जाता है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

25 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क मेक्सिको व कनाडा से आयातित वस्तुओं पर, जबकि चीन से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने।

प्रह्लाद सबनानी
वैश्विक-आर्थिक मामलों के जानकार

अमेरिका चुनाव परिणाम

नई सरकार का भारत पर संभावित असर

अगले वर्ष के आरंभ में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार कार्यभार संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव प्रचार के समय से ही वह कहते रहे हैं कि अमेरिका को एक बार पुन: विनिर्माण इकाइयों का केंद्र बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वह अन्य देशों, विशेष रूप से चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों पर 60 प्रतिशत तक का आयात शुल्क लगा सकते हैं। ऐसा होने से विनिर्माण इकाइयां अमेरिका में ही इन वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ करेंगी। इस तरह की परिस्थितियों के निर्मित होने की दशा में भारत को भी लाभ होने की उम्मीद जगी है

काइट हाउस : अमेरिका में अगले माह होने वाले सत्ता हस्तांतरण से बदल सकते हैं वैश्विक व्यापार के समीकरण। फाइल

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को भारत में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। वस्तुत: ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका के रिश्तों को भारत के साथ मजबूत करने का प्रयास किया था। वहीं, इस बार वह कह रहे हैं कि व्यापारिक लिहाज से अमेरिकी हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में आयात कर को बढ़ा देता है तो इसका प्रभाव भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पादों पर होगा। हालांकि अमेरिका में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में श्रम की लागत बहुत अधिक है। अमेरिका में निर्मित उत्पादों की लागत तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक रहने वाली है, इसके कारण एवं अमेरिका में आयातित उत्पादों पर आयात शुल्क के बढ़ाने से अमेरिका में मुद्रास्फीति की समस्या भी खड़ी हो सकती है।

इसके अलावा, अमेरिका यदि आयात को प्रतिबंधित करता है तो डालर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में और मजबूत होगी एवं अन्य देशों की मुद्राओं की बाजार में कीमत गिरेगी जिससे इन देशों में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात और अधिक आकर्षक होने लगेंगे। बल्कि इससे तो भारत से टेक्स्टाइल, लेदर, विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र से उत्पादों के निर्यात अमेरिका को बढ़ेंगे। अमेरिका से निर्यात कम होने लगेंगे, क्योंकि अन्य देशों को अमेरिका से आयातित वस्तुओं के एवज में महंगे डालर का भुगतान करना होगा। परंतु ट्रंप प्रशासन ने तो आगे आने वाले समय का आभास अभी से देना शुरू कर दिया है और मेक्सिको व कनाडा से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का आयात शुल्क एवं चीन से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी भारत से आयातित वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा अभी नहीं की गई है।

भारतीय उत्पादों की अमेरिका में एंट्री : यदि ट्रंप प्रशासन चीन से आयातित उत्पादों पर भारी भरकम आयात शुल्क लागू करेगा तो इससे भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका में जगह बन सकती है। विशेष रूप से आटो पार्ट्स, सौर ऊर्जा उपकरण एवं रसायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारतीय विनिर्माण इकाइयां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती हैं। इसी प्रकार, यदि अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी मात्रा में आयात शुल्क लगाया जाता है तो चीन के निर्यात कम होंगे और इससे चीन में आर्थिक वृद्धि दर कम होगी और ऊर्जा उत्पादों (कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि) की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम होगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें भी कम होंगी, इसका सीधा-सीधा लाभ भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत विश्व में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। साथ ही, ट्रंप ने अमेरिका में भी कच्चे तेल के उत्पादन को आगे आने वाले समय में बढ़ाने की घोषणा की है और तुलनात्मक रूप से कुछ सस्ते दामों पर कच्चे तेल का निर्यात भारत को किया जा सकता है। विनिर्माण एवं सुरक्षा (डिफेंस) के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को लाभ हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने ट्रंप के प्रथम कार्यकाल में भारत के साथ कई बड़े रक्षा सौदे संपन्न किए थे। अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत से सुरक्षा क्षेत्र के उत्पादों का आयात आगे आने वाले समय में बढ़ा सकता है।

ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत के खिलाफ कुछ आर्थिक कदम उठाए थे, जैसे भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) से हटा दिया था। लेकिन अंततोगत्वा भारत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ था। वर्ष 2018 में अमेरिका ने स्टील पर 25 प्रतिशत, अल्यूमिनियम पर 10 प्रतिशत, वाशिंग मशीन पर 35 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया था, परंतु वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच अमेरिका को भारत का स्टील निर्यात 44 प्रतिशत बढ़ गया था। इसी प्रकार, फुटवियर, मिनरल्स, रसायन, इलेक्ट्रिकल और मशीनरी जैसे उत्पादों का निर्यात भी भारत से अमेरिका को बढ़ा है, इससे सिद्ध होता है कि भारत कई उत्पादों के मामले में चीन के मुकाबले वैश्विक सप्लाई चेन में होने वाले बदलाव का अधिक लाभ उठाने की स्थिति में है। फिर भी, भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना होगा। भारत को नए निर्यात बाजार को तलाशना होगा एवं आयात कम करने के लिया आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर अधिक मजबूती से आगे बढ़ना होगा। ट्रंप प्रशासन यदि चीन के विरुद्ध कारोबारी युद्ध को प्रारंभ करते है, जिसकी प्रबल संभावना दिखाई देती है, तो इसका लाभ भारत को मिल सकता है। फार्मा, टेक्स्टाइल एवं इलेक्ट्रानिक्स जैसे क्षेत्रों में सप्लाई चेन में होने बदलावों के देखते हुए भारत लाभ की स्थिति में रह सकता है।

वीजा नियमों में बदलाव : ट्रंप प्रशासन के प्रथम कार्यकाल में अमेरिका में वीजा के नियमों को कठिन बना दिया गया था। यदि अपने दूसरे कार्यकाल में भी एच-1बी वीजा के नियमों को कड़ा किया जाता है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय मूल के नागरिकों पर पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में प्रतिवर्ष लगभग 85 हजार एच-1बी वीजा जारी किए जाते हैं एवं इसमें से लगभग 60 हजार वीजा भारतीय मूल के नागरिकों को जारी होते हैं। भारतीय मूल के नागरिकों पर वीजा संबंधी नियमों के कड़े किए जाने का प्रभाव सबसे अधिक हो सकता है। इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अमेरिकी और भारतीय चुनावी नारे में समानता

गजेंद्र सिंह

एक ऐसी दुनिया में, जहां शब्द न केवल धारणा को आकार देते हैं, बल्कि भावनाओं को भी जगाते हैं और भीड़ को एकजुट करते हैं, कोई सोच सकता है कि एकता की कुंजी एक नारे की सूक्ष्म शक्ति में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, हाल ही के अमेरिकी चुनाव के दौरान उपयोग किया गया नारा "यूनाइटेड वी स्टैंड" को लें। यह कितनी शक्तिशाली से एकजुटता का संदेश देता है। यह वाक्यांश न केवल एकता की बात करता है, बल्कि इसमें एक परिष्कार है जो इसे एक क्लासिक स्लोगन बनाता है। लेकिन स्लोगन की दुनिया में प्रतिस्पर्धा है और इस बार मैदान में एक क्षेत्रीय खिलाड़ी भी है, जिसका उपयोग खासकर महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में हुए उप चुनाव में किया गया था, जिसका नाम है "बंटेंगे तो कटेंगे"। इसमें एक स्थानीय आकर्षण है। पर क्या यह सचमुच उतना असरदार है?

"यूनाइटेड वी स्टैंड" एक ऐसा वाक्यांश है जो लोगों को धीरे से समूह में साथ आने का निमंत्रण देता है, मानो कह रहा हो, "हम अलग हो सकते हैं, पर अच्छे के लिए साथ भी आ सकते हैं।" इसकी अपील वैश्विक है। यह किसी भी भाषा में, देश के सभी क्षेत्र में, सभी पर प्रभाव डालता है। अब बारी है "बंटेंगे तो कटेंगे" की। यह वाक्यांश जैसे सीधे-सीधे, बिना किसी ताम्झाम के समझाता है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो नुकसान हमारा ही होगा। यह नरा सड़क का है, कोई आर्डबर नहीं, कोई पालिश नहीं, बस सीधा संदेश। इसी सुनकर ऐसा लगता है कि अगर हमने एकजुटता नहीं दिखाई, तो हम सब में मुश्किल में पड़ जाएंगे। "यूनाइटेड वी स्टैंड" का शिष्टाचार एक कुशल नेता की तरह लोगों को प्रेरित करता है, जैसे किसी सभा में एक प्रेरक भाषण दिया जा रहा हो। दूसरी तरफ, "बंटेंगे तो कटेंगे" बिना किसी झिझक के सीधा, गंभीर चेतावनी देता है। यह नारा मानो एक मां की तरह कहता है, "देखो, एकजुट हो जाओ, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार रहो।" इसमें नर्मी नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी है।

यदि एक आदर्श दुनिया की बात करें तो शायद सभी लोग "यूनाइटेड वी स्टैंड" से प्रेरणा लेंगे, इसे एकता का शिखर मानेंगे। परंतु कभी-कभी लोग सख्त शब्दों में बताई गई सच्चाई को भी सुनना चाहते हैं। "यूनाइटेड वी स्टैंड" जहां एक उम्मीद भरा संदेश देता है, वहीं "बंटेंगे तो कटेंगे" जैसे एक प्रकार से हमारे सामाजिक विखंडन की अखिरी चेतावनी की तरह सुनाई देता है। परंतु इतना अवश्य है कि यह नारा अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है। इसलिए इतिहास से सीख लेते हुए इस दिशा में अमल किया जाना चाहिए।

(लेखक सामाजिक चिंतक हैं)

अमेरिका में विजेय संबंध : भारत की तुलना में अमेरिका के पास लगभग साढ़े तीन गुणा अधिक जमीन है, जबकि जनसंख्या भारत की तुलना में एक चौथाई ही है। अमेरिका के पास 95 हजार किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा उपलब्ध है, अमेरिका के पास पूरे विश्व का 45 प्रतिशत पानी उपलब्ध है, पूरे विश्व के कोयला भंडारण का 22 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका के पास है। पूरे विश्व की जमीन का लगभग छह प्रतिशत हिस्सा अमेरिका में है। वहीं पूरे विश्व की कृषि योग्य भूमि का 10 प्रतिशत भाग अमेरिका के पास है, जबकि विश्व की केवल चार प्रतिशत जनसंख्या ही अमेरिका में निवास करती है। अमेरिका के पास 25,600 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार हैं जो सऊदी अरब में कच्चे तेल के कुल भंडारण से भी 20 प्रतिशत अधिक है। अब ट्रंप प्रशासन कच्चे तेल के इस भंडार में से अधिक मात्रा में कच्चा तेल निकालकर उपयोग करना शुरू करेगा। वर्ष 2018 तक अमेरिका कच्चे तेल का आयात ही करता रहा है, जबकि इसके बाद से अमेरिका कच्चे तेल का निर्यात भी करने लगा है। इसके चलते ही अमेरिका को पूरे विश्व में विशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। ट्रंप प्रशासन भारत को अपना स्ट्रेटेजिक भागीदार मानता रहा है। अमेरिका से विशेष दोस्ती होने के चलते आगे आने वाले समय में भारत को विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ होने की संभावना दिखाई देती है।

खरी-खरी

दुख में सुमिरन करने वालों का सुख

गिरीश सरस्वत

चुनाव होते हैं। जीत के जश्न भी मनते हैं। लेकिन कुछ लोग हारे हुए का हाल जानने को उत्सुक रहते हैं। उसकी नजरें हमेशा किसी राज को भेदने के लिए तत्पर रहती हैं।

वस्तुत: छिद्रान्वेषण एक सामाजिक क्रिया है। बढ़ती दुर्घटनाओं के साथ छिद्रान्वेषियों के लिए तुष्टीकरण के अवसर बढ़ रहे हैं। छिद्रान्वेषी वहां मौजूद रहकर देखना चाहता है कि आखिर हुआ क्या और कैसे? फिर, अपने मित्रमंडल में बताते हुए गौरवान्वित महसूस करता है, 'मैंने स्वयं देख था पूरा नजारा।' हादसे में किसी का खून बह रहा हो, तो छिद्रान्वेषी का चेहरा कितना भी नीला-पीला पड़ जाए, किंतु वहां से हटने को तैयार नहीं होता। शेखी जो बघारन है, 'मुझे तो नींद ही नहीं आई कल की घटना को याद करके।'

पीड़ा जितनी बड़ी होती है, पीड़ा के उपभोक्ता उतने ही अधिक होते हैं। दूसरों के दर्द को पास जाकर महसूस करना अजीब प्रकार की जिज्ञासा है। शेखी जो बघारन है, 'मुझे तो नींद ही नहीं आई कल की घटना को याद करके।'

पीड़ा जितनी बड़ी होती है, पीड़ा के उपभोक्ता उतने ही अधिक होते हैं। दूसरों के दर्द को पास जाकर महसूस करना अजीब प्रकार की जिज्ञासा है। शेखी जो बघारन है, 'मुझे तो नींद ही नहीं आई कल की घटना को याद करके।'

मदद की गुहार लगाते लोग उसे नयन सुख प्रदान करते हैं। हेलीकाप्टर से चक्कर काटते तमाशी का नजारा देखने वाला आत्मा सुख पाता है कि दुख के इन अनमोल दृश्यों को निहार पाने का गौरव केवल उसके लिए ही आरक्षित है। आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के आस-पास खड़े छिद्रान्वेषी और परिवार के सदस्यों का चेहरा पढ़ने की कोशिश करते हैं।

छिद्रान्वेषी दूसरों की कही सुनकर सुनने वाली थर्ड पार्टी बनने की जगह 'आई विटनेस' वाली फर्स्ट पार्टी बनने में विश्वास रखता है। घटना को सबसे पहले देखने से उसे सुनने का कापीराइट मिल जाता है। दूसरों का तुच्छ देख आदमी का मन ऐसा कैनवास बन जाता है जिस पर वह कल्पना के रंग बिखेर अगली बड़ी घटना के छिद्रान्वेषी को अपना चार्ज देने तक कल्पना चित्रों का चित्रेरा बन जाता है। माफ करना कबीर जी, दुख में सुमिरन करने वाले हमसे दूर ही रहें तो अच्छा।

पोस्ट

सिर्फ प्रतिभाशाली होना ही पर्याप्त नहीं। प्रतिभावान में समर्पण, एकाग्रता व सफलता की भूख होना भी जरूरी है। अवसर के साथ भाग्य का साथ देना भी आवश्यक है।
आर रजन सिंह@rranjan501

संभल मामले में विपक्षी दल भाजपा की पिच पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मामले में विपक्ष (विशेष तौर पर कांग्रेस) एक उचित दूरी बनाकर रखे तो उसे कहीं अधिक लाभ मिल सकता है।
सत्या चौधरी@satyagodara

वर्तमान परिस्थितियों में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी को कायम रखना ही तार्किक है। साथ ही, मध्यक्रम में रोहित शर्मा के उतरने से वैसी ही अनुभूति हो रही है, जैसे कभी आस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी क्रम में एडम गिलक्रिस्ट खेलते थे।
निखिल नाज@NikhilNaz

अगर आप पंडित नेहरू या इंदिरा गांधी पर कोई किताब लिखो तो कोई यह नहीं पूछता कि क्या आप कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस आदि में शामिल हो रही हैं, लेकिन विकसित भारत पर किताब लिखना जरूर कुछ लोगों को अखरने लगता है और वे अनाप-शनाप बातें करने लगते हैं।
शेहला राशिद@Shehla_Rashid

झारखंड डायरी

झामुमो का बढ़ता प्रभाव, भाजपा से छिटकते आदिवासी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में आदिवासी सुरक्षित 28 में से 27 सीटों पर क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कब्जा कर लिया। भाजपा के हिस्से में केवल एक आदिवासी सुरक्षित विधानसभा सीट आई। उस सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने जीत हासिल की। इसी वर्ष संपन्न लोकसभा चुनाव में भी राज्य की सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आदिवासी भाजपा से दूर हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब दो पड़ोसी राज्यों ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। आदिवासियों को आकर्षित करने की गरज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। वह झारखंड में राज्यपाल भी रह चुकी हैं।

इन सारी कवायद के बीच झारखंड में ऐसी क्या वजह हो गई कि भाजपा का आदिवासी सुरक्षित सीटों पर खाता नहीं खुल पा रहा है। जबकि इसे लेकर रणनीति बनाने में भाजपा ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी इसी उद्देश्य से दिया गया कि वह जनजातीय मतदाताओं का रुझान पार्टी की ओर करने में कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने भी बेहतर राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अपने दल का भाजपा में विलय कर दिया। दरअसल वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। फाइल

से ही भाजपा से आदिवासी वोटों की दूरी स्पष्ट दिखने लगी थी। इसी कारण से बाबूलाल मरांडी को पार्टी में वापसी कराई गई। इस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बढ़ी बहू सीता सोरेन और शिबू सोरेन परिवार के विश्वस्त रहे चम्पाई सोरेन को भाजपा में शामिल करने के पीछे भी आदिवासी मतदाताओं पर प्रभाव जमाना ही मुख्य उद्देश्य था। सीता सोरेन और चम्पाई सोरेन के माध्यम से इसकी खूब कसरत भी हुई। लेकिन सीता सोरेन चुनाव के मैदान में फिसड्डी साबित हुईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सोरेन परिवार के सहारे के बगैर उनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ने वाली है। वहीं चम्पाई सोरेन के चमत्कार पर भाजपा के नेताओं को खूब भरोसा था। यही कहकर उनकी पार्टी में एंट्री भी कराई गई कि वे झामुमो के लिए हानिकारक साबित होंगे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। चम्पाई स्वयं तो चुनाव जीते, लेकिन अपने बेटे को विधानसभा नहीं पहुंचा पाए। किसी आदिवासी सुरक्षित सीट पर भी उनका जलवा नहीं दिखा।

भाजपा ने इसके अलावा भी कई उपाय किए। घुसपैठ से लेकर रोटी, बेटी, माटी के सवाल उठाए गए, लेकिन ये सारे असरहीन रहे तो इसके पीछे की कोई न कोई वजह अवश्य रही होगी। दरअसल 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में खुधर दास के नेतृत्व में बनी सरकार के दौरान हुए कुछ निर्णयों को आदिवासी वोटों के छिटकने का बड़ा कारण माना जाता है। आदिवासियों के लिए बने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में आंशिक संशोधन की कोशिश गले की हड्डी बन गई। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इससे संबंधित प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन जनजातीय समाज में इससे प्रतिकूल संदेश गया। जल, जंगल, जमीन के प्रति संवेदनशील जनजातीय समाज ने इसे उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार के रूप में लिया।

आदिवासी बहुल इलाकों में परंपरागत पत्थलगड़ी को रोकने की मुहिम को भी इस समुदाय ने परेपर पर आघात के तौर पर लिया। हालांकि तब की सरकार ने पाथलगड़ी की आड़ में कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ मुकदमे किए थे। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद ये मुकदमे वापस ले लिए गए थे। इससे झामुमो का जनजातीय समुदाय के बीच का पुराना आधार और विस्तृत हुआ एवं नए इलाकों में पार्टी ने सफलता के झंडे गाड़े। उपरोक्त घटनाओं ने अलग-अलग क्षेत्र में बंटे जनजातीय समाज को एक जगह लाने और मिलकर ठोस निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित किया। इसका परिणाम हालिया विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। चुनाव परिणाम के बाद हेमंत सोरेन ने सत्ता में शानदार तरीके से वापसी की है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है।

उधर भाजपा हार के बाद संभल नहीं पाई है। पार्टी में समीक्षाओं का दौर चल रहा है और हार के ढेरों कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन अंतोत में हुए कुछ निर्णय इस परिस्थिति तक पहुंचने के बड़े कारणों में से एक है। शायर मुजफ्फर रज्मी ने भी क्या खूब लिखा है- ये जख्म भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई...।

मंथन

सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना

भारत में हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर बनाए गए अतिक्रमित स्थानों की पुनर्स्थापना की कोई राह न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से खुल रही है तो उसे सभी संबंधित समुदायों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग शांति का मार्ग है

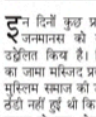

डा. विकास दवे
निदेशक, साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश

इन दिनों कुछ प्रकरणों ने भारतीय जनमानस को मानसिक रूप से उद्वेलित किया है। विशेष कर संभल का जामा मस्जिद प्रकरण और उस पर मुस्लिम समाज की उग्र प्रतिक्रिया अभी ठंडी नहीं हुई थी कि अजमेर का विषय जागृत हो गया। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के विषय भारतीय समाज के लिए नए हैं। भोजशाला के संदर्भ में केवल धार जिले के ही नहीं, बल्कि आसपास के झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगौन से लेकर संपूर्ण मालवा निमाड़ के शांतिप्रिय समाज को हम सबने सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाते हुए देखा है। इस तरह के संदर्भों की गाथा भारत में कभी समाप्त नहीं हुई। यह सब स्वाभाविक इसलिए भी है, क्योंकि भारत ने लगभग सात सौ वर्षों तक इन उग्र एकेश्वरवादी आक्रांताओं को अपने पूजास्थल तोड़ते हुए देखा है।

इन सारे प्रकरणों के बीच राम मंदिर के साढ़े पांच सौ वर्ष के संघर्ष ने जब न्यायालय के माध्यम से न्याय प्राप्त कर लिया और हिंदू समाज के स्वाभिमान का प्रतीक राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो एक आशा जागी कि यदि यह हो सकता है तो फिर शेष भी हो सकते हैं। विष्णु शंकर जैन जैसे अधिवक्ताओं ने भी इन प्रक्षालन के कार्यों को अपने जीवन का ध्येय पथ बना लिया। केवल वही नहीं, बल्कि उनके सुपुत्र भी निरंतर इन प्रकरणों को न्यायिक माध्यमों से न्याय दिलवाने के लिए लगे हुए हैं। कई बार इन प्रकरणों को जब समाचार पत्रों और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उठाए मन हिंदू समाज पढ़ता-देखता है तो हमारे कुछ लिबरल लोग बड़ी सहजता से यह कह देते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना देश को दंगों की आग में झोंकने का काम करेगा, किंतु हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जब इस शांतिप्रिय समाज ने कोई प्रतिकार नहीं किया, तब भी वह मारा काटा गया। एक अंग्रेज इतिहासकार ने अब तक के संपूर्ण इस्लामी आक्रमण का शोध संपन्न करके यह निष्कर्ष दिया है कि इस्लामी आक्रमणों में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की न्यूसंस हत्याएं की गईं।

हिंदू धर्मस्थलों की वैधानिक तरीके से वापसी के रास्ते में कोई क्या नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। फाइल

राम जन्मभूमि आंदोलन : अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन को जब शुरुआत हो रही थी, तब विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में संतों ने हुंकार भरते हुए कहा था कि हमें केवल अयोध्या, मथुरा और काशी वापस लौटा दीजिए, हम शेष मस्जिदों की बात नहीं करेंगे और हमें यह भी स्मरण है कि उस युग में टीवी और इंटरनेट की उपलब्धता तो नहीं थी, किंतु समाचार पत्रों में मुस्लिम समाज के पुरोधाओं के वे वक्तव्य आग में घी डालने का काम करते थे कि एक इंच भूमि भी हिंदुओं को नहीं लौटाएं जाएगी।

यह घोषणा करने वाले अपने ही मजहब के द्वारा दी हुई सीख को भूल जाते हैं। इस्लामी धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस स्थान को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया हो, वहां पर पढ़ी हुई नमाज को खुदा भी कबूल नहीं करता, फिर उन्होंने अपने मजहब की एक राजनीतिक आंदोलन बनाकर क्रूरता के नवीन इतिहास क्यों रच डाले? भारतीय समाज सीधे ढंग से बिना सड़कों पर उतरे संविधान की न्यायिक प्रक्रिया के तहत यदि अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहता है तो इसमें किसी को आपत्ति कयों होनी चाहिए? केवल इस भय से कि संघर्ष सड़कों पर आ सकता है, पीड़ित पक्ष ही अपने अधिकार को छोड़ना क्यों पसंद करेगा? हिंदू समाज समझ गया है कि यदि हम भारत की अधिकांश मस्जिदों में उपस्थित पुरातात्विक अवशेषों की अवहेलना करते हुए अपमान के घूंट पीते रहे तो मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का यह क्रम समाप्त ही नहीं होगा। यदि मुस्लिम मताबलंबियों ने अपने ग्रंथों के आधार पर यह तय किया है कि अन्य किसी धर्म के पूजास्थल को वह धरती पर अस्तित्व में रहने ही नहीं देंगे, तो इस संघर्ष की समाप्ति कैसे होगी? स्वाभाविक रूप से हिंदुओं से छीन लिए गए धर्मस्थलों को वे फिर से प्राप्त करने के प्रयास करेंगे, तभी जाकर दूसरे पक्ष को यह समझ में आएगा कि अपने धर्मस्थल को कोई प्रतिपक्षी वैधानिक तरीके से भी प्राप्त कर लेता है तो कितना कष्ट होता है?

भारत में यदि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर बनाए गए अतिक्रमित स्थानों की फिर से स्थापना का कोई रास्ता खुल रहा है तो उस रास्ते को भारत के दोनों ही समुदायों को इसलिए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह मार्ग शांति का मार्ग है। इस आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यदि एक पक्ष सड़क पर आता है तो दूसरा पक्ष भी शक्ति प्रकट करने के लिए सड़क पर आने के लिए बाध्य हो जाएगा और उस स्थिति में देश को ही नहीं, बल्कि दोनों ही पक्षों को भी अधिक हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसे में बेहतर यह होगा कि दोनों ही पक्ष बाबा साहब आंबेडकर के बने संविधान के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया से आए हुए निर्णयों का खुले दिन से स्वागत करें।

जागरण जनमत कल का परिणाम

भारत में भी 16 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल नेटवर्क से दूर रखना चाहिए?

आज का सवाल
क्या भारतीय टीम द्रारा केएल राहुल- यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी को कायम रखने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण डाट कम संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पुरुषत्व जी भी तुलकर गए अतीमान,
बीजेपी पर कर दिया शिंदे ने 'अहसान'।
शिंदे ने 'अहसान' बांटिए अब तो पढ़ा,
पांच वर्ष तक बंधुवत रेना कही वेखेड़ा!
गृह मंत्रालय हेतु फूलकर समूह था कुप्पा,
जाने फिर क्या सोच स्वयंही मारी पुरुषत्व!!
- ओमप्रकाश तिवारी